• कर्ज के सहारे चल रही मप्र सरकार • विकास में केंद्र सरकार कर रही भेदभाव

In Pursuit of Truth

पाक्षिक

अक्स

www.akshnews.com

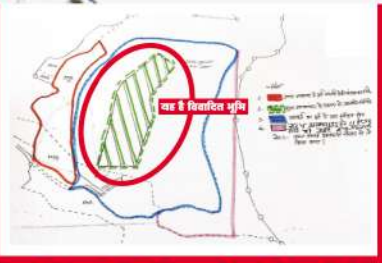

लीज के लिए दो की बलि

वर्ष 18, अंक-11 1 से 15 मार्च 2020 मूल्य 25 रूपये

दिल्ली का दर्द

घाव बना नासूर

R.N.I NO.HIN/2002/8718 M.P. BPL/642/ 2015-17

Zircon Hospitality

PVT LTD

COMMING SOON...

Next to Bhuj Railway Station, Railway Area, Bhuj-370001, Gujarat

Setting up Hotel Project in Sector-5, Pithampur Industrial Area (M.P.)

इस अंक में

राजपथ

10-11 | चुनौतियों भरा ताज

मप्र भाजपा में अब 4जी (फोर्थ जनरेशन) यानी चौथी पीढ़ी के नताओं का महत्व बढ़ेगा। प्रदेश भाजपा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ने वाले नेताओं की अब लॉटरी खुलने वाली है।

चौसर

12 | अटक गए निकाय चुनाव

मध्यप्रदेश में निकाय व पंचायत चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने की पूरी संभावना है। मतदान का पैटर्न बदले जाने पर सरकार में सहमति बन गई है। अभी पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव...

लालफीताशाही

16 | महंगी होगी शराब

मध्य प्रदेश में राजस्व में बढ़ोतरी के लिए शराब दुकानों के वार्षिक मूल्य में 25 फीसदी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में दुकानों की दर में यह बढ़ोतरी होगी। साथ ही नई उप-दुकानें न खोलने का भी सरकार ने फैसला लिया है।

विडंबना

19 | 54 गांवों में डर का साया

40 साल पहले मध्य प्रदेश के चुटका सहित 54 गांव बरगी बांध के कारण विस्थापित हुए थे। अब इन गांवों पर चुटका परमाणु विद्युत परियोजना से विस्थापित होने की तलवार लटक रही है। आखिर कितनी बार कोई आदिवासी अपने घर-द्वार-जल-जंगल और जमीन छोड़ेगा?

आवरण कथा 24, 25, 26, 27, 28

दिलवालों की दिल्ली में पिछले दिनों दहशत का जो खेल खेला गया, वह सुनियोजित षड्यंत्र था। वरना जिस शहर में हमेशा 50 हजार से अधिक पुलिस बल सक्रिय रहता है, वहां हिंसा और आगजनी की वारदात इतना भयानक रूप कैसे ले सकती थी? आरोप तो यह लग रहे हैं कि घाव के नासूर बनने का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन यह नासूर 42 जिंदगियां लील जाएगा, इसका किसी को अनुमान ही नहीं था।

13

20

39

45

सियासत

32-33 | राहुल की होगी वापसी!

राहुल गांधी को जल्द ही एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसका संकेत इसलिए भी मिल रहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के करीबी नेताओं को राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है। यह इस बात का संकेत है कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें रिलॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है।

उत्तरप्रदेश

35 | मंदिरों पर मेहरबानी

उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2020-21 के लिए 5,12,860.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बजट पेश करते हुए जानकारी दी कि बजट में 10,967.80 करोड़ रुपए की नई योजनाओं का प्रावधान किया गया है। बजट में धार्मिक स्थलों...

राजस्थान

36 | सीधी जंग की सियासत

पिछले विधानसभा चुनावों में वसुंधरा राजे को कमान सौंपने के मामले में भाजपा नेतृत्व का तुजुर्बा काफी कसैला रहा था। बावजूद अजमेर और जयपुर में आयोजित संघ के चिंतन शिविरों में राजे के विकल्प का मुद्दा काफी कसमसाता रहा।

6-7 अंदर की बात
41 महिला जगत
42 अध्यात्म
43 कहानी
44 खेल
45 फिल्म
46 व्यंग्य

अपनी बात

जख्म खरीदकर लाया हूं, बाजार-ए-मोहब्बत से

किसी शायर ने क्या खूब कहा है...

जख्म खरीदकर लाया हूं, बाजार-ए-मोहब्बत से
दिल बड़ी जिद कर रहा था, कुछ लाकर दो

कुछ ऐसी ही स्थिति शेयर बाजार की भी है। शेयर बाजार में बड़े से बड़े खिलाड़ी को धड़ाम होते देर नहीं लगती है और बड़े से बड़े अनाड़ी का भाग्य चमकने में देर नहीं होती। यानि शेयर बाजार में समझदारी से बड़ा भाग्य का खेल होता है। आर्थिक जगत में शेयर बाजार को सट्टा नहीं माना जाता है लेकिन जिस तरह बाजार में उतार और चढ़ाव होता है, उससे यह किसी सट्टे से कम नहीं है। किसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक या अन्य कारणों से बाजार या तो एकाएक आसमान पर चला जाता है या धड़ाम हो जाता है। तो इसे क्या कहेंगे। हाल ही में चीन में कोरोना वायरस ने पांव क्या फैलाया उसका असर बाजार पर भी पड़ा। फरवरी माह के अंतिम दिनों में तो शेयर बाजार खुलने के शुरुआती 15 मिनट में ही मार्केट से करीब 5 लाख करोड़ स्वाहा हो गए। 28 फरवरी को बाजार लगातार छठे कारोबारी दिन लाल निशान में बंद हुआ है। और बीते पूरे हफ्ते में सेंसेक्स करीब 2900 प्वाइंट और निफ्टी 900 प्वाइंट टूटा है। शेयर बाजार में एक दिन में इतनी बड़ी गिरावट कम ही हुई है और चिंता की बात ये है कि बाजार लगातार कई दिन से गिर रहा है। अमेरिकी बाजारों के लिए तो बीता हफ्ता 2008 की आर्थिक मंदी के बाद सबसे खराब रहा है। तो आखिर बाजार को हुआ क्या है? ग्लोबल फैक्टर है या घरेलू? शेयर बाजारों में तबाही सिर्फ भारत में हो रही हो, ऐसा भी नहीं है। दुनियाभर के बाजार गिरावट के नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। अमेरिका में सिर्फ एक हफ्ते के अंदर बाजारों में 10 प्रतिशत तक कमजोरी देखने को मिली है, जो कि बहुत ज्यादा है। एशियाई बाजारों, यूरोपीय बाजारों, ऑस्ट्रेलिया सब तरफ बाजार लाल ही लाल है। दरअसल, गिरते इंटरनेशनल बाजारों का असर भारत पर तो हो ही रहा है, भारत की अपनी इकनॉमी की हालत भी खस्ता है। जीडीपी 6 साल में सबसे कम है, बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा है। ऐसे में बाजार से लाभ की उम्मीद नहीं की जा सकती है। शेयर बाजार में निवेश करने वाला वही व्यक्ति सफल होता है जो पल-पल चढ़ते-उतरते शेयरों के भाव को देखकर नहीं, बल्कि आगामी स्थितियों को पढ़कर निवेश करता है। दरअसल, शेयर बाजार में लोग आते तो यह खुशफहमी लेकर हैं कि हम इससे जग जीत लेंगे। यहां से रकम दोगुनी करके ले जाएंगे। असली बाजार के पंडित हम ही हैं। और, यह बाजार हमारे ही इशारों पर चल रहा है। भला आज तक कौन पार पा सका है शेयर बाजार या सट्टे से। यह वह दरिया है, जहां आप जितनी रकम डालते जाएंगे, धीरे-धीरे सब डूबती जाएगी। स्क्रीन पर चलती लाल-नीली पट्टियों का आकर्षण ही आदमी को अपनी गिरफ्त में लिए रहता है। बिरले होंगे, जो इस बाजार से रकम कमाकर ले गए हों। वरना यहां हर बंदा लुटने के लिए खुद चला आता है। इस बाजार से लोगों को कमाते कम, गंवाते ज्यादा देखा गया है। यहां कमा वही पाता है, जिसके पास अथाह धैर्य हो। सट्टा बाजार में धैर्य बहुत मुश्किल काम है। शेयर बाजार का कायदा है, यहां से जितना लाभ मिल रहा है, तुरंत ले लो, पर कभी दिल लगाने की गलती मत करो। क्योंकि शेयरों से अगर दिल लगाएंगे तो एक दिन यह आपके दिल को ही बैठा देगा। यह तय है कि शेयर बाजार की हर बड़ी गिरावट बड़ा नुकसान लेकर आती है। हर बड़े नुकसान से निपटना हमारी समझदारी पर ही निर्भर करता है। जो सक्षम होते हैं, गिरावट के भंवर में से निकल आते हैं, जो नहीं निकल पाते, वे अंततः डूब जाते हैं। यही शेयर बाजार का कायदा भी है और दस्तूर भी।

-राजेन्द्र आगाल

पाक्षिक अक्स

वर्ष 18, अंक 11, 1 से 15 मार्च, 2020

प्रकाशक एवं संपादक : राजेन्द्र आगाल

सम्पादकीय कार्यालय :
प्लाट नम्बर 150, जोन-1 मनोरमा कॉम्पलेक्स,
एफ-03, 04, प्रथम तल, एम.पी. नगर
भोपाल- 462011 (म.प्र.),
फोन नं. 0755-2557777, टेलीफेक्स - 0755-4017788
email : akshmagazine@gmail.com
Website : www.akshnews.com
RNI NO. HIN/2002/8718 MPBPL/642/2015-17

ब्यूरो
मुंबई :- ऋतेन्द्र माथुर, **कोलकाता:-** इंद्रकुमार, **जयपुर:-** आर.के. बिन्नानी, **छत्तीसगढ़:-** संजय शुक्ला, मार्केण्डेय तिवारी, टी.पी. सिंह, **लखनऊ :-** मधु आलोक निगम।

प्रदेश संवाददाता
094251 25096 (इंदौर) विकास दुबे
098276 18400 (जबलपुर) धर्मेन्द्र कथूरिया
094259 85070, (उज्जैन) श्यामसिंह सिकरवार
094259 85070, (मंदसौर) धर्मवीर रत्नावत
098934 77156, (विदिशा) ज्योत्सना अनूप यादव

क्षेत्रीय कार्यालय
नई दिल्ली : ईसी 294 माया इंक्लेव मायापुरी-
फोन : 011 25495021, 011 25494676
मुंबई : बी-1, 41 शिव पावर्ती चेम्बर प्लाट नंबर 106-110 सेक्टर-21
नेरूल, नवी मुंबई-400706 मो.-093211 54411
कोलकाता : 70/2 हजरा रोड कोलकाता
फोन-033 24763787, मोबाइल: 09331 033446
जयपुर : सी-37, शांतिपथ, श्याम नगर (राजस्थान)
फोन- 0141 2295805, मोबाइल-09829 010331
रायपुर : एमआईजी 1 सेक्टर-3 शंकर नगर, फोन : 0771 2282517
भिलाई : नेहरू भवन के सामने, सुपेला, रामनगर, भिलाई,
मोबाइल 094241 08015
इंदौर : 39 श्रुत्रि सिलटर निपानिया, इंदौर
मोबाइल - 094251 25096

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक, राजेन्द्र आगाल द्वारा आगाल प्रिंटर्स, प्लाट नं. 150, जोन-1, प्रथम तल, एफ-03, मनोरमा काम्पलेक्स, एम.पी. नगर भोपाल 462011 (म.प्र.), से मुद्रित एवं प्रकाशित

इस अंक में प्रकाशित सामग्री लेखकों के अपने विचार हैं इनसे सम्पादक का सहमत होना अनिवार्य नहीं हैं समस्त विवादों के लिए न्याय क्षेत्र भोपाल होगा।

पत्र–संपादक के नाम

akshnews.com

बजट से उम्मीदें

प्रदेश के बजट से आम आदमी को खासी उम्मीदें है। ऐसा लगता है कि इस बार प्रदेश सरकार केंद्र की सरकार से कई गुना अच्छा बजट लाएगी। किसान और बेरोजगार भी इस बजट से बहुत आस लगाए हुए हैं। इस बार बजट में सबकी नजरें कर्जमाफी की ओर रहेंगी।

● **संजय कुशवाहा,** इंदौर (म.प्र.)

गलत है मॉब लिंचिंग

मनावर के बोरलाई में जो मॉब लिंचिंग हुई है, वह निराशाजनक है। आए दिन इस प्रकार की घटना सुनने को मिलती है। बिना जाने-समझे किसी के साथ मारपीट करना गलत है। बाद में पीड़ित के परिवार का हाल कोई नहीं समझता। प्रशासन को इसके लिए कड़े कदम उठाने चाहिए।

● **नरेश मोटवानी,** ग्वालियर (म.प्र.)

पहले खुद को बदलना होगा

हमारे शहर को स्वच्छ रखना हर शहरवासी का कर्तव्य है। जब तक हम खुद से सफाई पर ध्यान नहीं देंगे तब तक कुछ नहीं बदलेगा। इंदौर भी हमारे ही प्रदेश का हिस्सा है। अगर इंदौर के लोग अपने शहर को स्वच्छता में नंबर-1 ला सकते हैं तो हम क्यों नहीं।

● **प्रिया शर्मा,** भोपाल (म.प्र.)

बहुत अच्छा फैसला

मध्यप्रदेश में आईफा का आयोजन करने का सरकार द्वारा किया गया एक बहुत अच्छा फैसला है। इससे समारोह से मध्यप्रदेश में पर्यटन के द्वार खुलेंगे। जब मध्यप्रदेश की धरती पर 5 हजार के करीब सेलिब्रिटीज आएंगे, तो देश-दुनिया में मध्यप्रदेश की छवि और उभरकर आएगी। निश्चित ही यह मध्यप्रदेश के लिए भी बड़ा अवसर है। आईफा समारोह से मध्यप्रदेश की ब्रांडिंग के साथ-साथ यहां के कलाकारों में भी एक आशा की किरण जगेगी। हमारा प्रदेश, हमारे शहर, हमारी कला संस्कृति, पर्यटन का आईफा के जरिए देश-दुनिया में प्रचार-प्रसार होगा। प्रदेश में आईफा समारोह को लेकर लोग उत्सुक हैं।

● **रचना शिवहरे,** भोपाल (म.प्र.)

केजरीवाल को काम पर वोट मिले

दिल्ली विधानसभा चुनाव में केजरीवाल सरकार को उनके काम के चलते वोट मिले हैं। शिक्षा के क्षेत्र में, महिलाओं के लिए फ्री सफर, फ्री बिजली और पानी जैसे उनके कामों से जनता खुश थी। उम्मीद है कि आगे भी वे काम पर वोट मांगेंगे। इस बार के दिल्ली चुनाव में एक नई प्रकार की राजनीति उभरकर सामने आई है। जिसमें आम लोगों की समस्या को हल करने वाले अरविंद केजरीवाल ने अपनी छवि एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर पेश की है। सबको यकीन है कि आगे भी वे दिल्ली के लोगों के लिए और अच्छा काम करेंगे।

● **अशोक शाक्य,** नई दिल्ली

पौधों को भी नहीं छोड़ा

प्रदेश में शिवराज सरकार के समय हुआ नर्मदा किनारे 6 करोड़ पौधे लगाने का फर्जीवाड़ा गर्माया हुआ है। भ्रष्टाचार करते-करते लोग यहां तक गिर गए हैं कि उन्होंने पेड़-पौधों को भी नहीं छोड़ा। उसमें भी घपले करने लगे हैं। एक पेड़ इंसान के लिए कितना कीमती होता है शायद वे लोग इस बात को नहीं जानते। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। ताकि भविष्य में उनकी कभी हिम्मत न हो, किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा करने की।

● **रोशनी सोनी,** जबलपुर (म.प्र.)

पाठकों से निवेदन

कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं पक्ष या विपक्ष जो भी संभव हो इस पते पर भेजें

अक्स

150 जोन-1, मनोरमा काम्पलेक्स,
एफ-02, 03, एमपी नगर, भोपाल

मुंगेरीलाल के हसीन सपने

अनुप्रिया पटेल की अपनी मां कृष्णा पटेल और छोटी बहन से नहीं पटी तो अपना दल पार्टी दो फाड़ हो गई। 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा से गठबंधन किया। दो सीटें मिलीं अनुप्रिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में राज्यमंत्री भी बनाया। फिर 2017 के यूपी विधानसभा के चुनाव में भी भाजपा से तालमेल कर अनुप्रिया की पार्टी नौ सीटें जीत गई। योगी आदित्यनाथ ने इस पार्टी के जयकुमार सिंह को राज्य मंत्री भी बना दिया। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में अनुप्रिया रूठने लगीं तो भाजपा ने फिर दो सीटें दीं और उनकी पार्टी जीत भी गई। पर भाजपा के अपने प्रचंड बहुमत ने अनुप्रिया के इस बार कैबिनेट मंत्री बनने के सपने को तोड़ दिया। फिर भरोसा मिला कि भरपाई के लिए उनके एमएलसी पति आशीष सिंह पटेल को योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री पद मिलेगा। यह भरोसा भी थोथा ही साबित हुआ। नतीजतन दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही अपना दल के लोगों ने नखरे दिखाने शुरू कर दिए। वहीं 2022 में अनुप्रिया पटेल ने यूपी का मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया। भाजपाई इसे मुंगेरीलाल के हसीन सपने से ज्यादा कोई भाव नहीं दे रहे। है भी ठीक, नौ विधायकों और दो सांसदों वाली एक खास जाति की पार्टी की नेता भला मुख्यमंत्री किस फार्मूले से बनेंगी।

क्या खत्म होगा वनवास?

अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री रहे और कभी वाजपेयी के नवरत्नों में गिने जाने वाले सैयद शाहनवाज हुसैन करीब छह साल से वनवास काट रहे हैं। वे 2014 में लोकसभा का चुनाव बहुत मामूली अंतर से हार गए थे। उसके बाद से ही वे एक तरह से राजनीतिक बियाबान में हैं। हालांकि वे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति के भी सदस्य हैं। पर 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया। सो, वे अब राज्यसभा के जरिए अपना वनवास खत्म होने की उम्मीद कर रहे हैं। ध्यान रहे भाजपा के सबसे लोकप्रिय चेहरों में एक चेहरा शाहनवाज का है। वे सिर्फ मुस्लिम समुदाय में ही नहीं, बल्कि बहुसंख्यक समुदाय में भी स्वीकृत हैं। बिहार में उनका अपना एक राजनीतिक मुकाम है। वे प्रदेश के दो अलग-अलग हिस्सों से चुनाव लड़े हैं और जीते भी हैं। पर मुश्किल यह है कि भाजपा उनको कहां से राज्यसभा में भेजे? उनके गृह प्रदेश बिहार में भाजपा की दो सीटें खाली हो रही हैं पर उसे सिर्फ एक सीट मिलेगी। बिहार से बाहर संभावना सिर्फ उत्तर प्रदेश में दिख रही है, जहां नवंबर में चुनाव होंगे और भाजपा को नौ सीटें मिलेंगी। सो, अगर मार्च के दोवार्षिक चुनाव में शाहनवाज का वनवास खत्म नहीं होता है तो संभव है कि नवंबर में हो जाए। उस समय भाजपा को नौ सीटों का फायदा होने वाला है।

वास्तुदोष से त्रस्त सीबीआई

शीर्ष केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) यूं तो लंबे अरसे से विवादों में रहती आई है, एजेंसी में काम कर रहे अफसरों का मानना है कि 2011 के बाद से हालात ज्यादा बिगड़े हैं। एजेंसी का नया और हाईटेक ऑफिस 2011 में बनकर तैयार हुआ था। इस इमारत में शिफ्ट होने के बाद से ही सीबीआई लगातार गलत कारणों के चलते सुर्खियों में बनी रही है। एजेंसी के तत्कालीन निदेशक आलोक वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना की लड़ाई तो सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंची थी। आलोक वर्मा को हटाए जाने वाली रात दिल्ली पुलिस सीबीआई मुख्यालय में घुस गई थी। इस घटनाक्रम से जुड़े एक सीबीआई अफसर ने राकेश अस्थाना पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी थी। बमुश्किल केंद्र सरकार इस फजीहत से पीछा छुड़ा पाई कि अब एक बार फिर से सीबीआई के भीतर कुछ बड़ी गड़बड़ी के समाचार सामने आ रहे हैं। जानकारों का कहना है कि आईपीएस बनाम सीबीआई कैडर के बीच चल रहे शीत युद्ध के चलते पिछले दिनों बड़ी तादात में ट्रांसफर कर दिए गए। अफसरों ने नई तैनाती पर जाने से साफ इनकार कर दिया है। खबर है कि ऐसे अधिकारियों को अब अनुशासनात्मक कार्यवाही का भय दिखाया जा रहा है।

बेबस हाईकमान

सोशल मीडिया पर संतोष के नाम से जारी चिट्ठी को बेशक भाजपा ने फर्जी बता दिया है। पर कर्नाटक में पार्टी के भीतर सुलग रहे असंतोष को सिरे से नहीं नकार पा रहे हैं पार्टी नेता। येदियुरप्पा को हटाने की मांग वाला यह पत्र सूबे में काफी चर्चित हो रहा है। इस महीने 27 तारीख को येदियुरप्पा 77 साल के हो गए। यानी भाजपा की नई आचार संहिता के हिसाब से तो वे एक दिन भी मुख्यमंत्री नहीं रह सकते। उनकी वफादारी को देखते हुए उनका पुनर्वास पहले ही किसी राजभवन में हो जाना चाहिए था। पर कुमारस्वामी की सरकार को गिराकर जब येदियुरप्पा ने पिछले साल सरकार बनाई थी, तभी वे 75 पार कर चुके थे। आलाकमान के इस नजरिए पर प्रदेश में नाखुशी है। लेकिन आलाकमान के सामने मुश्किल यह है कि येदियुरप्पा का सूबे की सियासत में जितना दबदबा है उतना भाजपा के किसी दूसरे नेता का नहीं। इसी मजबूरी के कारण बगावत कर अलग पार्टी बनाने के बावजूद येदियुरप्पा को पार्टी में वापस लेना पड़ा।

वक्त का फेर

कभी अपने केंद्रीय नेतृत्व को आंखें दिखाने के लिए चर्चित थीं वसुंधरा राजे। पर वक्त का फेर देखिए कि अब सूबे की सियासत में उनका रंग फीका पड़ने लगा है। जब तक मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष रहीं, पार्टी में सारे फैसले अपनी मर्जी से लेती थीं। जैसे सचमुच की महारानी हों। खांटी संघी अतीत वाले कद्दावर पार्टी नेता घनश्याम तिवाड़ी की ऐसी गत बनाई कि बेचारे पार्टी छोड़ने को ही मजबूर हो गए। संघ-भाजपा के हिमायती माने जाने वाले एक मीडिया समूह को भी विरोधी बना लिया। नतीजतन 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले संघी खेमा ही कहने लगा था कि अगर गलती से वसुंधरा राजे फिर सत्ता में आ गई तो हालात और बदतर होंगे। उनसे पीछा छुड़ाने की जुगत में पार्टी आलाकमान भी था ही। वक्त बदला, केंद्र में भाजपा की और मजबूती से वापसी हुई और राजस्थान में वसुंधरा सत्ता से बाहर हो गईं तो आलाकमान अपनी चलाने लगा। वसुंधरा को पूरी तरह हाशिए पर पहुंचा दिया। सो उन्होंने पार्टी कार्यक्रमों में शिरकत भी बंद कर दी।

और बॉल गुगली हो गई

प्रदेश में इस समय कई मंत्रियों की अपने विभाग के अधिकारियों के साथ पटरी नहीं बैठ रही है। ऐसी ही स्थिति प्रदेश के एक बड़े विभाग के बड़े साहब और मंत्री के बीच भी है। दोनों में पटरी नहीं बैठने के कारण मंत्रीजी साहब को विभाग से रवाना करवाने के मूड में थे। लेकिन न तो तबादले की पहली और न ही दूसरी सूची में साहब का नाम आया। सूत्र बताते हैं कि साहब की बिदाई की पूरी तैयारी हो चुकी थी। कच्चे कागज पर उनकी रवानगी फाइनल कर दी गई थी। लेकिन साहब के तबादले के लिए फेंकी गई बॉल इतनी वाइड गुगली हो गई कि साहब बाल-बाल बच गए। सूत्र बताते हैं कि साहब की जगह जिस दूसरे अधिकारी को लाने की तैयारी थी वे ग्राउंड फ्लोर पर बैठते हैं। ग्राउंड फ्लोर वाले साहब को दूसरी मंजिल पर बैठाने की तैयारी हो चुकी थी और दूसरी मंजिल वाले साहब को मंत्रालय में कहीं और बैठा दिया जाता। लगभग सब कुछ तय हो गया था। इसी दौरान साहब के मन में न जाने क्या सूझी कि उन्होंने मंत्रीजी के पास पहुंचकर गुहार लगाई। और अंततः मंत्रीजी ने साहब को तबादले से बचा लिया। अब देखना यह है कि मंत्री और साहब के बीच में समन्वय बन पाता है या फिर पहले की तरह द्वंद छिड़ा रहेगा। सूत्र बताते हैं कि अगर अब कुछ मनमुटाव हुआ तो साहब का बोरिया-बिस्तर बंधने से कोई रोक नहीं सकता है।

फिर फार्म में आए जनाब

हाल ही में सरकार बनी इस दौरान बड़े-बड़े अधिकारियों को इशारे पर नचाने वाले महाशय आयकर छापे के बाद नेपथ्य में चले गए थे। लेकिन इन दिनों फिर से वे फार्म में लौटते नजर आ रहे हैं। बताया जाता है कि उनकी दुकान फिर से जमने लगी है। वर्तमान में आधा दर्जन प्रमुख सचिवों को उन्होंने फिर अपने सांचे में उतार लिया है। कमाल है इन प्रमुख सचिवों को जरा भी डर, शर्म बची नहीं। लेकिन हद तो यह है कि साहब के काले अतीत को देखते हुए भी ये अफसर निडर हैं। यही नहीं उन प्रमुख सचिवों के विभाग में होने वाले काम नियम-कायदे से हो या न हो लेकिन ये महाशय चाह दें तो नियम विरुद्ध होने के बाद भी कोई काम हो जाते हैं। प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में चर्चा यह है कि आखिर इन अफसरों को इतनी हिम्मत कहां से आ रही है कि वे एक दागदार व्यक्ति को पाले हुए हैं। कहा जा रहा है कि इन अफसरों के नाम पर यह महाशय इन दिनों जमकर कमाई कर रहे हैं। आलम यह है कि जिन लोगों के काम अटक जा रहे हैं वे इन महाशय से संपर्क साध रहे हैं। बताया जाता है कि संपर्क साधने वालों से मोटी फीस लेकर महाशय धड़ाधड़ काम करवा रहे हैं। यहां यह बता दें कि वर्तमान सरकार के प्रारंभिक दिनों में ही साहब के ठिकानों पर आयकर विभाग ने छापामार कार्रवाई कर करोड़ों रुपए बरामद किए थे और शासकीय दस्तावेज भी इनके यहां मिले थे।

लोकायुक्त डीजी पर नजर

प्रदेश में जब भी कोई रसूख वाला पद खाली होता है तो उस पद पर बैठने के लिए अफसरों में होड़ मच जाती है। ऐसा ही एक पद लोकायुक्त संगठन में डीजी का खाली होने वाला है। सूत्र बताते हैं कि वर्तमान लोकायुक्त डीजी जल्द ही रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में इस पद की चाह रखने वाले अफसरों ने अपनी जमावट शुरू कर दी है। बताया जाता है कि जहां कुछ अफसर अपने दिल्ली संपर्कों को सक्रिय करने में जुटे हुए हैं तो वहीं कुछ ने प्रदेश के दिग्गज नेताओं के यहां धौंक देना शुरू कर दिया है। बताया जाता है कि करीब आधा दर्जन आईपीएस अधिकारी इस पद को पाने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। लॉबिंग में जुटे इन अफसरों को उनके शुभचिंतक अपने-अपने तरीके से सलाह भी दे रहे हैं। ऐसे ही एक सलाहकार ने कुछ अफसरों को सलाह दी है कि अगर लोकायुक्त डीजी बनना है तो आपको सुपर सीएम के दरबार में दस्तक देनी पड़ेगी। अगर वहां से हरी झंडी मिल गई तो आपको लोकायुक्त डीजी बनने से कोई नहीं रोक सकता। यही नहीं यह भी कहा जा रहा है कि प्रदेश में प्रशासनिक तबादलों में सुपर सीएम की ही चल रही है। इसलिए महत्वपूर्ण पदों पर वही लोग बैठ रहे हैं जिन्हें सुपर सीएम हरी झंडी दे रहे हैं। सलाहकार की सलाह मानकर कुछ अफसरों ने सुपर सीएम के करीबियों से नजदीकी बढ़ानी शुरू कर दी है। अब देखना यह है कि किसकी दाल गलती है।

मंत्री पद नहीं तो यही सही

15 साल बाद सत्ता में आने के बाद कई कांग्रेसी और निर्दलीय विधायकों को आस जगी थी कि उन्हें मंत्री पद मिलेगा और वे डेढ़ दशक के सूखे को खत्म कर देंगे। लेकिन करीब 14 महीने बाद भी कईयों की आस पूरी नहीं हो पाई है। आलम यह है कि इन्होंने मंत्री पद पाने के लिए सारे तिकड़म आजमा डाले हैं। लेकिन दाल गलती न देख 2 विधायकों ने तो अपनी कमाई का एक अनूठा ही रास्ता निकाल लिया है। इनमें से एक विधायक कांग्रेस के एक निर्दलीय हैं। एक माननीय ने चंबल संभाग के एक परिवहन बैरियर पर कब्जा जमा लिया है तो दूसरे ने निमाड़ क्षेत्र के बैरियर पर। यही नहीं दोनों ने उन बैरियरों पर पदस्थ अधिकारियों को साफ-साफ शब्दों में कह दिया है कि तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। तुम जहां मन करे वहां जाओ। तुम्हारा हिस्सा नियत समय पर पहुंच जाएगा। विधायकों के इस रुख को देखकर परिवहन अधिकारियों के होश उड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि मंत्री पद की चाह लगाए अन्य विधायक भी कमाई के लिए कहीं इस तरह का रास्ता न अख्तियार कर लें।

साहब की कमाई का हिसाब

प्रदेश में सरकार भले ही कितने भी दावे करे कि भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा हुआ है लेकिन अफसर काली कमाई करने में हिचक नहीं रहे हैं। आलम यह है कि कुछ मैदानी अफसरों ने तो इसके लिए बकायदा आदमी रख रखा है। प्रदेश की प्रशासनिक वीथिका में इन दिनों 2010 बैच के एक ऐसे ही आईएएस अधिकारी चर्चा में हैं। दरअसल, हाल ही में ये अधिकारी एक जिले की कलेक्टरी से लौटे हैं और दूसरे जिले में कलेक्टरी कर रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि साहब वर्तमान में जिस जिले के कलेक्टर हैं वह जिला ग्वालियर संभाग में आता है और उस जिले में काली कमाई के बड़े मौके हैं। ऐसे में उन्होंने एक मंत्री के ओएसडी को अपना सारा काम सौंप दिया है। यहां यह बता दें कि ये जिस मंत्री के ओएसडी हैं उनके पूर्व ओएसडी एक विवाद के कारण हटा दिए गए थे। उक्त विवादित ओएसडी की जगह इन साहब को ओएसडी बनाया गया है। अब देखना यह है कि कलेक्टर साहब और मंत्रीजी के ओएसडी की यह जोड़ी किस तरीके से कमाई का रिकार्ड बनाती है। और इसमें किस-किस को हिस्सा दिया जाता है।

यहां आकर अच्छा लगा। भारत एक शानदार देश है। दिल्ली के हैप्पीनेस क्लास को देखकर मैं काफी खुश हूं। हैप्पीनेस शब्द प्रेरणा देने वाला है। यहां की सरकार शिक्षा के प्रति कितनी तत्पर है, यह हैप्पीनेस क्लास में आकर अहसास हुआ।

● **मेलानिया ट्रम्प**

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वस्त किया है कि वे पूरे देश में एनआरसी लागू नहीं करेंगे। हमने ये समझ लिया है कि सीएए, एनआरसी और एनपीआर की भूमिका क्या है। सीएए को लेकर किसी को डरने की जरूरत नहीं है। जो लोग इसके खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं, उन्हें समझने की जरूरत है। कोई भी सरकार गलत निर्णय नहीं ले सकती।

● **उद्धव ठाकरे**

क्रिकेट को आगे बढ़ाने के लिए भारत, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्रभुत्वों से आगे ले जाना होगा। इन तीन बड़े देशों को अपना फायदा दुनिया के उन देशों के साथ बांटना होगा जो अभी क्रिकेट के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं। हमें जिम्बाब्वे, आयरलैंड, श्रीलंका और बांग्लादेश को भी विकसित करना होगा।

● **स्टीव वॉ**

कानून का पालन करने वाले किसी भी नागरिक को कोई भी किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंचा पाएगा। सरकार पर विश्वास रखिए। दिल्ली में जो कुछ भी हुआ है वह चिंतनीय है, लेकिन दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। यह समय धैर्य रखने का है।

● **अजीत डोभाल**

मुझे 65वें फिल्म फेयर अवार्ड में स्टूडेंट ऑफ द ईयर-2 के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस चुना गया, लेकिन जब मैं स्टेज पर गई तो अवार्ड एक्सेप्टेंस स्पीच भूल गई। जबकि मैं 5 साल की उम्र से इसकी प्रेक्टिस करती आ रही हूं और इस बार भी की थी। फिल्म फेयर अवार्ड जीतना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मेरी मां और पापा वहां मौजूद थे, लेकिन मैंने उनके हाथ में ट्रॉफी घर पहुंचने के बाद ही दी। पापा ने मुझे इसे लिविंग रूम में रखने की सलाह दी, ताकि हम सब पूरे दिन इसे निहार सकें। इस अवार्ड से मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ा है।

● **अनन्या पाण्डे**

वाक्युद्ध

भारत में धार्मिक असहिष्णुता में वृद्धि भयानक है। लोकतांत्रिक देशों को विभाजन और भेदभाव बर्दाश्त नहीं करना चाहिए और ऐसे कानून को बढ़ावा भी नहीं देना चाहिए, जो धार्मिक स्वतंत्रता को कमजोर करता हो। भारत की मोदी सरकार ने कुछ विवादित कदम उठाए हैं, उन्हें वापस लेना चाहिए।

● **प्रमिला जयपाल**

अमेरिकी सांसद प्रमिला जयपाल अमेरिकी नीतियों पर सवाल क्यों नहीं उठाती हैं। हमारी सरकार ने जो भी कदम उठाया है, वह देश की सुरक्षा को देखते हुए है। भारत सरकार अच्छी तरह जानती है कि उसे क्या करना है। इसके लिए किसी विदेशी की सलाह की जरूरत नहीं है। सरकार सही दिशा में है।

● **मनोज तिवारी**

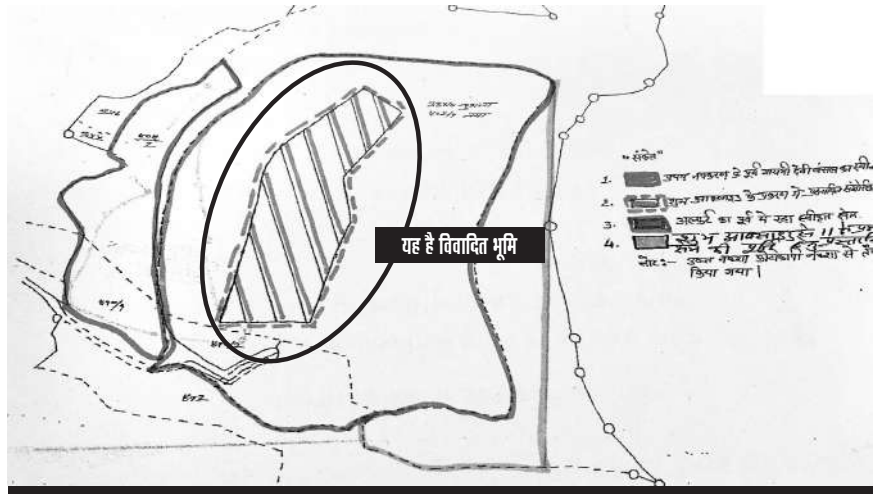

लीज के लिए दो की बलि

विवादों में हंस की नियुक्ति

एडिशनल डायरेक्टर एनके हंस को वर्तमान दायित्व के साथ संचालक खनिज का प्रभार सौंपा गया है। लेकिन उनकी नियुक्ति भी विवादों में है। हंस की नियुक्ति 1983 में सहायक भौमिक विद के पद पर पर हुई। उस दौरान उनकी परिवीक्षा अवधि पूरी नहीं हुई और विभागीय परीक्षा भी पास नहीं की है। न्यूनतम आयु होने पर भी उन्हें पदोन्नति दी गई। सरकार ने 2017 में इन मामलों की जांच के लिए कमेटी भी गठित की है, जो ठंडे बस्ते में है। यही नहीं अगर नियमानुसार देखें तो संचालक को हटाए जाने के बाद वरीयता क्रम में शिवानी खननता संवर्ग में वरिष्ठतम अधिकारी हैं। इसलिए इन्हें संचालक की जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए थी। सवाल उठता है कि ऐसे विवादित अफसर को इतना महत्वपूर्ण दायित्व क्यों दिया गया। सूत्र बताते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम में विभाग के विवादास्पद अधिकारी शामिल हैं, जिसने पूरा ताना-बाना बुना है। अब देखना यह है कि विवादित हंस और उनके साथी क्या गुल खिलाते हैं।

म प्र में एक तरफ मुख्यमंत्री कमलनाथ अवैध खनन, अवैध निर्माण, अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा मामला आया है जिसमें 30 वर्ष तक खनन कर लिया और अब वो नया माइनिंग प्लान लेकर पहुंच गए। क्योंकि पुरानी जमीन में कुछ माल बचा नहीं। इस कारण लीज नहीं देने के कारण दो अफसरों की बलि (तबादला) चढ़ गई। इस पूरी घटना के पीछे कांग्रेस के एक कद्दावर और पूर्व में बड़े ओहदेदार रहे नेता और जबलपुर जिले के उनके सखा का हाथ बताया जा रहा है।

दरअसल, मामला जबलपुर जिले के जोली गांव में मेसर्स शुभ ऑक्साइड मिनरल रेड ऑक्साइड के लिए उस भूमि पर उत्खनन की अनुमति मांग रहा था, जो सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसके लिए कंपनी के एक रसूखदार ने राजनीतिक रसूख के सहारे उक्त भूमि पर खनन के लिए अनुमति मांगने के लिए सारे तिकड़म लगा दिए, लेकिन विभाग के तत्कालीन संचालक विनीत ऑस्टिन ने उसकी दाल नहीं गलने दी। इसके लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता ने सरकार पर दबाव डाला, तो सरकार की भी कोशिश नाकाम रही। ऐसे में ऑस्टिन को विभाग से चलता कर उनकी जगह एडिशनल डायरेक्टर एनके हंस को वर्तमान दायित्व के साथ संचालक खनिज का प्रभार सौंपा गया है। सूत्र बताते हैं कि हंस को इसी शर्त पर लाया गया है कि वे नया माइनिंग प्लान स्वीकृत करने में उनकी मदद करेंगे।

दरअसल, इस फर्जीवाड़े की शुरुआत कुछ इस तरह हुई। 1982 में जबलपुर जिले के जोली गांव में गायत्री देवी बंसल को 11.10 हेक्टेयर क्षेत्र में मिनरल ऑक्साइड के खनन के लिए खदान लीज पर आवंटित की गई। गायत्रीदेवी के निधन के बाद उक्त लीज को उनके उत्तराधिकारी रामशरण बंसल को ट्रांसफर की गई। फिर रामशरण बंसल के निधन के बाद लीज उनके दो बेटियों और नाती को नियमानुसार दी गई। उत्तराधिकारियों ने मेसर्स शुभ ऑक्साइड नाम से एक कंपनी बनाई। कुछ वर्ष बाद शुभ ऑक्साइड में कुछ और पार्टनर बना लिए गए, लेकिन इसकी सूचना सरकार को नहीं दी गई।

यही नहीं मेसर्स शुभ ऑक्साइड के तथाकथित पार्टनर और रसूखदार ने षड्यंत्र पूर्वक खनिज अधिकारी और कलेक्टर जबलपुर पर दबाव डालकर जोली गांव में आवंटित खदान में कोई माल बचा नहीं तो उन्होंने बाजू के रकबे का नया माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया, जिससे खनिज संचालक सहमत नहीं थे। कद्दावर नेता के दबाव में आकर भी उन्होंने इस नए माइनिंग प्लान को स्वीकृत नहीं किया। तत्पश्चात विभाग ने उक्त अनुमति की जांच के बाद खनिज अधिकारी जबलपुर से स्पष्टीकरण मांगा। खनिज विभाग के द्वारा स्पष्टीकरण मांगे जाने के बाद खनिज अधिकारी जबलपुर ने जांच पड़ताल के बाद सूचित किया कि जिस जमीन को आवंटित किया गया है वह सुप्रीम कोर्ट में विवादित है।

सूत्र बताते हैं कि तत्कालीन संचालक विनीत ऑस्टिन ने जब दोबारा उक्त जमीन का कलेक्टर सीमांकन कराया तो कलेक्टर की रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि उक्त क्षेत्र की गलत तरीके से प्लॉटिंग की गई है और नए सिरे से माइनिंग प्लान बनाया गया है। नक्शे में गलत जमीन दिखाई गई है। यही नहीं इस मामले में मेसर्स अलफर्ट प्राइवेट लिमिटेड और अन्नू गोयंका ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है कि यह वन भूमि है। इस रिपोर्ट के बाद तत्कालीन संचालक विनीत ऑस्टिन ने माइनिंग प्लान को अस्वीकृत कर दिया।

विनीत ऑस्टिन द्वारा लीज नहीं दिए जाने को कांग्रेसी नेता और उनके सखा ने प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया। फिर क्या था, सरकार में दखल रखने वाले वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और जबलपुर जिले के एक दमदार मंत्री के कहने पर बंद कमरे में मुख्यमंत्री ने एक बैठक विभागीय अधिकारियों के साथ बुला ली। इन दोनों ने मिलकर मुख्यमंत्री कमलनाथ को मामले की जानकारी दी और अनुमति दिलाने के लिए कहा। उक्त बैठक में रसूखदार सखा जोर-जोर से चिल्लाने लगे। उस समय तो मुख्यमंत्री ने उनकी बात पर विशेष ध्यान नहीं दिया। पर बाद में दमदार कांग्रेसी नेता और मंत्री के कहने पर संचालक को बदल दिया। ऑस्टिन ने मुख्यमंत्री को पूरी हकीकत बयां की। उन्होंने यह भी बताया कि मेसर्स शुभ ऑक्साइड अभी तक जो रकबा उसे 50 वर्ष के लिए लीज पर दिया है उस पर खुदाई कर रहा है। पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाकर हंस को वर्तमान दायित्व के साथ संचालक खनिज का प्रभार सौंपा गया है। परंतु हंस को संचालक तो दस्तखत करने के लिए बनाया है, इसके पीछे काम करने वाले कोई और अधिकारी होंगे, जो भाजपा सरकार में खनिज मंत्री के खास रहे हैं। उनकी भी शिकायत मुख्यमंत्री को आरटीआई एक्टिविस्ट मिश्रा द्वारा की गई। उन्होंने मांग की है कि उन्हें छत्तीसगढ़ कैडर अलॉट हुआ तो वे अभी तक यहां पर किसकी मेहरबानी से जमे हुए हैं। साथ ही उन्होंने हरदा जिले में करोड़ों की राजस्व हानि, भ्रष्टाचार करने की शिकायत की है। वहीं इस पूरे मामले से खनिज मंत्री प्रदीप जायसवाल भी नाखुश बताए जा रहे हैं। क्योंकि वित्तीय वर्ष समाप्ति की कगार पर है और इससे विभाग का टारगेट भी प्रभावित होगा।

● **कुमार राजेन्द्र**

2018 का विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा लगातार लड़खड़ा रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में एकता नजर नहीं आ रही है। ऐसे में मप्र भाजपा की कमान संघनिष्ठ वीडी शर्मा को सौंपी गई है। शर्मा के सामने भाजपा को संगठित करने के साथ ही चुनौतियों का पहाड़ है। अब देखना यह है कि दिग्गज नेताओं से भरी भाजपा को वीडी शर्मा चुनौतियों से निकालकर किस तरह कांग्रेस के मुकाबिल खड़ा करते हैं।

चुनौतियों भरा ताज

सामंजस्य की जरूरत

दिग्गज नेताओं से सियासी समन्वय बनाकर प्रदेश भाजपा की नई टीम बनाना वीडी शर्मा के लिए बेहद कठिन काम है। प्रदेशाध्यक्ष को लक्ष्य केंद्रित भविष्य को ध्यान रखकर अपनी मर्जी से बेदाग लोगों की टीम बनाना होगी, तभी पीढ़ी परिवर्तन का संदेश सफल होगा। संगठन चुनाव के दौरान भाजपा के मात्र 33 जिलों के अध्यक्षों का चुनाव आम सहमति से हो पाया है। अब 23 संगठनात्मक जिलों में अध्यक्षों का मनोनयन होना है। इंदौर-भोपाल और ग्वालियर जैसे ये सारे जिले कद्दावर नेताओं के प्रभाव वाले जिले हैं। दबाव से वे कैसे निपटते हैं, इससे शर्मा की संगठनात्मक क्षमता का लोहा माना जाएगा। मप्र दिग्गज नेताओं से भरा पड़ा है, ऐसे में सभी नेताओं के साथ ऐसा उचित समन्वय, जो जनता के अनुकूल और संगठन के मुताबिक हो, बनाना होगा। अनाप-शनाप बयानबाजी, मनमर्जी से फैसले लेने और संगठन की लाइन के खिलाफ जाकर काम करने वालों पर शर्मा कैसे लगाम लगाते हैं, ये कठिन दायित्व है।

मप्र भाजपा में अब 4जी (फोर्थ जनरेशन) यानी चौथी पीढ़ी के नताओं का महत्व बढ़ेगा। प्रदेश भाजपा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ने वाले नेताओं की अब लॉटरी खुलने वाली है। वीडी शर्मा के प्रदेशाध्यक्ष बनने के बाद तय हो गया है कि भाजपा में उन्हें अहम पद मिलेंगे। नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए उन्हें तैयार किया जाएगा। ऐसा करके शर्मा अपनी व्यक्तिगत टीम को भी मजबूत करने का प्रयास करेंगे। गौरतलब है कि 2018 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की हार के बाद **राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ** ने पार्टी में चौथी पीढ़ी के नेताओं को आगे लाने का सुझाव दिया था। सूत्र बताते हैं कि संघ के सुझाव पर ही वीडी शर्मा को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है।

गौरतलब है कि शर्मा की सीधी नियुक्ति संघ और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की विशेष रूचि के चलते हुई है। साथ में उन्हें फ्री हैंड भी दिया गया है ताकि वे प्रदेश में संगठन के काम को एक बार फिर मजबूत करें। योजना के हिसाब से शर्मा का सारा फोकस संगठन से युवाओं को जोड़ने और नया नेतृत्व खड़ा करने पर होगा। इसके चलते विद्यार्थी परिषद की टीम को मजबूत किया जाएगा। उस हिसाब से परिषद से जुड़े नेता जो भाजपा में अब तक लूप लाइन झेल रहे थे, उनकी लॉटरी खुल सकती है। बची हुई जिलास्तर की इकाई में उन्हें महत्वपूर्ण भूमिका दी जा सकती है। शर्मा लंबा चलने के लिए संघ को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। उसकी पसंद को भी गंभीरता से लेंगे।

प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए विष्णुदत्त शर्मा की राह आसान नहीं है। प्रदेशाध्यक्ष का ताज तो शर्मा ने पहन लिया पर अब संगठन के सामने मुंह बाए खड़ी चुनौतियों से निपटने में उन्हें एड़ी-चोटी का जोर लगाना होगा। सबसे बड़ी दिक्तत बड़े नेताओं के साथ समन्वय की होगी। मप्र से चार बड़े नेता केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उमा भारती हैं, दोनों ही संगठन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। आधा दर्जन के करीब पूर्व प्रदेशाध्यक्ष हैं। वीडी शर्मा को इन सभी के साथ तालमेल बैठाकर चलना है। संगठन चुनाव में जिन मंडल और जिलों में चुनाव नहीं हो पाए हैं। वहां आम सहमति बनाकर मनोनयन करना है। इन सब चुनौतियों से वे निपट पाए तो ही संगठन को पटरी पर ला पाएंगे।

प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा के सामने सबसे बड़ी चुनौती भाजपा के प्रदेश संगठन को पटरी पर लाना है। 15 साल की सत्ता से हाथ धोने के बाद से भाजपा का कार्यकर्ता मायूस है। उसे मानसिक रूप से तैयार कर कैसे घर से निकालेंगे, इसकी रणनीति शर्मा को बनानी होगी। भौगोलिक संतुलन के साथ **जातिगत समीकरण** भी साधना होगा। भाजपा ने मंडल और जिला स्तर के चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उम्र सीमा तय कर दी थी। अब शर्मा के सामने बड़ी चुनौती है कि युवाओं की भागीदारी को संगठन में कैसे बढ़ाएं।

शर्मा के सामने संगठन के साथ ही पार्टी के सांसदों और विधायकों को भी सक्रिय करने की जिम्मेदारी है। सांसदों और विधायकों की निष्क्रियता के कारण पार्टी की साख लगातार गिर रही है। गौरतलब है कि मप्र में 2018 के

विधानसभा चुनाव हारने के बाद भाजपा ने 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में प्रदेश की 29 सीटों में से 28 सीटें जीतकर अपनी साख वापस पा ली थी। लेकिन चुनाव जीतने के 7 माह के दौरान प्रदेश के भाजपा सांसदों की निष्क्रियता से प्रदेश में भाजपा का जनाधार लगातार गिर रहा है। इसका खुलासा संघ के 34 आनुषांगिक संगठनों की रिपोर्ट में हुआ है। रिपोर्ट मिलने के बाद संघ ने डैमेज कंट्रोल के लिए सक्रियता बढ़ा दी है।

जानकारी के अनुसार, संघ ने दिसंबर 2019 में अपने आनुषांगिक संगठनों से भाजपा के सभी 303 सांसदों की परफॉर्मेंस का आंकलन करवाया। आनुषांगिक संगठनों ने संसदीय क्षेत्र में सांसदों की सक्रियता, उनके द्वारा अनुमोदित विकास कार्यों, सांसद निधि के उपयोग, सांसद आदर्श ग्राम की स्थिति, केंद्र सरकार की योजनाओं के **प्रचार-प्रसार** और सांगठनिक गतिविधियों में भागिदारी के आधार पर परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की है। इसमें सबसे खराब परफॉर्मेंस मप्र के सांसदों की रही है।

संघ के आनुषांगिक संगठनों ने अपनी जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कहा गया है कि इंदौर सांसद शंकर लालवानी के अलावा मप्र भाजपा के बाकी 27 सांसद अपने संसदीय क्षेत्र से पूरी तरह गायब रहे हैं। यानी संसदीय क्षेत्र में वे न तो पार्टी और न ही सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे हैं। इसका असर यह हुआ है कि न तो केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार-प्रसार हो सका और न ही प्रदेश सरकार के खिलाफ माहौल बनाया गया। गौरतलब है कि 28 भाजपा सांसदों में से 3 यानी नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और फग्गन सिंह कुलस्ते केंद्र सरकार में मंत्री हैं। मंत्री होने के कारण ये केंद्र में ही अधिक सक्रिय रहते हैं। इस कारण इनका अपने क्षेत्र में कम आना होता है। लेकिन बाकी 23 सांसद पूरी तरह निष्क्रिय रहे हैं।

लोकसभा चुनाव जीतकर पहली बार संसद पहुंचे मप्र के सांसदों का प्रदर्शन हर क्षेत्र में काफी निराशाजनक रहा। संघ के एक पदाधिकारी कहते हैं कि लोकसभा सत्र में कुछ सांसदों ने न ही प्रश्नकाल में कोई सवाल किया न ही शून्यकाल

के दौरान पूछा। उन्होंने अपने क्षेत्र से संबंधित कोई भी समस्या नहीं उठाई। ऐसा क्यों हुआ इसको लेकर संघ पड़ताल करवा रहा है। संघ भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खराब प्रदर्शन से काफी चिंतित है। मध्यप्रदेश के अन्य सभी नए सांसदों के मुकाबले साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर कमजोर प्रदर्शन करने वाली सांसद बनकर उभरी हैं। सही मौके पर साध्वी की चुप्पी तुड़वाने के लिए अब संघ रणनीति तैयार कर रहा है। यह तय किया गया है कि प्रज्ञा के आसपास मौजूद लोगों से उन्हें मुक्ति दिलाकर नए सलाहकार और सहयोगी नियुक्त किए जाएंगे। साध्वी के आसपास का यह घेरा संघ तैयार करेगा। संघ के लोग ही आसपास नजर आएंगे। वही लोग प्रज्ञा को सलाह देंगे, ताकि सही मौके पर और लोकसभा में साध्वी की चुप्पी टूटे और बेवक्त आने वाले बयानों का सिलसिला थम सके।

सूत्र बताते हैं कि भोपाल में हुई संघ की बैठक में आनुषांगिक संगठनों ने संघ प्रमुख मोहन भागवत को रिपोर्ट दी है कि ज्वलंत मुद्दों जैसे अनुच्छेद 370 को जम्मू-कश्मीर से हटाने, तीन तलाक और सीएए के समर्थन में भाजपा द्वारा जितने भी कार्यक्रम आयोजित किए वे प्रभावहीन रहे। इसकी वजह यह बताई गई कि सांसद और विधायक निष्क्रिय रहे। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भाजपा और अन्य संगठनों से जुड़े लोगों के बीच चाल, चरित्र और चेहरे पर उठ रहे सवालों पर चिंता जताई है। साथ ही हिदायत दी है कि वे अपने आचरण पर भी गौर करें। सूत्रों का कहना है कि पिछले दिनों हनीट्रैप मामले के सामने आने और कई अन्य मामलों में भाजपा नेताओं और प्रचारकों के जुड़े होने की तरफ इशारों-इशारों में उन्होंने यह बात कही। सूत्रों के अनुसार, भागवत ने संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों को संघ की साख याद दिलाई। साथ ही कहा, समाज उनकी तरफ देखता है, अगर उनके आचरण में गिरावट आएगी, तो यह स्वीकार्य नहीं होगा। लिहाजा, सभी को अपने आचरण में बदलाव लाना होगा, अनुशासित रहना होगा।

संघ प्रमुख ने भाजपा नेताओं और अन्य संगठनों से जुड़े लोगों को संघ की सामाजिक प्रतिष्ठा याद दिलाई। साथ ही उन्हें अपने अतीत से सीख लेने पर जोर दिया। इतना ही नहीं, नेताओं की कार्यशैली और उन पर उठे सवालों पर सीधे तौर पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि संघ समाज के बीच जाकर समस्याओं और राष्ट्र की चुनौतियों के लिए लोगों को तैयार करता है, मगर राज्य के कई नेताओं के सवालों में घेरने से पूरे संगठन की छवि पर असर पड़ता है, इसे रोकने के प्रयास होने चाहिए।

● **अरूण दीक्षित**

नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में संघ संभालेगा मोर्चा

अपने गढ़ में भाजपा की कमजोर होती ताकत को मजबूत करने के लिए संघ ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। सूत्रों के अनुसार आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव में पार्टी का जनाधार मजबूत करने के लिए संघ मोर्चा संभालेगा। प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ही अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक भी मैदान में उतरेंगे। इस दौरान गोष्ठी के साथ ही स्वयंसेवक घर-घर जाकर राष्ट्रवाद का अलख जगाएंगे। इस काम में किसी तरह की कोताही न हो, इसके लिए समन्वयकों की भी तैनाती की जा रही है। संघ के सूत्रों के अनुसार लोकसभा चुनाव में स्वयंसेवकों ने जनता के बीच हजारों बैठकें की थीं। इस बार बैठकों की संख्या और अधिक करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि समाज के सभी वर्गों तक अपनी बात पहुंचाई जा सके। दरअसल, इन दिनों सीएए को लेकर फैलाए जा रहे दुष्प्रचार से संघ भी चिंतित है। संघ का मानना है कि वोट बैंक की राजनीति में भाजपा विरोधी पार्टियां सीएए को लेकर लोगों को गुमराह कर रही हैं। इसे ध्यान में रखकर लोकसभा की तुलना में ज्यादा बैठक करने के साथ ही जनसंपर्क अभियान चलाने का फैसला किया गया है। स्वयंसेवक लोगों से मिलकर उन्हें सीएए की सच्चाई बताएंगे। इसके साथ ही देश को कमजोर करने की चल रही साजिश के बारे में बताएंगे।

अटक गए निकाय चुनाव

मध्यप्रदेश में निकाय व पंचायत चुनाव ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर से कराने की पूरी संभावना है। मतदान का पैटर्न बदले जाने पर सरकार में सहमति बन गई है। अभी पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में निकाय और पंचायत चुनाव बैलेट पेपर से कराए जाने की व्यवस्था है। हालांकि अभी सूबे में चुनाव कराए जाने की तारीखों का पेंच फंसा है। कहा जा रहा था कि चुनाव मई में कराए जा सकते हैं। मगर अब खबर मिल रही है कि इसे अक्टूबर या नवंबर में कराया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक पिछले दिनों मुख्यमंत्री कमलनाथ और निर्वाचन आयुक्त की मुलाकात में बैलेट पेपर से चुनाव कराने के संबंध में चर्चा हुई थी। जिसमें चुनाव आयोग ने तर्क दिया कि अभी ऐसा कराया जाना संभव नहीं है। इसके लिए वक्त चाहिए होगा। इसी के मद्देनजर मई में होने वाले चुनाव छह माह के लिए टाले जा सकते हैं। उनका कहना था कि तत्काल यह कराना संभव नहीं हैं। सरकार के सूत्र बताते हैं कि प्रदेश के मंत्री भी इस बात पर सहमत हैं कि भले ही चुनाव में देरी हो, लेकिन इसे बैलेट पेपर से ही कराया जाना चाहिए। ईवीएम से चुनाव कराए जाने से भाजपा गड़बड़ी कर सकती है। अब यह मामला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पास जाएगा। वही इस पर फैसला लेंगे।

वर्ष 1994 के बाद यह पहला मौका है जब प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनावों को लेकर की गई तैयारियों का अधूरा होना है। दरअसल, मामला वार्डों के परिसीमन में ही अटका हुआ है तो दूसरी ओर भाजपा के वर्चस्व वाली निकायों को कांग्रेस हथियाना चाहती है। लिहाजा निकायों में जोड़तोड़ से सत्ता हासिल करने की अघोषित रूपरेखा भी तैयार की गई है। **परिसीमन को लेकर दो दर्जन से अधिक मामले हाईकोर्ट में विचाराधीन हैं।** राज्य निर्वाचन आयोग सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रहा है। गौरतलब है कि संविधान के 73 व 74 वें संशोधन के बाद मप्र राज्य निर्वाचन आयोग को निकायों के चुनावों की जिम्मेदारी मिली थी। वर्ष 2015 में परिसीमन के कारण भोपाल समेत कुछ नगरीय निकायों में चुनाव देरी से हुए थे। विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य सरकार नगरीय निकायों पर कब्जा करने के लिए सोची-समझी रणनीति के तहत काम कर रही है। इसमें निकायों के कार्यकाल खत्म होने का इंतजार किया जा रहा है। इसके बाद नगरीय विकास एवं आवास विभाग संबंधित निकायों के संचालन की जिम्मेदारी प्रशासक के रूप में अधिकारियों को सौंप रहा है। इस तरह, एक प्रकार से निकायों पर पूरी तरह से नियंत्रण राज्य सरकार का ही होगा। जबकि नियमों में यह बात साफ कही गई है कि निकायों के कार्यकाल खत्म होने से पहले ही इसकी चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए।

पहली बार देर से होंगे चुनाव

1994 के बाद यह पहला मौका है जब प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव समय पर नहीं हो पा रहे हैं। इसकी बड़ी वजह राज्य सरकार द्वारा निकाय चुनावों को लेकर की गई तैयारियों का अधूरा होना है। दरअसल, मामला वार्डों के परिसीमन में ही अटका हुआ है तो दूसरी ओर भाजपा के वर्चस्व वाली निकायों को कांग्रेस हथियाना चाहती है। गौरतलब है कि संविधान के 73 व 74वें संशोधन के बाद मप्र राज्य निर्वाचन आयोग को निकायों के चुनावों की जिम्मेदारी मिली थी। वर्ष 2015 में परिसीमन के कारण भोपाल समेत कुछ नगरीय निकायों में चुनाव देरी से हुए थे। उधर, निकायों पर फतह हासिल करने के लिए प्रदेश की कांग्रेस सरकार पूरा जोर लगा रही है। वहीं, नियमों में फेरबदल व अन्य बदलावों पर भाजपा नेताओं की सिर्फ बयानबाजी ही सामने आई है। स्थानीय स्तर पर नगर निगम के बंटवारे, महापौर के अप्रत्यक्ष चुनाव जैसे मामले पर विरोध हुआ लेकिन इसे प्रदेश स्तरीय मुद्दा बनाने में भाजपा नाकाम नजर आई।

भोपाल नगर निगम को दो भागों में विभाजित करने के मामले पर हाईकोर्ट ने स्थगन दे दिया है। हालांकि राज्य सरकार का यह गणित वोटों के बंटवारे के लिए था, इसमें भी नियमों को ताक पर रखकर काम किया गया। हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने इससे जुड़े एक मामले में प्रदेश सरकार को झटका दे दिया। नगरीय विकास एवं आवास विभाग की ओर से राजपत्र जारी किया गया था। इसमें नगरीय निकायों की सीमाओं में बदलाव को लेकर सूचना संबंधित अधिकार कलेक्टर को दिए गए थे। प्रावधानों के मुताबिक शहरी सीमा में किसी भी क्षेत्र को जोड़ने या घटाने को लेकर अधिकार राज्यपाल का होता है। इसी विसंगति पर हाईकोर्ट ने स्थगन दे दिया।

नगरीय निकाय के चुनावों की अधूरी तैयारी को लेकर सरकार की मंशा पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर 70 निकायों में वार्ड परिसीमन का काम पूरा हो चुका है। उधर, विभाग में अभी तक परिसीमन के प्रस्ताव आ रहे हैं। इसके अलावा नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने कलेक्टरों से संबंधित निकायों की वार्डों की संख्या संबंधित अधिसूचना का प्रतिवेदन, वर्ष 2011 की जनगणना के तहत कुल जनसंख्या, वार्डवार जनसंख्या, वार्डवार अनुसूचित जाति व जनजातियों की जनसंख्या की जानकारी मांगी है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि जब तक परिसीमन का काम नहीं होगा तब तक आरक्षण संबंधित कार्यवाई पूरी नहीं हो सकेगी।

प्रदेश में बीते एक महीने में कुल 278 नगरीय निकायों में प्रशासक नियुक्त किए जा चुके हैं। इसमें भोपाल की बैरसिया नगर परिषद का नाम भी शामिल है। प्रदेश में कुल 378 नगरीय निकाय हैं। नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा शेष 100 नगरीय निकायों में भी प्रशासकों की नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। प्रशासक के रूप में संभागीय कमिश्नर, कलेक्टर व अनुविभागीय अधिकारियों (राजस्व) को संबंधित निकायों की जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।

● **सुनील सिंह**

यह कैसी मुलाकात

मप्र कांग्रेस की राजनीति हमेशा से अबूच पहेली रही है। यही कारण है कि कोई भी यह अनुमान नहीं लगा सकता कि इस पार्टी में कब क्या हो जाए। विगत दिनों प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस के दो नेताओं राष्ट्रीय महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया और सांसद दिग्विजय सिंह की एकांत मुलाकात की हवा ऐसी उड़ी कि सबकी निगाह इस मुलाकात पर टिक गई। पूरा देशी और विदेशी मीडिया का ध्यान गुना पर टिक गया। दरअसल, माना जा रहा था कि इस गुप्तवार्ता के बाद मप्र कांग्रेस में उठ रहे **विरोध** थम जाएंगे। गौरतलब है कि सिंधिया अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। इसलिए गुना में दोनों नेताओं के बीच एकांत में होने वाली मुलाकात पर सबकी नजर थी। लेकिन जैसा कहा और सुना गया था, वैसा कुछ नहीं हुआ। गुना में सिंधिया और दिग्विजय मिले, लेकिन वह भी सड़क पर। दोनों नेता जब एक-दूसरे के आमने-सामने आए तो गर्मजोशी से मिले और एक-दूसरे को पुष्पहार पहनाया और चलते बने। लोगों को यह समझ में नहीं आया कि आखिर यह कैसी मुलाकात है। जबकि उसी दिन भोपाल में सिंधिया ने कहा था कि मुलाकात तो होनी ही थी, अगर वह गुना में नहीं तो दिल्ली में जरूर होती।

उल्लेखनीय है कि कांग्रेस में गुटबाजी खत्म करने के लिए दिग्गी और सिंधिया आठ साल पहले गुना में राजीव गांधी कांग्रेस भवन का लोकार्पण करने गए थे। इस दौरान दोनों नेता ने एक-दूसरे की शान में जमकर कसीदे पढ़े थे। 9 दिसंबर 2012 में कांग्रेस कार्यालय भवन के लोकार्पण के समय सिंधिया ने कहा था कि वह दिग्विजय सिंह के बेटे की तरह हैं। साथ ही उन्होंने दिग्गी राजा को **अपना प्रेरणास्त्रोत** तक कह दिया था। वहीं दिग्विजय सिंह ने कहा था कि सिंधिया यूपीए सरकार के सबसे काबिल मंत्री हैं। वहीं सिंधिया पर चुटकी लेते हुए उन्होंने कहा था कि बालहठ के आगे किसी की कहां चलती है। ठीक आठ साल बाद गुना में फिर दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच सर्किट हाउस के बंद कमरे में 45 मिनट तक बैठक होना थी लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दरअसल, मप्र कांग्रेस की राजनीति ही ऐसी है कि बड़े से बड़ा विश्लेषक भी उसे समझ नहीं पाता है।

वर्तमान समय में मुख्यमंत्री कमलनाथ और सिंधिया के बीच जिस तरह की राजनीतिक खींचतान चल रही है, वह 20 साल पहले की उस स्थिति का अहसास कराती है जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और सुभाष यादव में थी।

करीब 20 साल पहले दिग्विजय सिंह से उनके उप मुख्यमंत्री सुभाष यादव भी उलझ पड़े थे। सुभाष यादव ने नशाबंदी की आड़ में दिग्विजय पर निशाना साधा था। सिंह तथा यादव के बीच का झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों के बीच रोशनपुरा के जवाहर भवन में स्थित तत्कालीन राज्य कांग्रेस मुख्यालय में 'संधि वार्ता' कराना पड़ गई थी। लेकिन पूरे प्रसंग में न तो यादव ने कभी खुलकर 'सड़क पर उतरने' जैसी बात कही और न ही कभी सिंह को अपना स्तर 'तो उतर जाएं' वाला करना पड़ा। नाथ तथा सिंधिया के बीच जो कुछ चल रहा है, वह राजनीतिक शिष्टाचार के क्षरण की प्रक्रिया को और पंख प्रदान करने वाला ही माना जाएगा। सिंधिया को जो बात पार्टी के फोरम पर कहना चाहिए थी, वह उन्होंने सार्वजनिक मंच पर कह दी। नाथ को जिस संयम का परिचय देना चाहिए था, उसे एक किनारे रखकर उन्होंने पहले पांच साल बनाम पांच महीने और फिर तो उतर जाएं जैसी बात कह दी। नतीजा यह कि राज्य सरकार सहित सत्तारूढ़ दल के संगठन का जमकर चीरहरण किया जा रहा है। हालांकि इस वाकये से एक बात साफ है कि सिंधिया की स्थिति पार्टी में अब पहले जैसी मजबूत नहीं रह गई है। क्योंकि यह ध्यान रखना होगा कि यह बयान नाथ ने दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद दिया था। यानी, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नाथ ने आलाकमान से सिंधिया के बयानों पर बात की और फिर वहां से मिले संकेतों के आधार पर ही उनके लिए दो-टूक वाला भाव अपना लिया। दिग्विजय सिंह डैमेज कंट्रोल में जुट गए हैं। नाथ के कथन के बाद 'पार्टी में सभी साथ हैं' वाली बात कहकर वे सियासी रफूगरी के हुनर का परिचय देते नजर आ रहे हैं।

सिंधिया ताकत रूपी उस नशे का तोड़ तलाशने की जुगत में हैं, जिसके असर से नाथ एवं उनके खासमखास लोग प्रदेश सरकार सहित संगठन को अपनी बपौती मानकर आचरण कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में उस समय चहुंओर रौनक लौटी थी, जब नाथ के नेतृत्व में 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। तब हर गुट के नेता तथा समर्थक वहां विजय का सामूहिक गीत गा रहे थे। लेकिन अब इसी भवन में चले जाइए। सिंधिया गुट का वहां कोई नामलेवा भी नजर नहीं आता है। जो हैं वह या तो नाथ के खास लोग हैं या फिर वे, जिनके सिर पर दिग्विजय का हाथ माना जाता है।

● **अरविंद नारद**

ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं परफेक्ट कैंडिडेट

राज्यसभा की खाली हो रही सीटों पर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी हो गया है। इसके साथ ही दावेदार भी सामने आने लगे हैं। मध्यप्रदेश में कांग्रेस में राज्यसभा के लिए सबसे ज्यादा मारामारी है। अभी तक दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया दोनों सीटों के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। इस बीच ज्योतिरादित्य सिंधिया खेमे के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत का बड़ा बयान सामने आया है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की दावेदारी है या नहीं, ये तो मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन सिंधियाजी हर चीज के लिए कैपेबल हैं। वो राज्यसभा और प्रदेश अध्यक्ष के लिए परफेक्ट कैंडिडेट हैं। ये मेरी व्यक्तिगत राय है। लेकिन ये सिर्फ मेरी व्यक्तिगत राय नहीं बल्कि पूरे प्रदेश की इच्छा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेजा जाए और प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया जाए। वहीं, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के बयान पर मंत्री डॉ. गोविंद सिंह ने कहा कि ये तय करना हाईकमान का काम है कि किसको राज्यसभा भेजे और किसको नहीं। जो भी निर्णय हाईकमान लेगा, उसे हम लोग शत-प्रतिशत पालन करेंगे। दरअसल, गोविंद सिंह का यह बयान गोविंद सिंह राजपूत के बयान के बाद आया है। राजपूत खुलकर सिंधिया को राज्यसभा भेजने की वकालत कर रहे थे।

नाबार्ड के सहयोग से बढ़ाई जाएगी भंडारण क्षमता

खाद्य-नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर ने कहा है कि नाबार्ड के सहयोग से प्रदेश में खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार किया जाएगा। निजी गोदाम संचालकों को प्रोत्साहित किया जाएगा। नए गोदामों का निर्माण कराया जाएगा। इस काम में नाबार्ड के माध्यम से 221 करोड़ 27 लाख रुपए व्यय किए जाएंगे। मंत्री तोमर ने बताया कि इस परियोजना में अनावश्यक खाद्यान्न परिवहन व्यय को कम करने के लिए विकासखंड स्तर पर 136 चिन्हित स्थानों पर और 76 उपार्जन केंद्रों पर 500-500 मैट्रिक टन क्षमता के गोदाम-सह-उचित मूल्य दुकानों के लिए भवनों का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इन भवनों में किसानों एवं हितग्राहियों के लिए शुद्ध पेयजल और सुलभ कॉम्पलेक्स आदि मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएंगी। इस कार्य पर परियोजना की कुल राशि में से 77 करोड़ 40 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी। प्रद्युमन सिंह तोमर ने बताया कि परियोजनान्तर्गत वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन की भंडारण क्षमता का विस्तार किया जा रहा है। प्रदेश में अभी वेयर हाऊसों की भंडारण क्षमता 23 लाख मैट्रिक टन है। अब इन वेयर हाउसों में सीमेंट कांक्रीट रोड और बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जा रहा है। साथ ही, 250 वेयर हाउसों में सुलभ कॉम्पलेक्स और पेयजल सुविधा के विस्तार का काम जारी है। तोमर ने बताया कि 74 हजार मैट्रिक टन क्षमता के केप को भी गोदाम के रूप में परिवर्तित किया जा रहा है। राज्य सरकार ने प्रदेश में 2 स्थानों पर आधुनिक पद्धति से सर्वसुविधायुक्त गोदाम बनाने तथा 66 स्थानों पर डिजिटाईज्ड-9-वे ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया है। इन कार्यों पर परियोजना की कुल राशि में से 143 करोड़ 87 लाख रुपए की राशि व्यय की जाएगी।

विकास में थर्ड एम्पायर की भूमिका निभाएं युवा

आदिम-जाति कल्याण मंत्री ओमकार सिंह मरकाम ने अपने प्रभार के जिला शहडोल में ग्राम पंचायत भठिया में युवा संवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने ग्रामीण विकास में युवाओं की सहभागिता की आवश्यकता बताते हुए कहा कि जमीनी स्तर पर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में युवाओं की भूमिका थर्ड एम्पायर की होनी चाहिए। मरकाम ने कहा कि सरकारी योजनाओं का प्रभावी और परिणाममूलक क्रियान्वयन तभी होगा, जब युवा शासकीय योजनाओं के प्रति जागरूक होंगे। उन्होने कहा कि जल और पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं को आगे आकर काम करना चाहिए। प्रभारी मंत्री मरकाम ने कहा कि युवा विकास में सहभागी बनें तथा विश्वास के साथ प्रदेश को आगे बढ़ाएं। उन्होंने कहा कि शहडोल जिले के हर गांव में दस युवाओं की समिति बनेगी। यह समिति गांव में निर्माण कार्यों, पेंशन योजनाओं, स्वास्थ्य सेवाओं, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित कल्याणकारी योजनाओं एवं अन्य योजनाओं की मॉनीटरिंग करेगी।

मध्य प्रदेश की बेटियां पढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगी

महिला-बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने कहा कि प्रदेश की बेटियां पढ़ेंगी और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ेंगी। राज्य सरकार इस दिशा में सतत रूप से प्रयासरत है। मंत्री इमरती देवी खजुराहो में समृद्धि परियोजना के अंतर्गत एक्सपोजर राज्य-स्तरीय कार्यशाला में बोल रही थीं। यूएनएफटीए के सहयोग से आयोजित इस कार्यशाला में महिला-बाल विकास मंत्री ने कहा कि सतत प्रयासों से बेटियों की तरक्की को लेकर परिवार और समाज की सोच में सकारात्मक बदलाव आया है।

बेटियों ने हर क्षेत्र में लंबी छलांग लगाई है और उपलब्धियों के शिखरों का स्पर्श किया है। उन्होंने कहा कि बेटियों की शिक्षा को लेकर सरकार गंभीर है क्योंकि शिक्षित मां से ही परिवार शिक्षित बनता है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों और मैदानी कर्मचारियों से अपेक्षा की कि वे पूरे दायित्व-बोध के साथ अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन करेंगे। मंत्री इमरती देवी ने किशोरी बालिकाओं में लीडरशिप और स्किल डेव्हलपमेंट के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की महत्ता को रेखांकित करते हुए इस दिशा में यूएनएफपीए के प्रयासों की सराहना की।

विभाग के आयुक्त नरेश पाल ने बताया कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को आगामी 8 मार्च को विश्व महिला दिवस के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा। उन्होंने विभाग में ग्रेडिंग सिस्टम लागू होने की जानकारी दी। इस अवसर पर महिला-बाल विकास मंत्री ने समृद्धि (सेग) मोबाइल एप का लोकार्पण किया, जिसके जरिए विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन की बेहतर मॉनीटरिंग सुनिश्चित की जा सकेगी।

हुनरमंद बुनकरों, कारीगरों को मिलेगा प्रोत्साहन

कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री हर्ष यादव ने भोपाल हाट में नेशनल हैण्डलूम एक्सपो के समापन अवसर पर प्रदेश के उत्कृष्ट शिल्पियों को राज्य-स्तरीय कबीर बुनकर एवं विश्वकर्मा पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि माटी शिल्प, बांस शिल्प, काष्ठ कला, बुटिक प्रिंट, गोंडी चित्रकला, ब्लॉक प्रिंट, जूट शिल्प और ऐसी ही अन्य हस्तकलाओं के प्रतिभावान कलाकारों को निरंतर प्रोत्साहित किया जाएगा। कुटीर एवं ग्रामोद्योग मंत्री ने कलाकृतियों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। मंत्री यादव ने कहा कि वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए निर्णायक मंडल द्वारा शिल्पियों का चयन कर उन्हें पुरस्कृत करने का कार्य प्रदेश की नई सरकार ने किया है। इससे शिल्पियों और कलाकारों को अपनी कला में सुधार और विक्रय से आर्थिक उन्नति के अवसर भी मिलेंगे।

उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में बुनकरों को प्रशिक्षण और वर्कशेड उपलब्ध कराने पर ध्यान दिया गया है। उनके उत्पादों के विक्रय और विपणन के लिए भी आवश्यक सहयोग दिया जा रहा है। विभिन्न प्रदर्शनियों और मेलों में उनकी कलाकृतियों के प्रदर्शन के माध्यम से कलाकारों को लाभान्वित किया जा रहा है।

कुपोषण से मुक्ति में अहम भूमिका निभाए आयुष विभाग

चिकित्सा शिक्षा, आयुष एवं संस्कृति मंत्री डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ ने टीकमगढ़ में नव-निर्मित जिला आयुष कार्यालय भवन का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर अपने संबोधन में मंत्री डॉ. साधौ ने कहा कि जिले में मातृ-मृत्यु दर तथा शिशु मृत्यु दर (एमएमआर तथा आईएमआर) के साथ ही कुपोषण कम करने में आयुष विभाग महत्वपूर्ण भूमिका निभाए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में आयुष विभाग द्वारा सुपोषण के साथ ही वेलनेस गतिविधियों के माध्यम से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि स्वस्थ और सबल मध्यप्रदेश हम सबका प्रयास है। मंत्री डॉ. साधौ ने कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ के विजन के अनुसार आयुष विभाग प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी क्रम में आयुष विभाग के इन्फ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। साथ ही चिकित्सकों एवं स्टॉफ की कमी को भी शीघ्र पूरा किया जाएगा।

यह सरकार कथन की नहीं वचन की सरकार है

किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री सचिन यादव ने धार जिले के बदनावर कृषि उपज मंडी प्रांगण में जय किसान फसल ऋण माफी योजना के द्वितीय चरण में लाभार्थियों को ऋण माफी प्रमाण पत्र, किसान सम्मान पत्र प्रदान किए तथा हितग्राहियों को अनुदान राशि प्रमाण पत्र व तीन ट्रैक्टर, एक हार्वेस्टर और एक रोटावेटर मशीन देकर लाभान्वित किया। कार्यक्रम में बताया गया कि योजना के द्वितीय चरण में बदनावर तहसील के चार हजार 389 किसानों को 31 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि का हस्तांतरण आरटीजीएस के माध्यम से किया जा रहा है। योजना के प्रथम चरण में तहसील बदनावर के आठ हजार 473 किसानों को 32 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि का हस्तांतरण आरटीजीएस के माध्यम से किया गया था। अतिथियों का स्वागत साफा बांध, शाल व पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया।

कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों के द्वारा रासायनिक खाद और उर्वरक के अधिक प्रयोग से उत्पादन में थोड़ी वृद्धि तो हुई है लेकिन उसके साथ यह अन्न खाकर कई प्रकार की बीमारियां उन्हें और उनके परिजनों को हो रही है। उन्होंने कहा कि बदनावर के किसान प्रगतिशील किसान है। वे जैविक खेती को अपनाएं। फसलों की सभी बीमारी का इलाज गौमाता के पास है। जैविक खेती के लिए कृषि विभाग के माध्यम से किसानों को प्रशिक्षित किया जाएगा। रासायनिक उर्वरक ओर कीटनाशक के प्रयोग से उत्पादित अन्न में 70 प्रतिशत तक हानिकारक केमिकल पाया जाता है, ऐसा एक स्टडी में बताया गया है इसलिए खाने वाले को गंभीर बीमारी की आशंका बनी रहती है। यादव ने बताया कि किसान आंदोलन के दौरान किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के लिए कलेक्टर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। किसान उस कमेटी को आवेदन दें। शीघ्र ही प्रकरण वापसी का सिलसिला भी होगा।

● अक्स टीम

महंगी होगी शराब

3605 शराब दुकानों को लेकर केविएट दायर

कमलनाथ सरकार ने अपनी नई आबकारी नीति घोषित कर दी है, जिसका कई ठेकेदारों द्वारा विरोध किया जा रहा है। इस नीति को अदालती चुनौती न मिले और एकतरफा स्टे न हो जाए, जिसके लिए शासन के निर्देश पर आबकारी विभाग ने हाईकोर्ट में केविएट दायर कर दी है। 3605 देशी-विदेशी शराब दुकानों की ई-टेंडर के जरिए नीलामी आगामी वित्तीय वर्ष के लिए शुरू की जा रही है। पहले आबकारी नीति में शराब ठेकेदारों को 5 किलोमीटर के दायरे में एक उपदुकान भी खोलने की अनुमति देने का प्रस्ताव था, जिसका कुछ मंत्रियों ने विरोध किया। इसके चलते उपदुकानों का प्रस्ताव खारिज कर दिया। अलबत्ता 25 प्रतिशत कीमत अवश्य बढ़ा दी, जिससे शराब दुकानें इतनी महंगी होंगी ही, वहीं 1 अप्रैल से देशी-विदेशी शराब की कीमतों में भी 25 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हो जाएगी। शासन की इस नई आबकारी नीति को अदालत में चुनौती मिल सकती है और नीलामी प्रक्रिया को रोकने के लिए कहीं स्टे न मिल जाए, जिसके चलते हाईकोर्ट में केविएट दायर की गई। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गजट नोटिफिकेशन के जरिए वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नई नीति प्रदेशभर में लागू कर दी गई है। इसके चलते शराब दुकानों के ठेके, बार लाइसेंस और अन्य प्रक्रिया विभाग द्वारा शुरू की जा रही हैं, जिसके चलते वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय द्वारा जारी नोटिफिकेशन के विरुद्ध हाईकोर्ट से स्टे आदेश हासिल न किया जा सके, इसके लिए केविएट दायर कर दी है। वहीं भोपाल सहित प्रदेशभर में 2544 देशी शराब दुकानों और 1061 विदेशी शराब दुकानों के ठेके 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ ई-टेंडर नीलामी प्रक्रिया से दिए जाएंगे।

मध्य प्रदेश में राजस्व में बढ़ोतरी के लिए शराब दुकानों के वार्षिक मूल्य में 25 फीसदी वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। आगामी वित्तीय वर्ष में दुकानों की दर में यह बढ़ोतरी होगी। साथ ही नई उप-दुकानें न खोलने का भी सरकार ने फैसला लिया है। आधिकारिक तौर पर दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तावित आबकारी व्यवस्था में राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से 2,544 देशी मदिरा दुकानों और 1,061 विदेशी मदिरा दुकानों का निष्पादन पूर्व वर्ष के वार्षिक मूल्य में 25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ किया जाएगा। दुकानों का आवंटन ई-टेंडर सह-नीलामी प्रक्रिया से होगा।

मध्यप्रदेश के सभी 52 जिलों में देशी-विदेशी मदिरा दुकानों की नीलामी के लिए शासन ने आबकारी नीति घोषित कर दी है। वर्ष 2020-21 के लिए शराब दुकानें 25 फीसदी बढ़ोतरी से नीलाम होंगी और महानगरों में दो समूह बनेंगे। 15 पर्यटन स्थलों पर **अंगूर वाइन** के आउटलेट भी खुलेंगे। शराब की उपदुकानें नहीं खुल सकेंगीं। शासन को इस व्यवस्था से दो हजार करोड़ रुपए अतिरिक्त आय होने की उम्मीद है। राज्य सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आबकारी नीति लागू कर दी है। खास बात यह है कि मध्यप्रदेश में शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी, आबकारी विभाग ने पहले प्रस्ताव दिया था कि शराब दुकान के पांच किलोमीटर के दायरे में यदि कोई दुकान नहीं है तो ठेकेदार को उप दुकान खोलने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट ने आपत्ति ली थी। इसके बाद मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पुनर्विचार कर नीति लागू करने के निर्देश दिए थे।

नई नीति के अनुसार राजस्व बढ़ाने एवं सुरक्षित करने के लिए प्रदेश के 52 जिलों में दो हजार 544 देशी मदिरा दुकानों एवं एक हजार 61 विदेशी मदिरा **दुकानों का निष्पादन** पिछले वर्ष के वार्षिक मूल्य में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर ई-टेंडर सह-नीलामी व नवीनीकरण से किया जाएगा। प्रदेश के चार बड़े महानगर वाले जिले भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एवं जबलपुर में दुकानों के दो-दो समूह बनाए जाएंगे, जिसमें शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र तथा देशी-विदेशी मदिरा की दुकानें होंगी। इन मदिरा दुकानों का निष्पादन ई-टेंडर सह नीलामी से होगा एवं आरक्षित मूल्य पिछली बार के वार्षिक मूल्य से 25 प्रतिशत बढ़ाकर रखा जाएगा।

नगर निगम वाले 12 जिलों में दुकानों का एक समूह बनाकर मदिरा दुकानों का निष्पादन ई-टेंडर सह नीलामी से होगा एवं आरक्षित मूल्य पूर्व वर्ष के वार्षिक मूल्य से 25 प्रतिशत बढ़ाकर रखा जाएगा। 36 जिलों में वर्ष 2019-20 में प्रचलित मदिरा दुकानों के यथास्थित एकल समूहों के वार्षिक मूल्य में वर्ष 2020-21 के लिए 25 प्रतिशत की वृद्धि कर आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाकर, उनका निष्पादन वर्ष 2019-20 में प्रचलित व्यवस्था अनुसार अर्थात नवीनीकरण, लॉटरी एवं ई-टेंडर (क्लोज बिड एवं ऑक्शन) के माध्यम से किया जाएगा।

मध्यप्रदेश के अंगूर उत्पादक कृषकों की आय वृद्धि एवं अंगूर की खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंगूर से बनाई जा रही वाइन के प्रसार के लिए पर्यटन स्थलों पर 15 नए आउटलेट खोले जाएंगे। मदिरा के व्यवसाय पर प्रभावी नियंत्रण करने के उद्देश्य से प्रत्येक बोतल में बार-कोड लगाए जाने के अतिरिक्त प्रत्येक बोतल की निगरानी का प्रयास किया जाएगा। खनिज साधन मंत्री प्रदीप जायसवाल और वित्त मंत्री तरुण भनोत ने कैबिनेट में सुझाव दिया था कि छोटे क्लस्टर बनाने की जगह जिले में दो-तीन समूह बनाकर ठेके दिए जाएं। सरकार ने इसे मान लिया है। जायसवाल खुद शराब व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, इस लिहाज से सरकार ने उनके सुझाव को तवज्जो दी।

प्रदेश के चार बड़े महानगर वाले जिले भोपाल, इंदौर, ग्वालियर और जबलपुर में दुकानों के 2-2 समूह बनाए जाएंगे। इन समूहों में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र की **देशी-विदेशी मदिरा** की दुकानें शामिल होंगी। शेष 12 नगर निगम वाले जिलों में दुकानों का एक समूह बनाया जाकर निष्पादन की कार्यवाही ई-टेंडर सह-नीलामी प्रक्रिया से होगी। शेष 36 जिलों में वर्ष 2019-20 में प्रचलित मदिरा दुकानों के यथास्थित एकल समूहों के वार्षिक मूल्य में 25 प्रतिशत की वृद्धि कर आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएगा। इन दुकानों का निष्पादन वर्ष 2019-20 में प्रचलित व्यवस्था के अनुसार अर्थात नवीनीकरण, लॉटरी, ई-टेंडर के माध्यम से किया जाएगा। देशी और विदेशी मदिरा की उप-दुकानें नहीं खोली जाएंगी।

● **राजेश बोरकर**

कर्ज के सहारे सरकार

केंद्र सरकार के असहयोग के कारण प्रदेश सरकार वित्तीय संकट के दौर से गुजर रही है। इसलिए प्रदेश सरकार को लगातार कर्ज लेना पड़ रहा है। 25 फरवरी को एक बार फिर बाजार से एक हजार करोड़ रुपए का कर्ज सरकार को लेना पड़ा। इस राशि का उपयोग विकास परियोजनाओं और वित्तीय गतिविधियों में किया जाएगा। गौरतलब है कि मार्च में सरकार मप्र का बजट पेश करेगी। ऐसे में सरकार के सामने चुनौतियों का पहाड़ है।

विगत दिनों मुख्यमंत्री निवास पर बजट को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा है कि बजट में आम जनता विशेष तौर पर ग्रामीणों से संबंधित योजनाओं को शामिल कर वचन पत्र में किए गए वादों को पूरा करने पर फोकस किया जाए। लेकिन अफसरों के सामने चुनौती यह है कि वह आर्थिक बदहाली के इस दौर में काम कैसे करें। प्रदेश में करीबन 15 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता और राहत राशि पांच प्रतिशत बढ़ाने का फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। वहीं, धनराशि नहीं होने से विभागों के बजट में बड़ी कटौती भी करनी पड़ी है। इस मामले पर मिली सूचना के अनुसार केंद्रीय करों में 14 हजार 233 करोड़ रुपए की कटौती होने के पश्चात सरकार का वित्तीय प्रबंधन गड़बड़ा चुका है।

बता दें सरकार द्वारा पहले भी सालभर में 20 हजार 600 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। सरकार ने कई खर्चों पर वित्त विभाग ने रोक लगा दी है। जिस कारण से प्रगतिरत काम में वित्तीय संकट के **कारण रुकावट** आ सकती है। इस तरह की रुकावट न हो, इसलिए यह कर्ज लेने का फैसला लिया गया है। यह कर्ज भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बाजार से दस साल के लिए लिया जा रहा है। वित्त विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में तय सीमा के दायरे में रहते हुए कर्ज किया जा रहा है। यह राज्य सकल घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 3.5 फीसदी तक कर्ज लिया जा सकता है। वित्त विभाग के अनुसार बेहतर वित्तीय प्रबंधन के चलते मप्र को राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के 3.5 प्रतिशत तक कर्ज लेने का अधिकार है। इस हिसाब से मध्य प्रदेश राज्य 28 हजार करोड़ रुपए तक का कर्ज ले सकता है। अधिकारियों का कहना है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में तय सीमा के दायरे में रहते हुए कर्ज ले रहे हैं। यदि जरूरत पड़ी तो और कर्ज भी लिया जा सकता है।

सूत्रों के मुताबिक किसानों की कर्जमाफी और विकास कार्यों के लिए सरकार को बड़ी राशि की जरूरत है। गत दिनों वित्त विभाग द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों के बारे में भी सीएम को अवगत कराया गया। कमेटियों की रिपोर्ट में कहा गया है कि अलग-अलग विभागों की एक जैसी योजनाओं का मर्जर किया जा सकता है। इन सभी योजनाओं को एक अंब्रेला स्कीम के नाम पर संचालित किया जा सकता है। इसके साथ ही जो योजनाएं अनुपयोगी हो गई हैं, उन्हें बंद करने के लिए कहा गया है। साथ ही यह सुझाव भी सामने आए हैं कि जो **स्कीम नॉमिनल** बजट वाली हैं और उनमें हर साल मामूली प्रावधान कर उन्हें संचालित किया जा रहा है, उन्हें या तो बंद कर दिया जाए या फिर उनकी री स्ट्रक्चरिंग कर मौजूदा परिस्थितियों के हिसाब से उपयोगी बनाया जाए। गौरतलब है कि जीएडी द्वारा ऊर्जा, अधोसंरचना, कृषि और सहयोगी क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा और स्वास्थ्य, अतिरिक्त राजस्व उपार्जन के उपाय के लिए पांच अपर मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रिपोर्ट मांगी गई थी। एसीएस एम गोपाल रेड्डी, मनोज श्रीवास्तव, इकबाल सिंह बैंस, केके सिंह और अनुराग जैन की अध्यक्षता वाली अलग-अलग कमेटियों ने वित्त विभाग को रिपोर्ट सौंप दी थी।

अभी जो स्थिति है, उसमें विभाग के हिसाब से हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए स्कीम तैयार की गई है। ऐसे में हितग्राही वर्ग एक होने के बाद भी विभाग अलग-अलग हैं। ऐसे में अब सरकार इस कोशिश में लगी हुई है कि एक जैसी योजनाओं को मर्ज किया जाए, ताकि आर्थिक चुनौती का सामना किया जा सके।

● **बृजेश साहू**

37 हजार करोड़ के विकास कार्य अटके

गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही प्रदेश सरकार कई योजनाओं को शुरू करने के लिए कर्ज का इंतजार कर रही है। इन योजनाओं के लिए कर्ज पाने के लिए सरकार द्वारा कई संस्थाओं से बातचीत की जा रही है। यह कर्ज बिजली के क्षेत्र में डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम सुधार, राशन दुकानों को इंटीग्रेडेट बनाने, युवाओं के रोजगार के अवसर बढ़ाने, मल्टी वेलेज ग्रामीण वॉटर सप्लाई करने, विभिन्न शहरों में आरओबी का निर्माण सहित सड़कों का जाल बिछाने के अलावा पर्यटन के क्षेत्र में नए-नए कार्य विकसित करने के लिए तैयारी की जा रही है। इन पर करीब 37 हजार करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। यह कर्ज वर्ल्ड बैंक, केएफडब्ल्यू बैंक, जापान फंड तथा एडीबी सहित एनडीबी से लेने की तैयारी की जा रही है। इनमें से कई प्रोजेक्ट शिवराज सरकार के समय से लंबित हैं। अब इनमें से कुछ पर कमलनाथ सरकार ने भी काम करना शुरू कर दिया है। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए ऊर्जा विभाग 1400 करोड़ की लागत वाला प्रोजेक्ट बनाया है। इसके तहत स्मार्ट मीटर लगाने डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम ठीक करने, चिन्हित शहर में इंवेस्टमेंट बढ़ाने के प्रोजेक्ट पर काम प्रारंभ किया है, परंतु इसमें फंड का अभाव रोड़ा बना हुआ है। इसके लिए सरकार एफडब्ल्यू बैंक से लोन लेने के प्रयास में लगी है। इसी तरह से टारगेट व्यक्तियों को राशन सप्लाई की सिस्टम को सुधारने के लिए 96 करोड़ की राशि खर्च की जानी है। ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर सप्लाई के लिए 3 हजार करोड़ की राशि का प्रोजेक्ट जून 2013 से लंबित है। इसके लिए जाइका से कर्ज की बात हो रही है। इसके अलावा मल्टी वेलेज ग्रामीण वाटर सप्लाई फेस-टू का प्रोजेक्ट 4500 करोड़ का लंबित है। साथ ही मल्टी वेलेज ग्रामीण वाटर सप्लाई फेस-थ्री के लिए एक हजार करोड़ की राशि खर्च होनी है और इसके लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से लोन लेने की बात हुई है, मगर सरकार के प्रयास सफल नहीं हुए।

10 योजनाएं समाप्त

मप्र सरकार ने आखिरकार लैंड पूलिंग एक्ट प्रदेश में लागू कर ही दिया। जिसमें नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अधिनियम 2019 की लगभग 12 धाराओं में संशोधन किया है। इसमें धारा 2 से लेकर धारा 87 में किए गए संशोधन के चलते इंदौर विकास प्राधिकरण की 10 योजनाएं समाप्त हो गई हैं। इन योजनाओं में शामिल लगभग 5 हजार एकड़ निजी जमीनें भी मुक्त हो गईं, लेकिन एक्ट में प्राधिकरण को 6 माह का समय दिया गया है। इस एक्ट के चलते प्राधिकरण की योजना 134-ए, 134-बी, 165, 170, 171, 172, 174, 175, 176 और 177 समाप्त हो गई हैं। नए लैंड पूलिंग एक्ट में योजनाएं लाने पर 50 प्रतिशत जमीन किसानों या उनके मालिकों को लौटाना होगी और 20 प्रतिशत जमीन पर प्राधिकरण भूखंड विकसित कर बेचेगा।

नया भूमि अधिग्रहण कानून लागू होने के बाद से प्राधिकरण इन तमाम योजनाओं में एक एकड़ भी जमीन हासिल नहीं कर पा रहा था। अलबत्ता कुछ योजनाओं में उसने जमीन मालिकों के साथ अनुबंध अवश्य किए, जिसमें नकद मुआवजे के बदले अधिकतम 33 प्रतिशत तक विकसित भूखंड दिए जाना हैं। पिछले दिनों कमलनाथ सरकार ने अहमदाबाद की तर्ज पर लैंड पूलिंग एक्ट घोषित करवाया, क्योंकि सालों तक जमीनें न तो प्राधिकरण-हाउसिंग बोर्ड जैसी संस्थाओं के काम आ रही थीं और न ही किसान या जमीन मालिक उनका कोई उपयोग कर पा रहे थे। हजारों एकड़ जमीनें इंदौर सहित प्रदेशभर में सालों से अनुपयोगी ही पड़ी हैं। प्राधिकरण के पास करोड़-अरबों रुपए की राशि भी नहीं है कि वह जमीन मालिकों को दो से चार गुना तक नए एक्ट के मुताबिक मुआवजा बांट सकें। वहीं अधिकांश **जमीन मालिकों** ने भी अनुबंध करने के बजाय प्राधिकरण से नकद मुआवजे की मांग शुरू कर दी।

लैंड पूलिंग के दायरे में आने वाली प्राधिकरण की 10 योजनाएं समाप्त हो गई हैं, पर 6 माह तक इनमें शामिल निजी जमीनों पर कोई अभिन्यास मंजूर नहीं होंगे। अगली बोर्ड बैठक में नोटिफिकेशन के आधार पर जिन योजनाओं में 10 प्रतिशत भी विकास कार्य नहीं हो पाए हैं, उन्हें लैंड पूलिंग एक्ट के तहत मुक्त किया जाएगा। प्राधिकरण इन योजनाओं को नए सिरे से भी घोषित करने पर विचार करेगा। इनमें कई योजनाएं शहरहित के लिए भी जरूरी हैं, क्योंकि मास्टर प्लान से लेकर मेजर सड़कों का निर्माण इनको अमल में लाने पर ही हो सकेगा। प्राधिकरण के मुताबिक लैंड पूलिंग एक्ट के कारण उसकी 10 योजनाएं समाप्त हो गई हैं, जिनमें योजना 134-ए, 134-बी, राऊ की योजना 165, 170 और बॉम्बे हॉस्पिटल के सामने ग्राम खजराना स्थित बहुचर्चित योजना 171, जिसमें एक दर्जन से ज्यादा गृह निर्माण संस्थाएं हैं, जिन पर भू-माफियाओं ने कब्जे जमा रखे हैं, उनके अलावा योजना 172, 174, 175, 176 व 177 प्रभावित हो रही हैं।

प्राधिकरण रिकॉर्ड के मुताबिक इन 10 योजनाओं में निजी और सरकारी जमीनें शामिल हैं। सबसे ज्यादा निजी जमीनें बायपास की योजना 175 में शामिल हैं, जिसमें करीब 1200 एकड़ से ज्यादा निजी जमीनें हैं। इसके पश्चात योजना 177, जो कि भौंरासला और अन्य जमीनों पर घोषित की गई हैं, में एमआर-12 का निर्माण किया जाना है। इस योजना में 270 हेक्टेयर, यानी 800 एकड़ से ज्यादा जमीन शामिल हैं। इसी तरह योजना 176, जो सुपर कॉरिडोर पालाखेड़ी में मौजूद है, उसमें भी 500 एकड़ से ज्यादा निजी जमीनें शामिल हैं। ट्रांसपोर्ट हब की योजना 174, जो कि लसूड़िया मोरी व अन्य जमीनों पर घोषित की गई, उसमें 300 एकड़ से ज्यादा निजी जमीनें शामिल हैं। इसी तरह योजना 172 में लगभग 100 एकड़ तो अन्य योजनाओं में भी निजी जमीनें शामिल हैं। इन सभी 10 प्रभावित हो रही योजनाओं में लगभग 5 हजार एकड़ निजी जमीनें शामिल हैं, जो अब मुक्त हो गई हैं। इसके अलावा 400-500 एकड़ सरकारी जमीनें भी इन योजनाओं में शामिल हैं। एक्ट लागू होने के बाद 6 महीने तक निजी जमीन मालिक अभिन्यास मंजूर नहीं करा पाएंगे।

● **विशाल गर्ग**

जादूगरों ने अटकाया था लैंड पूलिंग एक्ट

लैंड पूलिंग एक्ट का गजट नोटिफिकेशन इसलिए विलंब से जारी हुआ, क्योंकि कुछ इंदौरी जमीनी जादूगरों ने इसे भोपाल में विभागीय मंत्री के माध्यम से अटकवा दिया था। दरअसल ये जादूगर चाहते थे कि योजना 175 में अदालती आदेश के चलते उनकी जमीनें छूट जाएं, ताकि वे अभिन्यास मंजूर करवा सकें। अगर एक्ट लागू हो गया तो 6 माह तक अभिन्यास मंजूर हो सकेंगे और उसी बीच प्राधिकरण नए सिरे से योजना लागू कर देगा। कुछ जमीन मालिकों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर कर रखी हैं, जिसमें कोर्ट ने प्राधिकरण को दिशा-निर्देश भी दिए हैं और उस पर अमल न होने पर अवमानना याचिकाएं भी दायर कर रखी हैं। जल्द ही इन पर फैसला आने वाला है, लेकिन अब इन जादूगरों के मंसूबे पूरे नहीं हो सकेंगे।

योजना 171 की जमीनें सबसे बेशकीमती

लैंड पूलिंग एक्ट के दायरे में खजराना की चर्चित योजना 171 'जो कि पूर्व में 132 के नाम से मशहूर रही' भी आ गई है। एक्ट लागू होने के चलते यह योजना भी छूट गई है, लेकिन प्राधिकरण का कहना है कि गृह निर्माण संस्थाओं की सभी जमीनों की जांच राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर करवाई जाएगी, ताकि यह पता लग सके कि यह जमीन किन-किनको बिकी है। वैसे भी 6 महीने तक तो अभिन्यास भी मंजूर नहीं होंगे। योजना 171 की जमीन अत्यंत बेशकीमती है और मौके पर अधिकांश जमीनें खाली भी पड़ी हैं। एक दर्जन से ज्यादा गृह निर्माण संस्थाओं की जमीनें इस योजना में शामिल हैं।

54 गांवों में डर का साया

40 साल पहले मध्य प्रदेश के चुटका सहित 54 गांव बरगी बांध के कारण विस्थापित हुए थे। अब इन गांवों पर चुटका परमाणु विद्युत परियोजना से विस्थापित होने की तलवार लटक रही है। आखिर कितनी बार कोई आदिवासी अपने घर-द्वार-जल-जंगल और जमीन छोड़ेगा? अनिल अश्विनी शर्मा ने चुटका सहित कुल 11 गांवों में जाकर आदिवासियों के उजड़ने और फिर बसने की पीड़ा जानने की कोशिश की। उनके चेहरों पर उजड़ने का डर नहीं अब गुस्सा है। यह गुस्सा चिंगारी बनकर कभी भी भड़क सकता है।

मध्य प्रदेश के मंडला जिले के चुटका सहित 54 गांवों को इस परमाणु बिजली घर के बारे में लगभग 25 साल बाद पता चला। चुटका गांव में अक्टूबर, 1984 में परमाणु ऊर्जा आयोग का विशेष दल स्थल निरीक्षण के लिए आया था। इस संबंध में चुटका गांव निवासी नवरतन दुबे बताते हैं कि इसके बाद फिर 1985-86 में एक दल आया और उसने 4 से 500 फीट ड्रिलिंग की। इसके बाद मिट्टी निकालकर उसे लैब भेजा। उस समय हमसे कहा गया कि चूंकि हम बरगी **बांध से विस्थापित** हैं इसलिए सरकार यहां एक फैक्ट्री स्थापित करने जा रही है। लेकिन हमें इस परमाणु बिजली घर की जानकारी 14 अक्टूबर, 2009 को तब हुई जब जबलपुर के स्थानीय अखबारों में इस आशय की खबर छपी कि चुटका में परमाणु बिजली घर बनेगा और इससे 54 गांव विस्थापित होंगे। तब इसके विरोध में आदिवासी ग्रामीणों ने पहली बार 20 अक्टूबर, 2009 को एक बैठक कर चुटका परमाणु विरोधी संघर्ष समिति का गठन किया। समिति ने 22 अक्टूबर, 2009 को मंडला जिले के तत्कालीन कलेक्टर एके खरे को एक ज्ञापन सौंपकर विरोध जताया।

पिछले एक दशक से आदिवासियों ने लगातार संघर्ष कर चुटका गांव में प्रस्तावित परमाणु बिजली संयंत्र का निर्माण नहीं होने दिया है। ग्रामीणों ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपना गांव नहीं छोड़ने वाले। ध्यान रहे कि इस परियोजना से 1.25 लाख लोग विस्थापित होंगे। इस परियोजना को केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर, 2009 में मंजूरी प्रदान की गई। इसमें बताया गया कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआईएल) द्वारा इस परमाणु बिजली घर का निर्माण किया जाएगा। जमीन, पानी और बिजली आदि के लिए मध्य प्रदेश पावर जेनरेटिंग कंपनी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह भी कहा गया कि 700 मेगावाट की दो यूनिट से 1400 मेगावाट बिजली बनाने के बाद जल्द ही इनका विस्तार कर 2800 मेगावाट बिजली बनाने का प्रस्ताव है। इस योजना की प्रारंभिक लागत 16,500 करोड़ रुपए आंकी गई है।

चुटका, टाटीघाट, कुंडा और मानेगांव की लगभग 497 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना प्रस्तावित है। इसमें 288 हेक्टेयर जमीन निजी खातेदारों की और 209 हेक्टेयर जमीन राज्य सरकार के वन विभाग और नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण की है। जबकि संयंत्र को स्थापित करने के लिए कुल 6663.22 हेक्टेयर वन भूमि और वन क्षेत्र वाली 76699.56 हेक्टेयर सरकारी भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। ध्यान रहे कि इन गांवों में 85 फीसदी गोंड जनजाति के आदिवासी रहते हैं।

चुटका परमाणु बिजली घर की प्रस्तावित जमीन पर खड़े कुंडापे दूर तक फैले बरगी बांध के जल संग्रहण क्षेत्र की ओर अंगुली दिखाते हुए कहते हैं कि हर किसी के लिए पानी जीवन होता है लेकिन हमारे लिए तो यह पानी पिछले 40 साल से मरणशैय्या बना हुआ है। पहले पानी के पास होने के कारण हटाए गए और अब पानी गांव के तीन ओर है, इसलिए हटाए जा रहे हैं। वह बताते हैं कि हमारा यह गांव नर्मदा नदी के किनारे ही बसा था। हमारे गांव के सामने से नदी का बहाव क्षेत्र था। 1975 में पहली बार जब हमने अपने बुजुर्गों से सुना कि अब डूब जाएंगे तो हमारे मन में यह सवाल कौंधा कि अभी तो नर्मदा में बाढ़ भी नहीं आ रही है ऐसे में हम कैसे डूब जाएंगे। तब हमारे पिताजी ने बताया कि यहां एक बड़ा बांध बनने वाला है और उसके डूब क्षेत्र में हमारा यह गांव भी आता है। कुंडा गांव के निवासी बाबूलाल बताते हैं कि तब हमें लालच दिया गया था कि हमें **मुफ्त बिजली, परिवार** के एक सदस्य को नौकरी, घर और खेतों का मुआवजा मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। हर परिवार को 1300 रुपए मात्र दिए गए। वह अपने पहले विस्थापन को याद करते हुए कहते हैं कि 1980 में जब बरगी बांध बनना शुरू हुआ तो हम आदिवासियों को ढोर-गंवारों की तरह सरकार ने हांक दिया और हाथ पर रख दिए कुछ सौ के नौट। तब हम जैसे-तैसे इस ऊंचे पहाड़ी टीले पर आ बसे कि यहां तक तो पानी आएगा ही नहीं। हमें क्या मालूम था कि यहां जंगल में बसना भी हमारे लिए मुसीबत बनकर आएगा। वह बताते हैं कि अब हमारे गांव के तीनों ओर लबालब भरे इस बरगी बांध के पानी पर सरकारी लार पिछली 11 सालों से टपक रही है।

● **नवीन रघुवंशी**

ग्राम सभा की इजाजत तक नहीं ली गई

सरकार ग्राम सभा की अहमियत को समझ नहीं रही है कि यह कितनी महत्वपूर्ण होती है। इस संबंध में बरगी गांव के शारदा यादव ने बताया कि राज्य सरकार को यह समझने की जरूरत है कि वह ग्रामसभा की इजाजत के बिना संयंत्र लगाने की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ा सकती। पंचायती राज अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम (पेसा) और आदिवासी व अन्य वनवासी भूमि अधिकार अधिनियम, वनाधिकार कानून को आधार बनाकर ही सर्वोच्च न्यायालय ने ओडिशा की नियमगिरी पहाड़ियों से बाक्साइट के खनन पर रोक लगाई थी। ओडिशा सरकार ने नियमों की अनदेखी करते हुए वेदांता समूह को बॉक्साइट उत्खनन की मंजूरी दे दी थी। इस परमाणु संयंत्र के परिपेक्ष्य में मध्य प्रदेश सरकार को इस फैसले के मद्देनजर ही भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई को आगे बढ़ाने की जरूरत है, अन्यथा उसे मुंह की खानी पड़ सकती है।

राशन की कालाबाजारी पर लगाम

गरीबी हटा देने का दावा करने वाली पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में एक समय ऐसा भी आया था कि प्रदेश में 5 करोड़ 55 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वालों की सूची में शामिल हो गए थे। लेकिन राशन दुकानों पर गरीबों को सस्ती दरों पर मिलने वाले गेहूं-चावल के वितरण को पीओएस सिस्टम (अंगूठा लगाकर राशन वितरण) से जोड़ने के बाद फर्जी गरीब सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) की दुकानों से दूर हो गए। इसका असर यह हुआ कि पिछले छह महीने में अकेले मप्र की पीडीएस दुकानों पर 11 करोड़ 66 लाख किलो अनाज बच गया है। मप्र की राशन की दुकानें राशन लेने आने वाले रहवासियों के लिए परेशानी का सबब बन गई थीं। कालाबाजारी गरीबों को मिलने वाला निवाला भी छीन रही थी। पर अब इन राशन की दुकानों की सूरत बदल चुकी है। सरकार ने राशन की दुकानों के लिए पीओएस (पाइंट ऑफ सेल) सिस्टम लागू किया है। इसके तहत सितंबर में 2019 में पूरे प्रदेश में पीडीएस दुकानों को फिंगर प्रिंट व्यवस्था से जोड़ दिया गया। इससे कालाबाजारी रुक गई है। इससे 8 करोड़ 73 लाख किलो गेहूं और 2 करोड़ 93 लाख किलो चावल बच गया है।

वहीं प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के राशन कार्डों का सर्वे किया गया तो 1.39 करोड़ राशन कार्ड कम करने पड़े। इनमें से कुछ राशन कार्डधारी स्थानांतरित हो गए तो कुछ फर्जी भी हो सकते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके राशन कार्ड तो हैं लेकिन वे राशन लेने नहीं जाते। प्रदेश में कुल 6.68 करोड़ राशन कार्ड थे जिनमें से अब 5.29 करोड़ ही रह गए हैं। खाद्य आपूर्ति मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर कहते हैं कि हम राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने को प्रयासरत हैं। हमारा उद्देश्य असल गरीबों को लाभ देने का है। बीपीएल सर्वे पूरा होने के बाद इसमें और सुधार आएगा।

अब प्रदेश में हर महीने न केवल 16 लाख अतिरिक्त गरीब परिवारों को पर्याप्त राशन बांटा जा रहा है, बल्कि हर महीने केंद्र से मिलने वाले कोटे में से औसतन ढाई से तीन हजार मीट्रिक टन अनाज की बचत भी हो रही है। यह स्थिति तब है, जब केवल शहरी क्षेत्रों में ही पीडीएस सिस्टम में बायोमीट्रिक पहचान अनिवार्य की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी इस सिस्टम के लागू होने के बाद बचत का यह अनुपात दोगुना हो सकता है। एक साल में 18 लाख 85 हजार 145 कथित पीडीएस परिवारों ने अब तक अपना आधार लिंक नहीं कराया है, ये लोग पीडीएस दुकानों पर राशन लेने भी नहीं आ रहे हैं। आशंका इसी बात की है कि इतनी बड़ी संख्या में गरीबी रेखा के फर्जी राशनकार्डों के जरिए पीडीएस के अनाज की कालाबाजारी की जा रही थी। हालांकि इन राशनकार्डों को अभी निरस्त करने के बजाय इनका राशन का कोटा रोका गया है। ताकि कोई व्यक्ति गलती से छूट गया है, तो वह अपना आधार लिंक कराकर फिर से राशन ले सकता है। पीडीएस के लिए हर महीने प्रदेश को 2.89 लाख मीट्रिक टन अनाज का कोटा आवंटित होता है। इसमें प्रदेश की 5 करोड़ 34 लाख आबादी कवर होती है। जबकि प्रदेश में पीडीएस पात्रता वाली गरीब आबादी की संख्या 5 करोड़ 50 लाख (1 करोड़ 18 लाख 21 हजार 99 परिवार) है। इनमें लगभग 1 करोड़ 2 लाख प्राथमिकता परिवार (बीपीएल) हैं, जबकि 16 लाख परिवार अंत्योदय सूची में आते हैं।

मप्र सरकार एक और क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है। सरकार अब राशन की होम डिलीवरी करने जा रही है। खाद्य मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया कि ऐसे बुजुर्ग जिनकी उम्र 80 वर्ष से अधिक है उनके हिस्से का राशन उन्हें घर पर पहुंचाया जाएगा। उन्हें राशन की दुकान पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं है। मंत्री तोमर ने यह नहीं बताया कि यह योजना कितनी तारीख से शुरू होगी। खाद्य मंत्री ने कहा कि अब बाकी सामानों की तरह ही केवल बुजुर्गों के लिए राहत देने के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। अब बुजुर्गों के लिए सरकारी अनाज की होम डिलीवरी की जाएगी, लेकिन इसके लिए 80 साल की उम्र होना जरूरी है। इसके लिए खाद्य विभाग अब राशन कार्ड के जरिए ऐसे बजुर्गों को चिन्हित कर रहा है, जो कि काफी उम्रदराज हैं और उनके घर में कोई वयस्क नहीं है। अब बुजुर्गों के लिए अनाज पहुंचाना सरकार और खाद्य विभाग की जिम्मेदारी होगी। तोमर का कहना है कि प्रदेशभर में राशन दुकानों पर खाद्य की कालाबाजारी रोकने के लिए सेल्समैन तैनात किए जा रहे हैं। जबकि हर राशन दुकान पर एक सेल्समैन तैनात होगा। इसके अलावा वेयरहाउस की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। प्रदेश में आधे से ज्यादा वेयरहाउस में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं और बाकी को लेकर काम काफी तेजी से चल रहा है।

● **विकास दुबे**

11 जिलों में बंट सकता है बचा अनाज

पीओएस सिस्टम लागू होने के बाद प्रदेश में पिछले छह माह में जितना अनाज बचा है वह 11 जिलों में आवंटित किए जा रहे अनाज के बराबर है। जानकारी के अनुसार सितंबर में 52 जिलों को 22 करोड़ 28 लाख 72 हजार 105 किलो गेहूं आवंटित हुआ। इन्हीं जिलों को फरवरी में 13 करोड़ 55 लाख 52 हजार 763 किलो गेहूं दिया गया है। यानी प्रदेशभर में 8 करोड़ 73 लाख 19 हजार 342 किलो गेहूं बच गया है। बचे हुए गेहूं की मात्रा इतनी है कि चंबल-ग्वालियर संभाग के सातों जिले श्योपुर, ग्वालियर, मुरैना, भिण्ड, दतिया, शिवपुरी, गुना के 11.44 लाख गरीबों (जिन्हें हर माह 1.35 करोड़ किलो गेहूं बंटता है) को छह माह तक बंट सकता है। इसी प्रकार बचा अनाज चार महानगरों भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर और इंदौर के 12 लाख 13 हजार गरीब परिवारों (जिन्हें हर माह 1.52 करोड़ किलो गेहूं बंटता है) को साढ़े पांच माह तक दिया जा सकता है। मांग में कमी को देखते हुए शासन ने भी दुकानों का राशन आवंटन कम कर दिया है।

विकास में भेदभाव

वक्त है बदलाव का... के नारे के साथ सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रदेश में किसानों की कर्जमाफी सहित विकास की दिशा में कई सार्थक कदम उठाए। मुख्यमंत्री कमलनाथ और उनकी सरकार की लगातार कोशिश रही है कि वे अपने वचन पत्र में किए गए हर वादे को पूरा करें। करीब एक साल के कार्यकाल के दौरान सरकार ने वचन पत्र के 365 से अधिक वादे पूरे कर दिए हैं। लेकिन इस दौरान केंद्र सरकार ने उनकी राह में कई रोड़े खड़े किए हैं। केंद्र सरकार ने मप्र के हिस्से की करीब 31,140 करोड़ की राशि रोक रखी है। इस कारण किसानों की कर्जमाफी, बोनस और विकास कार्यों में बाधा खड़ी हो गई है। गौरतलब है कि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेश पहले से ही कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है। ऐसे में केंद्र सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैए, केंद्रीय करों में कटौती और केंद्र से मिलने वाले फंड को रोके जाने से मप्र सरकार के सामने **चुनौतियों** का पहाड़ खड़ा हो गया है। मप्र में जब से सत्ता परिवर्तन हुआ है तब से ही केंद्र सरकार मप्र से भेदभाव कर रही है। आर्थिक तंगी से जूझ रही प्रदेश की कांग्रेस सरकार को केंद्र की मोदी सरकार ने सबसे बड़ा झटका विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्र से मिलने वाली राशि को रोककर दिया है। वित्त विभाग के सूत्रों से मिले आंकड़ों के मुताबिक, केंद्रीय योजनाओं के तहत मिलने वाले राज्य के 31,139.81 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने नहीं दिए हैं। 12 से अधिक योजनाओं का पैसा केंद्र सरकार ने अटका दिया है।

प्रदेश के हिस्से की लंबित राशि को जारी करने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री लगातार केंद्र सरकार के मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हर केंद्रीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही राशि जारी कर दी जाएगी। लेकिन एक साल से अधिक का अरसा बीत जाने के बाद भी राशि जारी नहीं की जा रही है। सत्ता परिवर्तन के बाद से ही केंद्र की भाजपा सरकार मप्र से भेदभाव कर रही है। आलम यह है कि केंद्र अपनी ही योजनाओं को अमलीजामा पहनाने के लिए मप्र को फंड नहीं दे रहा है। इस कारण कई योजनाएं पिछड़ रही हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना। केंद्र सरकार की **भेदभावपूर्ण नीति के** कारण प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ बेघर परिवारों को नहीं मिल पा रहा है। मप्र में ही गरीबों को पक्के मकान मुहैया कराने के लिए संचालित इस योजना से करीब 2.90 लाख लोग वंचित है। उप्र, महाराष्ट्र व गुजरात जैसे पड़ोसी राज्यों के मुकाबले यह संख्या बहुत अधिक है। इसके बाद योजना संचालन के लिए तय लक्ष्य 2022 तक इसका फायदा जरूरतमंदों को मिल जाएगा, इस पर संशय जताया जाने लगा है।

मंत्रालयीन सूत्रों के अनुसार, हितग्राही चयन में देरी के साथ निर्माण प्रक्रिया की धीमी गति इसके पीछे जहां मुख्य वजह बताई जाती है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच खींचतान भी एक बड़ा कारण माना जा रहा है। बताया जाता है कि मध्यप्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद योजना मद में केंद्र से मिलने वाली राशि जहां देरी से आई है, वहीं उनमें कटौती भी हुई है।

गरीबों के लिए आवास निर्माण को लेकर राज्य सरकार की संजदगी लोकसभा में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के एक जबाव से सामने आई। 6 फरवरी 2020 तक के आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया कि, प्रधानमंत्री आवास योजना फेस-2 में केंद्र ने मध्यप्रदेश को 8 लाख 32 हजार 100 घरों का लक्ष्य दिया था। राज्य सरकार ने 2 लाख 30 हजार घर पहले ही बनाने में असमर्थता जता दी। इसके बाद जो लक्ष्य खुद तय किया उसमें भी राज्य सरकार ने सिर्फ 3 लाख 72 हजार 700 घरों की मंजूरी ही केंद्र को भेजी है। इसमें भी अब तक सिर्फ 1 लाख 48 हजार 15 आवास ही पूरे हो पाए हैं। राज्य सरकार ने योजना के द्वितीय चरण में ही 2 लाख 24 हजार 702 मकान नहीं बनाए हैं। जबकि इसके पहले साल 19-20 के पहले 2016 से 2019 के बीच स्वीकृत 14 लाख 2 हजार 823 मकान के विपरीत वह 65 हजार 835 आवासों का निर्माण नहीं करा पाई है।

● **श्याम सिंह सिकरवार**

हजारों योजनाएं बंद करने की तैयारी

मप्र सरकार को केंद्रीय बजट में मिले झटके के बाद प्रदेश सरकार हजारों योजनाएं बंद करने की तैयारी कर रही है। इसके बाद सरकार नए सिरे से तय करेगी कि इनमें से कौन-सी योजनाएं बंद करना है और कौन-सी चालू रखना है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने इनमें से बड़ी संख्या में अनुपयोगी योजनाओं को बंद करने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार ऐसी योजनाएं जिनके संचालन में केंद्र और राज्य सरकार के फंडिंग का रेशो क्रमशः 60 :40 प्रतिशत है उनमें से अनुपयोगी हो चुकी योजनाओं को बंद किया जा सकता है।

इन योजनाओं का पैसा अटका

योजना	रुकी राशि (करोड़ में)
मनरेगा	1,900
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	2,209
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)	2,332.40
अमृत योजना	208
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	446.81
फूड सब्सिडी	700
फसल बीमा योजना	2,800
जीएसटी मुआवजा	1,502
ऊर्जा प्रणाली की मजबूती के लिए	1,400
सौभाग्य योजना	70
राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम	571.60
केंद्रीय करों के हिस्से की राशि	17,000

शेरों का संरक्षण जरूरी

भारत में लुप्तप्राय शेरों का संरक्षण जरूरी है। यह बात कई शोध में सामने आ चुकी है। इसके लिए गुजरात के गिर के बब्बर शेरों को मप्र के श्योपुर जिले के कूनो पालपुर अभयारण्य में बसाने की कवायद वर्षों से चल रही है। वहीं शेरों की निगरानी और संरक्षण के लिए वन्यजीवों के जानकार केशव गोगोई और भारतीय वन्यजीव संस्थान के सहयोगियों ने अपने निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं। गुजरात के गिर जंगलों में केवल 50 की संख्या में बचे हुए एशियाई शेरों को संरक्षण के द्वारा बचाया गया था, जिनकी आज अनुमानित संख्या 500 तक पहुंच गई है। हालांकि, मौजूदा निगरानी के तरीके, विशेष रूप से एक तकनीक जिसे (टोटल काउंट्स) कुल गिनती के रूप में जाना जाता है। इस तकनीक में गिनने के दौरान कुछ शेर छूट सकते हैं या उनकी दोबारा गिनती हो सकती है। यह तरीका शेरों के स्थानीय आबादी के घनत्व पर बहुत सीमित जानकारी देता है।

नए अध्ययन में, गोगोई और उनके सहकर्मियों ने एशियाई शेरों की निगरानी के लिए एक वैकल्पिक तरीके का प्रयोग किया है। उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके अलग-अलग शेरों की पहचान करने के लिए **मूंछ पैटर्न** और शरीर के स्थायी निशानों को पहचान के तौर पर इस्तेमाल किया है। शेरों के आबादी के घनत्व का अनुमान लगाने के लिए एक गणितीय मॉडलिंग विधि के साथ डेटा का विश्लेषण किया जाता है। जिसे स्थानीय तौर पर स्पष्ट रूप से कैप्चर रिकैप्चर के रूप में जाना जाता है। उन्होंने शेरों द्वारा किए जाने वाले शिकार की आबादी का घनत्व और अन्य कारकों का भी आकलन किया जो शेर के आबादी के घनत्व की विस्तृत जानकारी दे सकते हैं।

शोधकर्ताओं ने गिर के जंगल में 725 वर्ग किलोमीटर में एक अध्ययन किया, जिसके अंदर 368 शेर देखे गए। इनमें से 67 अलग-अलग शेरों की पहचान की गई, जिसमें प्रति 100 वर्ग किलोमीटर में 8.53 शेरों की आबादी के घनत्व का अनुमान लगाया गया। ऊबड़-खाबड़ या ऊंचे क्षेत्रों के विपरीत समतल घाटी में शेरों की आबादी का घनत्व अधिक पाया गया था और निकटवर्ती स्थलों पर जहां पर्यटक शेरों को देखना चाहते है वहां शेरों को आकर्षित करने के लिए भोजन रखा गया था। इसके अलावा शोधकर्ताओं ने अपने निष्कर्ष में कहा कि पर्यटन के लिए शेरों को लालच देने से उनके प्राकृतिक आबादी के घनत्व पैटर्न को बहुत नुकसान होता है। अन्य शोध भी यह दर्शाते है कि लालच के रूप में चारा देना शेर के व्यवहार और सामाजिक गतिशीलता (डाइनैमिक्स) को बाधित करता है। शोधकर्ताओं का सुझाव है कि उनकी वैकल्पिक निगरानी पद्धति का उपयोग शेरों को उनकी सीमा का आंकलन करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि मौजूदा संरक्षण प्रयासों को अधिक सटीक रूप से उपयोग किया जा सके।

शोधकर्ताओं के मुताबिक दुनिया में एशियाई शेरों की एकमात्र आबादी सौराष्ट्र में जीवित है। विज्ञान और प्रबंधन का अच्छा उपयोग करके इन उप-प्रजातियों का प्राथमिकता के साथ संरक्षण करना सभी की जिम्मेदारी है। यह शोध इस प्राथमिकता को उनकी संख्या मूल्यांकन और निगरानी के लिए एक मजबूत दृष्टिकोण विकसित कर सकता है, जिसका उपयोग दुनियाभर में शेरों की आबादी का संरक्षण करने के लिए किया जा सकता है।

केंद्र सरकार के सिंह प्रोजेक्ट की शुरुआत वर्ष 1994 में हुई थी, जो आज भी अधूरी है। इस प्रोजेक्ट और शेर लाने के संबंध में प्रदेश सरकार का 27 वर्षों से गुजरात व केंद्र सरकार से पत्राचार चल रहा है। वर्ष 2003 में कूनो पालपुर में शेरों के रहवास के लिए समस्त सुविधाएं जुटा ली गईं, जिसकी जानकारी गुजरात को भी दे दी गई है। सरकार तकनीकी कमेटी की 85 फीसदी शर्तों को पूरा कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी भी कूनो पालपुर में शेरों की शिफ्टिंग पर सहमति दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 छह माह में शेर शिफ्ट करने के निर्देश गुजरात सरकार को दिए थे। इसके बाद भी गुजरात सरकार शेर देने को तैयार नहीं है।

कूनो-पालपुर में गिर के एशियाई शेरों को बसाने के लिए सुप्रीम कोर्ट फैसला 2013 में कर चुका है। जिस पर ट्रांस लोकेशन कमेटी 2016 में विजिट कर चुकी है और शेरों की बसाहट के लिए इसे अनुकूल बता चुकी है। लेकिन यहां गुजरात हमेशा ही टाइगर ट्रेल बताकर शेर देने में आनाकानी कर रहा है और मामले में नए-नए पेंच फंसाकर इसमें लगातार देरी कर रहा है। चूंकि कूनो-पालपुर सेंक्चुरी राजस्थान के सवाई-माधौपुर स्थित रणथम्भौर सेंक्चुरी से नजदीक है और यहां बाघों का विचरण भी होता रहता है। ऐसे में अफ्रीका चीता यहां बसाने में कठिनाई आएगी। क्योंकि चीता उसी जंगल में रुकता है जहां पहले से कोई बड़ा जानवर यानी बाघ या शेर न हो। यदि ऐसा भी है तब भी उसे कम से कम दो साल का समय लगता है। इन दो सालों में वह अपनी व अपने परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही जंगल में रुकता है लेकिन कूनो सेंक्चुरी में टाइगर लगातार आता जाता है। मप्र के ही नोरदेही में चीता बसाने के लिए केंद्र से पूर्व में चिन्हित किया था। कूनो के साथ इस जगह का नाम भी शामिल है। लेकिन वर्तमान में यहां सरकार को भारी मशक्कत करनी पड़ेगी। यहां चीता बसाना आसान नहीं है। नोरदेही में जंगलों के बीच में ही कई अतिक्रमण हैं, इनमें करीब 55 गांव बसे हुए हैं। जिन्हें विस्थापित करना सरकार के लिए आसान नहीं है।

● **धर्मेन्द्र सिंह कथूरिया**

शेरों का कब्रगाह बन गया गिर वन

गुजरात का गिर वन जंगल के राजा शेरों के लिए कब्रगाह बनता जा रहा है। गुजरात सरकार की ओर से विधानसभा में पेश आंकड़े तो यही इशारा कर रहे हैं। गुजरात के वन मंत्री के मुताबिक 2 साल में 222 शेरों की मौत हो चुकी है। वनमंत्री गणपत वसावा ने कहा कि पिछले दो सालों यानी 2017-18 और 2018-2019 में गुजरात में अब तक 222 शेरों की मौत हो चुकी है। वन मंत्री ने कहा कि ज्यादातर शेरों की मौत प्राकृतिक है, हालांकि कई शेर अप्राकृतिक कारणों से भी मरे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दो साल में 52 शेरों, 74 शेरनियों जबकि 90 शावकों की मौत हुई है। शेरों से जुड़े आंकड़ों की जानकारी कांग्रेस के विधायक इमरान खेड़ावाला ने मांगी थी। सरकार द्वारा डाटा दिए जाने के बाद कांग्रेस ने सदन में हंगामा किया और कहा कि वन विभाग शेरों के रख-रखाव में घोर लापरवाही बरत रहा है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार शेरों पर खर्च करने के लिए करोड़ों रुपए की ग्रांट की देती है, बावजूद इसके शेरों की असमय मौत हो रही है।

जांच की आंच

मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र की बदहाली दूर करने के लिए जारी किए गए 7,400 करोड़ के राहत पैकेज घोटाले का जिन्न एक बार फिर बोतल से बाहर आने को बेताब है। मध्यप्रदेश की कमलनाथ सरकार ने इसकी जांच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) से कराने का आदेश जारी किया तो पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान की चिंताएं बढ़ गईं। ऐसा इसलिए क्योंकि बुंदेलखंड पैकेज निगरानी समिति भी पैकेज में हुई गड़बड़ी को लेकर सीधे जांच के निशाने पर आ रही है। इस समिति के अध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ही थे और मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के आदेश पर हुई जांच के बाद भी वह इसमें फंसने वाले प्रशासनिक अधिकारियों को बचाने के लिए फाइल दबाए रखने के आरोपों से भी घिरे रहे हैं। यह पैकेज राहुल गांधी की पहल पर यूपीए सरकार ने बुंदेलखंड के विकास के लिए जारी किया था, लेकिन अनियमितताओं का शिकार हो गया। विधानसभा चुनाव में इस घोटाले को कांग्रेस ने मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया और सरकार बनाने के बाद अब कमलनाथ ने इसकी जांच ईओडब्ल्यू को सौंप दी है।

वर्ष 2009 में तत्कालीन यूपीए सरकार ने मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र के 13 जिलों में विकास कार्यों के लिए 7,266 करोड़ रुपए का विशेष पैकेज जारी किया था। बाद में यह बढ़कर 7,400 करोड़ से अधिक का पैकेज हो गया। इनमें 3,800 करोड़ रुपए मध्यप्रदेश और 3,500 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के लिए दिए गए थे। साल 2012 में ही बुंदेलखंड पैकेज की अनियमितताएं सामने आने लगीं थीं। इस मामले की पहली जांच चीफ टेक्निकल एक्जामिनर विजिलेंस (सीटीईवी) द्वारा की गई। नेशनल रेनफेड एरिया अथॉर्टी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) जेएस सामरा ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिलों में दौरा कर निर्माण कार्यों में अनियमितताएं होने की रिपोर्ट दोनों राज्यों को भेजी थी, लेकिन राज्यों ने इस जांच पर कोई ठोस एक्शन नहीं लिया। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के जिलों में पैकेज के तहत खोदे गए तालाब, कुएं, बकरी पालन से लेकर हर एक मद में घोटाले के आरोप सामने आने के बाद भी राज्य सरकारें इस मामले को लेकर गंभीर नहीं दिखीं।

2014 में टीकमगढ़ के समाजसेवी पवन घुवारा ने इस मामले में आरटीआई से मिली जानकारियों के आधार पर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। इस याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बुंदेलखंड पैकेज में हुए घोटालों की जांच के लिए निर्देश जारी कर दिए। हाईकोर्ट के निर्देश पर गठित जांच टीम ने 2017 में जो रिपोर्ट जारी की उसमें पैकेज की धनराशि में बड़े पैमाने पर घोटाला होने की पुष्टि हो गई। जांच टीम ने साफ तौर पर 350 स्टाप डैम के निर्माण में भारी अनियमितता होने का खुलासा किया। मध्य प्रदेश के छह जिलों में 1250 नलजल योजनाओं में से एक हजार नलजल योजनाएं पूरी तरह से बंद पाई गईं, जबकि पैकेज का पैसा खर्च कर इनको चालू बताया गया था।

पैकेज के सही तरीके से लागू नहीं होने का कारण पलायन

बुंदेलखंड को दिए गए इतने बड़े राहत पैकेज के सही तरीके से खर्च नहीं होने के कारण लाखों की संख्या में स्थानीय लोग रोजगार की तलाश में पलायन होने पर मजबूर हो रहे हैं। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार, 2015-16 में बुंदेलखंड के प्रमुख रेलवे स्टेशनों से लगभग 18 लाख लोग अनारक्षित डिब्बों का टिकट कटाकर राजधानी दिल्ली पहुंचे। पलायन करने वाली आबादी बुंदेलखंड की कुल जनसंख्या का 10 फीसदी है। स्थानीय अधिकारियों के अनुसार, इस क्षेत्र में लगभग 60 से 70 प्रतिशत लोग कृषि पर जीवित रहते हैं। बहुत से लोगों के पास खेती खराब होने के बाद कुछ नहीं बचता है। ऐसे में क्षेत्र से पलायन अब एक दुष्चक्र बन गया है। बुंदेलखंड के पारंपरिक तालाबों की बनावट यहां के प्राकृतिक हालात को देखते हुए की गई थी। ये तालाब इस तरह बनाए गए थे कि एक तालाब के पूरा भरने पर उससे निकला पानी अगले तालाब में अपने आप चला जाता था, यानी बारिश की एक-एक बूंद संरक्षित हो जाती थी। अब यहां के अधिकतर पारंपरिक तालाब सूख गए हैं। 2004 से 2008 तक बुंदेलखंड में भयंकर सूखा पड़ा, जिसे देखते हुए सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज की घोषणा की थी। यह पैकेज काफी बड़ा और कई परतों में है। इसमें 11 विभाग हैं। हर विभाग में कई योजनाएं बनाई गईं। माना गया कि बुंदेलखंड क्षेत्र सूखा प्रभावित इलाका है, इसलिए पैकेज को सूखा से निपटने के लिए डिजाइन किया गया। लेकिन, विडंबना यह है कि पैकेज निर्माण में स्थानीयता व पारंपरिकता का ध्यान नहीं रखा गया। पैकेज में विभाग, मद या योजना के लिए स्थानीय स्तर से किसी से सुझाव नहीं मांगा गया, सीधे केंद्रीय स्तर से योजनाएं बनाई गईं। इसमें कृषि, सिंचाई व बागवानी सहित 11 विभागों की योजनाओं पर फोकस किया गया।

बुंदेलखंड पैकेज के तहत मध्य प्रदेश के सागर में 840 करोड़, छतरपुर में 918 करोड़, दमोह में 619 करोड़, टीकमगढ़ में 503 करोड़, पन्ना में 414 करोड़ और दतिया में 331 करोड़ का काम होना था। इस मामले में आरटीआई लगाकर हाईकोर्ट से **जांच कराने** वाले पवन घुवारा कहते हैं कि जल संसाधन विभाग को 1340 करोड़, पीएचई विभाग के 300 करोड़, ग्रामीण विकास विभाग के 209 करोड़ खर्च, कृषि विभाग के तहत 614 करोड़, वन विभाग को जारी 180 करोड़ के कुल फंड की 80 फीसदी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई।

अनियमितताएं सामने आने के बाद प्रदेश के 200 से अधिक जिम्मेदार अधिकारियों को घोटाले का दोषी माना गया, लेकिन इस रिपोर्ट पर शासन स्तर से सिर्फ अधिकारियों को नोटिस जारी कर कार्रवाई को पूरी तरह से दबा दिया गया। पवन घुवारा की मानें तो सभी दोषी बताए गए **अधिकारियों पर एफआईआर** उसी समय हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसके बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर भी इसके छींटे पड़ना लाजमी थे। मध्य प्रदेश की शिवराज कैबिनेट ने 12 सितंबर 2017 को लिए गए फैसले में बुंदेलखंड पैकेज मे भ्रष्टाचार करने वालों पर (नियम) सेवानिवृत्त के चार साल बाद भी कार्यवाही होने की बात कही, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया।

बुंदेलखंड पैकेज को जमीन पर उतारने वाले पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य कहते हैं कि तत्कालीन केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड पैकेज के क्रियान्वयन में भरपूर मदद की, लेकिन राज्य सरकार ने काफी अनदेखी। योजना को केंद्र भेजता है, लेकिन उसके सही क्रियान्वयन की जिम्मेदारी राज्य की है, जिसमें उसने लापरवाही की। बाद के समय भी किसी भी सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया।

● **सिद्धार्थ पांडे**

दिल्ली का दर्द
घाव बना नासूर

दिलवालों की दिल्ली में पिछले दिनों दहशत का जो खेल खेला गया, वह सुनियोजित षड्यंत्र था। वरना जिस शहर में हमेशा 50 हजार से अधिक पुलिस बल सक्रिय रहता है, वहां हिंसा और आगजनी की वारदात इतना भयानक रूप कैसे ले सकती थी? आरोप तो यह लग रहे हैं कि घाव के नासूर बनने का इंतजार किया जा रहा था। लेकिन यह नासूर 42 जिंदगियां लील जाएगा, इसका किसी को अनुमान ही नहीं था।

● राजेंद्र आगाल

जिस दिल्ली को देश की सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, जहां राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री, तीनों सेनाध्यक्ष, खुफिया एजेंसियों के मुखिया रहते हों, वहां सुनियोजित तरीके से एक ऐसा षड्यंत्र बुना गया, जिसने देश के दिल को तबाह कर दिया, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी। आखिर इसके लिए दोषी कौन है? दिल्ली में जनसंख्या के **अनुपात में पुलिसबलों** की संख्या काफी कम है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि महज 1484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले दिल्ली शहर में 84,000 से ज्यादा पुलिसबल है, जिसमें करीब 50,000 पुलिसबल हमेशा सक्रिय और सेवा में रहता है। क्या इतने बड़े पुलिसबल को भी 5 से 6 कालोनियों में भड़की दंगों को काबू में करना मुश्किल था? वह भी तब जब उत्तर पूर्व दिल्ली की इन **चार-पांच** कालोनियों को छोड़कर पूरी दिल्ली में शांतिपूर्ण माहौल था। देश के दिल में हुआ यह षड्यंत्र सरकार के लिए एक बड़ा सबक है।

राजधानी दिल्ली में हुई हिंसा और आगजनी डरावनी और चिंताजनक है। सुनियोजित साजिश के बिना इतने व्यापक पैमाने पर हिंसा नहीं हो सकती। दिल्ली में स्थिति बिगाड़ने के संकेत तभी मिलने आरंभ हो गए थे जब जाफराबाद में सड़क को घेरकर धरना आरंभ किया गया। इससे साफ हो गया था कि जगह-जगह शाहीन बाग पैदा करने की तैयारी हो रही है। जब एक समूह ने इसके विरोध में मौजपुर में धरना दिया तो उस पर पथराव किया गया और वहीं से स्थिति बिगड़ने लगी। शाहीन बाग की तरह ही यहां भी पुलिस की विफलता स्पष्ट है। पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करेंगे तो यह समझते देर नहीं लगेगी कि धरना के समानांतर हिंसा, आगजनी और दंगों की भी तैयारी की गई थी। आखिर इतनी संख्या में लोग पत्थरबाजी कैसे करने लगे?

आखिर इस कदर हिंसा हुई कैसे?

बीती 23 फरवरी से राजधानी दिल्ली में शुरू हुई हिंसा में इन पंक्तियों के लिखे जाने के समय तक 42 लोगों की मौत हो चुकी थी और 300 से अधिक घायल लोग अस्पतालों में भर्ती हैं। पुलिस ने 167 एफआईआर दर्ज की है और 885 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालात काबू में करने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) अजीत डोभाल को दे दी गई है। मगर मूल सवाल यह है कि दिल्ली में किसी भी संकट से निपटने के लिए मौजूद **तमाम संसाधनों** के बावजूद आखिर इस कदर हिंसा हुई कैसे? क्या इसके लिए सिर्फ कपिल मिश्रा, ताहिर हुसैन जैसे छुटभैय्ये नेता और उनके उकसाऊ भाषण जिम्मेदार हैं या इसके लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक की घोर लापरवाही जिम्मेदार है? या फिर हिंसक उग्रता को जांचने-परखने के लिए दिल्ली को एक मॉडल की तरह इस्तेमाल किए जाने की यह देन है? उत्तर प्रदेश के पूर्व डीआईजी पुलिस तथा चर्चित विचारक विभूति नारायण राय ने बहुत साल पहले एक बात कही थी कि अगर सरकार और पुलिस न चाहे तो दंगे भड़क तो सकते हैं, लेकिन वो फैल नहीं सकते।

दिल्ली में पिछले करीब 3 महीनों से जिस तरह की स्थितियां धीरे-धीरे करके गढ़ी गई हैं, उससे तो लगता है कि यहां सांप्रदायिक तनाव विस्तारित नहीं हुआ बल्कि एक तरह से उसे पूरी मेहनत, मशक्कत के साथ जमीन में बोया गया है, जिसकी अब जहरीली फसल तैयार हो चुकी है। दिल्ली में पिछले तीन दिनों में देखते ही देखते जिस तरह स्थितियां काबू से बाहर हुईं, वह दंगों के फैलने और बढ़ने का एक क्लासिक उदाहरण है। शायद देश के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब थोड़े से इलाके में सांप्रदायिक तनाव के चलते दो समुदायों के बीच रह-रहकर एक हजार राउंड से भी ज्यादा गोलियां चलाई गई हैं। याद रखिए यह आंकड़ा बहुत खतरनाक इसलिए भी है क्योंकि इतनी गोलियां महज 48 घंटे के अंदर चलीं। ऐसा अब के पहले कभी नहीं हुआ, मुंबई जैसे भयानक दंगों के समय भी नहीं।

डर के साये में जिंदगी

खुरेजी, चांदबाग, भजनपुरा, जाफराबाद समेत उत्तर-पूर्वी दिल्ली और आसपास के इलाकों में शांति है लेकिन खौफ और दहशत का माहौल अभी बना हुआ है। ज्यादातर दुकानें बंद हैं और उनके दरवाजों पर हिंसा के निशान साफ देखे जा सकते हैं। सांप्रदायिक हिंसा के बाद उत्तर-पूर्वी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में शांति वापस लौट रही है। अब जहां एक ओर सड़कों पर पुलिस है और हिंसा के निशान हैं तो वहीं दूसरी ओर गलियों में हालात अब भी सामान्य नहीं हैं। लोगों में खौफ और दहशत का माहौल अभी बना हुआ है। गलियों में अब भी लोग इकट्ठा होकर माहौल भांपने की कोशिश कर रहे हैं। इन इलाकों में ज्यादातर दुकानें बंद हैं और उनके दरवाजों पर हिंसा के निशान साफ देखे जा सकते हैं। सड़कों पर पत्थर और ईंट के टुकड़े फैले हुए हैं। बीच-बीच में जली हुई दुकानें दिख रही हैं। फूंकी हुई गाड़ियां और सामान दिख रहे हैं और हिंसा को रोकने के लिए पुलिस प्रभावित इलाकों में फ्लैग मार्च कर रही है। कई जगहों पर लोगों के घर जला दिए गए हैं। रोजमर्रा का हर सामान और रोजी-रोटी का जरिया भी राख में बदल गया है। नफरत और हिंसा की ये तस्वीरें आपको सड़कों पर हर तरफ दिख जाएंगी।

सुनियोजित साजिश या लापरवाही

लगता है दिल्ली की इस अराजक हिंसा के बाद अब दंगाइयों का गोली चलाना आम हो जाएगा। आखिर ये स्थितियां क्यों और कैसे बनीं ? इसके पीछे किसकी सुनियोजित साजिश या लापरवाही थी? क्या यह हिंसा और बेकाबू में हुई स्थितियां राजनीतिक फायदा उठाने के लिए एक तयशुदा योजना के साथ घटित हुईं? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि दिल्ली में पुलिस और कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी केंद्रीय गृहमंत्री की है। गृह मंत्रालय के अधीन देश के अंदर और देश के बाहर सक्रिय रहने वाली खुफिया एजेंसियां हैं तथा और भी जबरदस्त नेटवर्क हैं। इसके बाद भी यह किसकी चूक थी कि एक मामूली सा तनाव देखते ही देखते इतना उग्र हो गया। अगर सारी स्थिति को क्रमिकता के नजरिए से देखें तो साफ पता चलता है कि दिल्ली में जो खौफनाक स्थितियां पैदा हुईं, वह स्वतः स्फूर्त नहीं थीं, उन्हें कोशिशन पैदा किया गया था और इसमें हर राजनीतिक पार्टी की अपने-अपने स्तर की भूमिका थी। केंद्रीय गृह मंत्रालय जिसके अंतर्गत दिल्ली की पुलिस तथा कानून व्यवस्था आती है, वह केंद्र सरकार अगर पहले से इस भयावह स्थिति का सही आंकलन कर पाती तो इस तरह की स्थितियां नहीं बनतीं। लेकिन सिर्फ केंद्रीय गृह मंत्रालय और अमित शाह को ही इस पूरी घटना का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

केजरीवाल कहां थे?

आखिर दिल्ली के अब तक के सर्वाधिक लोकप्रिय और जनता के लिए उनके हितैशी के रूप में मशहूर केजरीवाल ने इन दंगों को इस स्थिति तक न पहुंचने देने के लिए क्या किया? माना कि उनके पास पुलिस की बागडोर नहीं है, लेकिन पुलिस से ज्यादा कारगर दंगों के समय राजनेताओं का जमीन में उतरना होता है। क्या मुख्यमंत्री केजरीवाल अपने विधायकों, मंत्रियों के साथ तनाव वाली सड़कों में उतर नहीं सकते थे? अगर वह वाकई ऐसा करते क्या तब भी स्थितियां ऐसी होतीं? अगर कांग्रेस तथा दूसरी विपक्षी पार्टियों के लोग भी इस तनावपूर्ण स्थिति की संवेदना को समझते हुए लोगों के बीच पहुंचते तो क्या दंगाई मनमानी कर पाते? हकीकत तो यह है कि जिन इलाकों में पुलिस को स्थिति काबू में करनी थी, वहां कई जगहों पर पुलिस अपनी घिनौनी हरकतों से खुद सांप्रदायिक उन्माद का हिस्सा बनी हुई थी। दरअसल, दिल्ली में जो हिंसक वारदात हुई उसके पीछे राजनीतिक कमजोरी के साथ ही पुलिस की निष्क्रियता भी कारण रही है।

केंद्र इतना उतावला क्यों?

दिल्ली दंगे की मूल वजह क्या है, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन इसके पीछे केंद्र सरकार का उतावलापन भी एक वजह माना जा रहा है। दरअसल, जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने और राम मंदिर का मसला सुलझाने के बाद केंद्र सरकार इतनी उत्साहित हो गई थी कि उसने सीएए, एनआरसी और एनपीआर को भी लागू करने की जल्दबाजी दिखा दी। दरअसल, सीएए में सरकार ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुसलमानों को छोड़कर अन्य जातियों के लोगों को नागरिकता देने का जो प्रस्ताव रखा है, उसको जनता के बीच इस तरह तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है जिससे मुसलमान भ्रमित हो रहे हैं। कुछ बातें तो पहले से ही सामने हैं। एक समूह देशभर में नागरिकता संशोधन कानून, एनपीआर और एनआरसी के नाम पर झूठ और गलतफहमी के द्वारा मुसलमानों के अंदर भय पैदा करने तथा उनके एक बड़े तबके को उकसाने में सफल हो चुका है। यह तथ्य बार-बार स्पष्ट किया जा चुका है कि नागरिकता कानून से भारत के नागरिकों का कोई संबंध नहीं है। इसी तरह एनपीआर 2010 में हुआ, 2015 में अद्यतन किया गया और यह सामाजिक-आर्थिक जनगणना है जो अब मूल जनगणना का भाग है। एनआरसी पर अभी सरकार के अंदर औपचारिक फैसला नहीं हुआ है। अगर कल फैसला हुआ और उसमें कोई आपत्तिजनक या अस्वीकार्य पहलू होगा तो उसका विरोध किया जाएगा। जो अभी है ही नहीं उसका विरोध करने का कारण क्या हो सकता है? यह प्रश्न और ये तथ्य उनके लिए मायने रखते हैं जिनका उद्देश्य सच समझना हो। जिनका उद्देश्य सरकार के विरुद्ध पूरे समुदाय को भड़काकर स्थिति बिगाड़नी हो उनके लिए इनका कोई अर्थ नहीं है। ये समाज विरोधी, सांप्रदायिक और उपद्रवी शक्तियां हैं जिनके इरादे खतरनाक हैं।

ट्रम्प को दिखाने के लिए

दिसंबर की जामिया हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस के आरोप पत्र में ही इस तरह की साजिश का विवरण है। जो लोग किसी तरह कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा कर सरकार को बदनाम करने की फिराक में थे उनके लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की यात्रा भी बड़ा अवसर था। इसमें दोनों तरह की शक्तियां थीं। एक वे जो धरना-प्रदर्शन से ही स्थिति को बिगाड़ देना चाहते थे तथा दूसरे वे जो हिंसा द्वारा ऐसा करने की तैयारी में थे। वे चाहते थे कि किसी तरह दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक स्थिति इतनी बिगाड़ दी जाए जिससे ट्रम्प की नजर तो जाए ही, उनको कवर कर रही अंतरराष्ट्रीय मीडिया के फोकस में भी विरोध आ जाए। अलीगढ़ में अशांति पैदा करने की कोशिशें पुलिस और प्रशासन की सक्रियता से विफल कर दी गईं, किंतु दिल्ली में ऐसा नहीं हो सका।

शाहीन बाग के पीछे का चेहरा

समझने की आवश्यकता है कि शाहीन बाग का जो धरना सामने दिख रहा है उसके पीछे कई प्रकार के शरारती दिमाग और खतरनाक विचार हैं। पूरे देश ने वह वीडियो देखा जिसमें उच्चतम न्यायालय द्वारा वार्ताकार नियुक्त किए जाने के साथ तीस्ता सीतलवाड़ अपने साथियों के साथ वहां महिलाओं को प्रशिक्षण दे रही थीं कि आपको किस सवाल का क्या जवाब देना है और अपनी ओर से क्या सवाल करना है या शर्तें रखनी हैं। उस वीडियो ने शाहीन बाग के पीछे छिपे चेहरे को उजागर कर दिया था। यह सीधे-सीधे वार्ताकारों को विफल करने की साजिश थी।

फैसला आने का इंतजार क्यों नहीं?

जो लोग अभी भी नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर हो रहे विरोध को संविधान बचाने से लेकर लोकतांत्रिक बता रहे हैं उनसे यह पूछा जाना चाहिए कि अब क्या होगा जिसके बाद आपका भ्रम टूटेगा? उच्चतम न्यायालय की एक पीठ नागरिकता संशोधन कानून पर 160 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। अगर संविधान बचाने का विचार हो तो कायदे से इसके संवैधानिक-गैर संवैधानिक होने का फैसला न्यायालय पर छोड़ा जाना चाहिए था, लेकिन जब उद्देश्य खतरनाक हो तो वे क्यों ऐसा करेंगे? उनको केवल आग लगाना और उसका विस्तार करना है ताकि केंद्र सरकार के लिए विकट स्थिति पैदा हो जाए। इस आग को रोकना है तो तथाकथित मानवाधिकारवादियों तथा मीडिया के एक वर्ग की निंदा का जोखिम उठाते हुए भी कार्रवाई करनी होगी। दिल्ली पुलिस को शाहीन बाग खाली करने के लिए किसी न्यायालय

कारोबार पड़ा ठप, करोड़ों का नुकसान

उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों से इन इलाकों में कारोबार ठप सा हो गया है। दूर गांवों से दिल्ली आए कारीगर अपने घरों को लौट गए हैं। बेपटरी कारोबार के कारण करोड़ों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगे में कुटीर व लघु उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। शेरपुर, बिहारीपुर व तुकमीर पुर में बड़े पैमाने पर मशीनों द्वारा कढ़ाई व जरी का काम होता है। दंगों ने इस कारोबार को ठप कर दिया है। चारों ओर बंद दुकानें यहां के हालात बयां कर रही हैं। कढ़ाई का काम बंद होने से धागों की दुकानों का काम भी ठप हो गया है। शेरपुर चौक के पास धागे की दुकान पर बैठे कौशल किशोर उर्फ कालू भाई बताते हैं कि पांच दिन बाद दुकान खोली है सुबह से कोई ग्राहक नहीं है। अधिकांश कारीगर घर चले गए हैं। करावल नगर व्यापार एकता मंडल के उपाध्यक्ष प्रदीप कुमार अरोड़ा ने पांच दिन तक दुकान बंद रहने और हिंसा के दौरान दुकानों के जलने व लूट लिए जाने से 200 करोड़ रुपए के नुकसान होने का दावा किया है। 5 किमी के दायरे में मुस्तफाबाद और करावल नगर विधानसभा का इलाका फैला है। जिसमें परचून से लेकर कई रेडीमेड कपड़ों की दुकानें शामिल हैं। हिंसा के समय यह पूरा इलाका प्रभावित था। कई दुकानों को फूंका और लूट लिया गया, जिससे काफी नुकसान पहुंचा है।

के आदेश की आवश्यकता नहीं। सड़क घेरना गैर कानूनी यानी आपराधिक कदम है और पुलिस को इसके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। अगर दिल्ली को संभालना है तथा देश में इन खतरनाक साजिशों की पुनरावृत्ति नहीं होने देना है तो फिर पुलिस प्रशासन को अपनी भूमिका कठोरता से निभानी होगी, किंतु हमें यह भी समझना होगा कि यह एक वैचारिक संघर्ष में भी परिणत हो चुका है।

आपने कई भाषण सुने होंगे जिनमें कहा जा रहा है कि तीन तलाक के खिलाफ कानून बना और हम चुप रहे। 370 हट गया फिर भी हमने कुछ नहीं किया। अयोध्या का फैसला आ गया और हम खामोश बैठे रहे। अब नागरिकता कानून बन गया। आगे एनआरसी होगा। फिर कुछ होगा। इस तरह मुसलमानों को यह समझाया जा रहा है कि वर्तमान सरकार उनकी विरोधी है और अपना वजूद बचाना है तो उठो और लड़ो। इस तरह का खतरनाक झूठ फैला दिया जाए तो अलग-अलग तरह के तत्व अपने-अपने तरीके से विरोध करने लगते हैं। इसका सामना करने के लिए समाज को आगे आना होगा।

दंगों का दर्द कब तक?

दंगों का दर्द कब तक रुलाएगा, कोई नहीं जानता। लोग अपनों की तलाश में इधर से उधर भटक रहे हैं। अस्पतालों से लेकर थानों तक के चक्कर लगा रहे हैं, आसपास के नालों में खोजबीन करवा रहे हैं। पर दंगों से जो सवाल फिर से निकले हैं, वे वही के वही हैं, जैसे दंगाई कौन थे, किसके इशारे पर दंगे हुए, शुरुआत में पुलिस मूकदर्शक-सी क्यों बनी रही? हमेशा की तरह इन सवालों के जवाब भी शायद ही मिलें। दंगों के बाद की दिल्ली की जो तस्वीर दिख रही है उसमें डर और नफरत अब भी बाकी है। दरअसल इस तरह की नफरती हिंसा देखने के बाद आपको देश में पुलिस प्रशासन, नेताओं और दूसरे जिम्मेदार लोगों की याद आती है। लेकिन देश के तमाम दूसरे दंगों की तरह यहां पर भी यह कहानी दोहराई गई है कि पुलिस, प्रशासन और राजनेता सभी इस दौरान लापता रहे। जबकि तकनीक ने इस दंगे की बर्बरता को और बढ़ा दिया। ये सिर्फ सिलेक्टिव घरों या दुकानों की कहानी नहीं है। करावल नगर पुश्ते पर दंगाई परिवहन विभाग के ऐप का इस्तेमाल करके गाड़ी के मालिक की पहचान कर रहे थे और तब गाड़ियों में आग लगा रहे थे। इसी तरह तमाम अफवाहें सोशल मीडिया (ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप और दूसरे माध्यम) के जरिए तेजी से वायरल हो रही थीं। दंगाग्रस्त इलाकों में घूमते समय ज्यादातर लोगों ने इस बात को दोहराया कि सोशल मीडिया ने निगेटिव रोल अदा किया। लोगों के बीच भय और नफरत के बीज वहीं से बोए गए। फिलहाल हमें इन तमाम खतरों के बीच ही अमन कायम करना है और इंसानियत की रक्षा करनी है।

दिल्ली पुलिस गफलत में

खौफनाक हिंसा से उभर रही दिल्ली के दामन पर जो दाग लगा उसे मिटाने के लिए यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है कि हत्या और आगजनी के लिए जिम्मेदार तत्वों की पहचान कर उन्हें सख्त सजा देना सुनिश्चित किया जाए। चूंकि बड़े पैमाने पर हुई हिंसा यह बता रही है कि उसके पीछे सुनियोजित साजिश और पूरी तैयारी थी इसलिए हर घटना की तह तक भी जाने की जरूरत है। दिल्ली की भीषण हिंसा यह बता रही है कि किसी न किसी स्तर पर दिल्ली पुलिस और साथ ही सरकार से गफलत हुई। वास्तव में इसी कारण वह निंदा और आलोचना के निशाने पर है। दिल्ली पुलिस और साथ ही मोदी सरकार को इस आलोचना का सामना करना ही होगा। आखिर दिल्ली की सुरक्षा सुनिश्चित करना उसकी ही जिम्मेदारी थी। जिस मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में देश में कोई बड़ा दंगा नहीं हुआ उसकी नाक के नीचे यानी राजधानी दिल्ली में इतने भीषण दंगे हुए कि 42 लोगों की जान चली गई।

यह घाव नहीं भरेगा

यूं तो वक्त के साथ सारे दुख-दर्द भुलाए जा सकते हैं, लेकिन दिल्ली के दंगों ने जो जख्म दिए हैं, उन्हें शायद ही भुलाया जा सकेगा। जिस तरह से 1984 के सिख दंगों और 2002 के गुजरात दंगों के घाव आज भी हरे हैं और पीड़ितों की आंखों में आज भी आंसू हैं, उसी तरह इस हफ्ते के शुरू में उत्तर-पूर्वी दिल्ली की बस्तियों में हुए दंगों ने भी लोगों के मन में हमेशा के लिए टीस पैदा कर दी है। इससे भी ज्यादा दुख इस बात का है कि तीन दिन तक चले हिंसा के इस तांडव को सांप्रदायिक रंग दे दिया गया, जबकि हिंसा फैलाने वालों के बारे में अब तक यही कहा जा रहा है कि यह शरारती तत्वों का काम था और किसी के इशारे पर इसे अंजाम दिया गया है। इस बात के भी संकेत मिले हैं कि यह कुछ पेशेवर आपराधिक समूहों का काम था। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर कोई पेशेवर आपराधिक समूह इतने बड़े पैमाने पर हिंसा फैलाता है तो इसके पीछे निश्चित रूप से कोई हाथ होगा, साजिश होगी। अब दंगों की जांच पुलिस के दो विशेष जांच दलों को सौंपी जा चुकी है, ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि सच सामने आएगा।

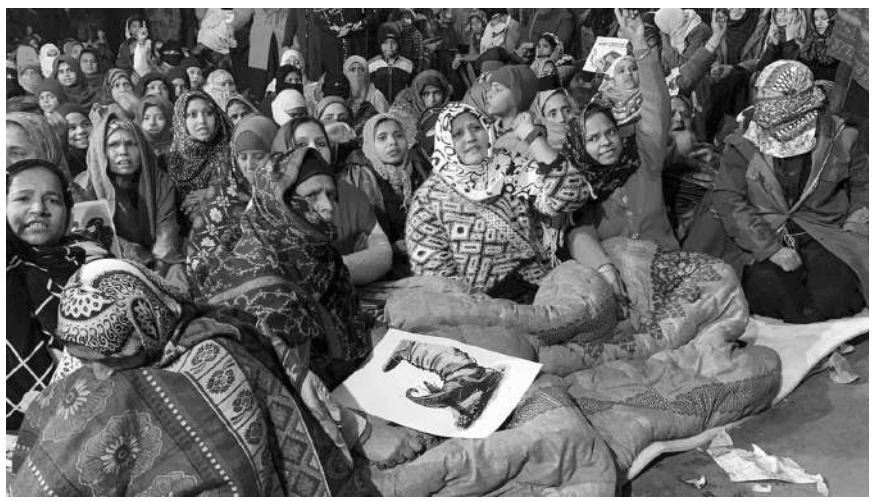

ऐसे पुलिस के हाथ से फिसलती चली गई बात

दिल्ली हिंसा के बाद यूं लग रहा है कि पर्याप्त पुलिस फोर्स ना होने की वजह से ही उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि पुलिस की तरफ से तुरंत फैसला नहीं लेने की वजह से ही महज 36 घंटों में 42 लोगों की जान चली गई। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि 22 फरवरी की रात को इस हिंसा के बीज बोए गए। करीब 600 महिलाएं जाफराबाद की संकरी गलियों से होते हुए दिल्ली मेट्रो स्टेशन की तरफ बढ़ रही थीं। हालांकि, पुलिस ने उस वक्त कोई दखलअंदाजी नहीं की। स्थानीय लोगों के अनुसार पुलिस मान रही थी कि वह महिलाएं वहां जा रही हैं, जहां पहले से ही प्रोटेस्ट हो रहा है, लेकिन वह मेट्रो स्टेशन पर ही प्रोटेस्ट करने लगीं, जो पहले वाली जगह से करीब 500 मीटर दूर था। उस वक्त बहुत ही कम महिला पुलिस बल मौजूद था, जो महिलाओं की भीड़ से निपट सके और पुलिस उन्हें तितर-बितर करने के लिए बल का प्रयोग भी नहीं कर सकती थी। उन्हें ऊपर से भी कोई आदेश नहीं मिला, क्योंकि ये नहीं पता था कि इस पर कोर्ट कैसा रुख अपनाएगा। देखते ही देखते महिलाओं के साथ करीब 400 पुरुष भी प्रोटेस्ट में शामिल हो गए। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार शुरुआत में प्रोटेस्ट करने वाले लोग स्थानीय नहीं थे। दूसरे दिन सुबह तक प्रदर्शनकारियों की संख्या बढ़कर 3000 हो गई। उन्होंने बताया कि उन्हें बल का प्रयोग कर के नहीं हटा सकते थे, ऐसे में उन्हें कोई भी टेंट लगाने या स्टेज लगाने से रोक दिया। पुलिस को लगा था कि ये प्रदर्शन भी शाहीन बाग की तरह शांतिपूर्ण रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा- हमने 24 फरवरी के लिए पर्याप्त इंतजाम किए थे, जब अमेरिकी राष्ट्रपति दिल्ली पहुंचे, हालांकि पूर्वी रेंज के अधिकारियों को छूट दी गई थी। फोर्स को लाने में कुछ समय लगा, लेकिन हमारे पास पर्याप्त पुलिस फोर्स थी। 24 फवरी को ही सुबह तक दंगे शुरू हो गए। जो पत्थरबाजी से शुरू हुआ था, वह धीरे-धीरे तोड़फोड़ और आगजनी में बदल गया। कुछ ही देर में दोनों समूहों के बीच देसी कट्टों से गोलीबारी शुरू हो गई। एक सूत्र के मुताबिक, 'गुस्साए समूह ना सिर्फ एक दूसरे पर हमले कर रहे थे, बल्कि पुलिस को भी निशाना बना रहे थे। कुछ जगहों पर तो भीड़ ने पुलिस को ही घेर लिया, तो कहीं पर तीनों तरफ से पुलिस पर हमले हुए।'

जले हिन्दू-मुस्लिम के मकान और रिश्ते

देश की राजधानी दिल्ली में 23 फरवरी से शुरू हुई पूर्व-नियोजित भयानक मुस्लिम-विरोधी हिंसा ने, जिसमें अब तक 42 लोगों की जानें जा चुकी हैं, एक बात बहुत साफ तौर पर बता दी है, वह यह कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) भारत के लिए अत्यंत विभाजनकारी व विघटनकारी हैं। इन्हें फौरन वापस लिया जाना चाहिए या रद्द कर देना चाहिए, नहीं तो दिल्ली से भी ज्यादा खौफनाक हालात देश में पैदा हो सकते हैं। सीएए-एनपीआर-एनआरसी को लेकर खासकर मुस्लिम समुदाय के अंदर गहरी असुरक्षा, चिंता और आशंका पैदा हो गई है, उसकी वाजिब वजहें हैं। इस चिंता और असुरक्षा को दूर करने की कोई कोशिश केंद्र की भाजपा सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने नहीं की, उलटे अपने बयानों और हाव-भाव से उसे और बढ़ाया ही। दिल्ली की करावल नगर विधानसभा के खजूरी खास इलाके की दो गलियों में 70-80 मकान थे जो सारे जला दिए गए केवल 3 मकान बचे जो हिन्दुओं के थे। जो मकान बचे उनमें एक मकान दिल्ली पुलिस के सिपाही का, एक मकान सील था और एक मकान वकील साहब का था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि दंगाई किस मकसद और मानसिकता से आए थे।

दिल्ली के दंगा पीड़ित खासतौर से जिन लोगों ने अपनों को हमेशा के लिए खो दिया है, वे सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर हमने किसी का क्या बिगाड़ा था, जिसकी वजह से आज ये दिन देखना पड़ा है। लेकिन दंगों का इतिहास बताता है कि ऐसे सवालों का किसी के पास कोई जवाब नहीं होता और ये सवाल वक्त के साथ गुम हो जाते हैं। दंगों में किसी ने अपने जवान बेटों को खोया, तो किसी ने अपनी बूढ़ी मां को। दंगाइयों ने ये भी नहीं देखा कि 85 साल की बूढ़ी महिला को जिंदा जलाने से उन्हें क्या हासिल होने जा रहा है, क्योंकि नफरत के उन्माद में उन्हें तो बस मारकाट मचाकर अपना मकसद पूरा करना था।

जो लोग तेजाबी हमले में झुलस गए या तलवार और गोलियों के हमले में जख्मी हो गए, वे शायद ही कभी इन खौफनाक क्षणों को भूल पाएं। तीन दिन के दंगों में जिस तरह से दुकानें लूटी गईं, तोड़फोड़ कर उन्हें आग के हवाले कर दिया गया, उससे अब लोगों के सामने रोजी-रोटी का बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। कैसे लोग फिर से अपना काम-धंधा शुरू करेंगे, यह बड़ा सवाल है। ज्यादातर दंगा पीड़ित रोज कमाने-खाने वाले हैं, मजदूरी करने वाले हैं, जिनके पास अब न रहने को ठिकाना बचा है, न अगले दिन के लिए काम।

अवैध हथियारों के जखीरे पर दिल्ली

दिल्ली में भड़की हिंसा के दौरान जमकर अवैध हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 500 राउंड से ज्यादा गोलियां चली हैं। उपद्रव में इतनी बड़ी संख्या में अवैध असलहों के इस्तेमाल से पुलिस भी परेशान है। आला पुलिस अधिकारी अवैध हथियारों की आपूर्ति करने वाले और इलाके के आपराधिक छवि वाले बदमाशों की तलाश में जुट गए हैं। पुलिस के अनुसार, दिल्ली हिंसा में पिस्टल और देशी तमंचों का जमकर इस्तेमाल किया गया। जगह-जगह पुलिस को कारतूस के खोखे मिल रहे हैं जिन्हें जांच के लिए जुटाया जा रहा है।

जांच के दौरान 0.32 मिलीमीटर, 0.9 मिलीमीटर पिस्टल 0.12 मिलीमीटर और 0.315 मिलीमीटर कैलिबर के कारतूस के खोखे बरामद हुए। आला पुलिस अफसरों का कहना है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली में बड़े पैमाने पर अवैध हथियारों की खेप होने की आशंका है। देश की राजधानी में इतनी बड़ी संख्या में गोलीबारी की यह पहली घटना है। इससे पहले 1984 के सिख दंगे और 1992 में हुए दंगों में गोलीबारी की घटनाएं कम थीं।

राजनीति की माया ही ऐसी है कि वह अच्छे-अच्छों को अपनी ओर आकर्षित करती है। यही कारण है कि हर विधा के लोगों की मंशा रहती है कि वह राजनीति में आएं। अभी तक रणनीतिकार के रूप में ख्यात पीके भी राजनीति में उतर गए हैं।

रणनीतिकार बने राजनीतिज्ञ

प्रशांत किशोर का नाम आज देश के सभी दिग्गज नेताओं की जुबान पर है। प्रॉफेशनल प्रमोटर से राजनीतिक सितारे बने पीके असल में किसके साथ हैं, किसी को नहीं पता चलता। वो हर चुनाव में किसी नए चेहरे के साथ होते हैं। पीके चुनाव जीतने की रणनीति को टॉप गीयर में डालते हैं, चुनाव जिताते हैं और वहां से विदा होकर किसी ओर चुनाव में किसी और चेहरे के साथ नजर आते हैं। एक मायने में पीके विशुद्ध रूप से व्यावसायिक यानि प्रॉफेशनल हैं। वो किसी भी विचार, विचारधारा या राजनीतिक दल के साथ नहीं हैं। इसलिए प्रशांत हर बार नए अंदाज में किसी नई जगह पर किसी नए साथी के साथ कुछ नया बुन रहे होते हैं।

पिछले कई चुनावों में कई राजनीतिक दलों के साथ खड़े होकर माहिर राजनीतिज्ञों को चाणक्य अंदाज में सत्ता तक पहुंचने के गुर सिखाने वाले प्रशांत किशोर को किसी राजनीतिक जमीन की जरूरत महसूस नहीं होती। शायद इसलिए ही जब जदयू के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर को पार्टी से निकाला गया तो जवाब में उन्होंने नीतीश कुमार को धन्यवाद कहकर जता दिया कि वो अपने सफर में किसी की जरूरत महसूस नहीं करते हैं। वो ऐसे कथानक हैं, जो खुद की और दूसरों की स्क्रिप्ट खुद लिखते हैं। यानि एक रणनीतिकार के रूप में वो उस मुकाम पर खड़े हैं, जहां उन्हें किसी की नहीं बल्कि दूसरों को उनकी खासी जरूरत है।

प्रशांत किशोर कभी भाजपा, कभी कांग्रेस, कभी जदयू, कभी दक्षिण की पार्टियों के साथ नजर आते रहे हैं तो अब वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े हैं। किशोर ने उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, आंध्र प्रदेश और पंजाब सहित कई राज्यों के चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से पहले प्रशांत ने 8 वर्षों तक संयुक्त राष्ट्र के लिए काम किया। 2011 में प्रशांत किशोर नौकरी छोड़ वतन लौट आए।

एक चुनावी रणनीतिकार के रूप में प्रशांत किशोर ने 2011 में गुजरात में नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनवाने में मुख्य भूमिका निभाई। प्रशांत स्वतंत्र रूप से काम करते हुए भाजपा या गुजरात सरकार में किसी भी कार्यालय को पकड़े बिना भाजपा के चुनाव-पूर्व अभियान में प्रमुख रणनीतिकारों में से एक बन गए। 2014 के आम चुनाव से पहले उन्होंने चुनाव की तैयारी के लिए एक मीडिया और प्रचार कंपनी का निर्माण किया। इस दौरान प्रशांत किशोर ने अभिनव विज्ञापन अभियान बनाए। उन्होंने नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए चाय पे चर्चा, 3डी रैली, रन फॉर यूनिटी, मंथन और सोशल मीडिया कार्यक्रम रखकर भाजपा के विचार को तेजी से जनता तक पहुंचाया।

2014 के लोकसभा चुनाव ने प्रशांत किशोर को देश के सामने असली पहचान दी। देश का हर दल उनके भाजपा के लिए चुनाव में किए गए काम से प्रभावित हुआ। लोगों से जुड़ाव के लिए शुरू किया गया चुनावी कैंपेन 'चाय पर चर्चा' प्रशांत किशोर का ऐसा आइडिया था जिसने मोदी की छवि को जनता के मध्य एक आम तबके के इंसान की बनाई। 2014 के चुनाव में सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी प्रशांत की ही देन थी।

हालांकि चुनाव के बाद अमित शाह से विवाद के बाद प्रशांत किशोर भाजपा के चुनावी अभियान से अलग हो गए। इसके बाद पीके 2015 में नीतीश कुमार के साथ जुड़े और बिहार चुनाव में जेडीयू-कांग्रेस-राजद के चुनावी अभियान का कार्य संभाला। ऐसा माना जाता है कि एक-दूसरे के धुर विरोधी जेडीयू-आरजेडी-कांग्रेस का महागठबंधन बनवाने में भी पीके की अहम भूमिका रही।

नीतीश कुमार का जनसंपर्क अभियान 'हर-घर दस्तक' कार्यक्रम प्रशांत किशोर की तरफ से लॉन्च किया गया था ताकि चुनाव प्रचार में नीतीश आखिरी व्यक्ति तक अपनी बात पहुंचा सकें। इसी चुनाव में उनका दिया गया नारा 'बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है' पूरे बिहार में हिट हुआ। इस नारे के पीछे भी प्रशांत किशोर का ही दिमाग था। नतीजा यह हुआ कि यहां भाजपा को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही प्रशांत किशोर का सक्रिय राजनीति में भी पदार्पण हो गया और नीतीश ने पीके को जदयू का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। यहीं से पीके को राजनीति का ऐसा चस्का लगा कि वे रणनीतिकार से अब राजनेता बन गए हैं। अब देखना यह है कि वे कितना सफल होते हैं।

● **ऋतेन्द्र माथुर**

पीके के पास अभी भी कई ऑफर

इस बार प्रशांत किशोर दिल्ली विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के साथ खड़े थे, और पूरी-पूरी संभावना भी जताई जा रही थी कि यहां भी केजरीवाल के विकास कार्ड के साथ पीके का जादू चलेगा। सो दिल्ली में आपकी दोबारा सरकार बन गई। अब भले ही पीके ने अपनी राजनीतिक पारी शुरू कर दी है, लेकिन अभी भी उनके पास कई पार्टियों से चुनावी रणनीति बनाने के लिए ऑफर आ रहे हैं। ताजा खबर के अनुसार बिहार की प्रमुख और लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने उन्हें पार्टी में आने न्यौता दिया है। राजद नेता और लालू यादव के बड़े सुपुत्र तेजप्रताप ने उन्हें पार्टी में आने का खुला निमंत्रण दिया है। पीके राजद में शामिल होंगे या नहीं, वो दूर की बात है लेकिन तेजप्रताप के बयान के बाद ही पार्टी में पीके को लेकर दो धड़े बन गए हैं। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने प्रशांत किशोर की तुलना नाली में रहने वाले कीड़े से कर दी, हालांकि तेजस्वी यादव ने जगदानंद को फटकार लगा दी है।

जोड़ी कितनी सफल

भारतीय राजनीति में जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल, अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी के बाद नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी चर्चा में है। मोदी-शाह के बीच सत्ता का ऐसा अनूठा समीकरण है जैसा न तो नेहरू-पटेल के बीच था और न ही वाजपेयी-आडवाणी के बीच था। लेकिन दिल्ली में पार्टी की हार के बाद शाह ने अपने राजनीतिक करियर के नये अपरिचित दौर में कदम रख दिया है। अब देखना यह है कि यह जोड़ी आगे क्या गुल खिलाती है।

अमित शाह ने पार्टी की बागडोर कुछ दिन पहले जेपी नड्डा को थमा दी है। हालांकि, दिल्ली चुनाव उनके ही एजेंडे का बकाया आइटम है, तब सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में चल रही भाजपा सरकार के बारे में हम क्या आंकलन कर सकते हैं? आगे की इसकी राह कैसी दिखती है?

हमारी 73 वर्ष की आजादी के इतिहास में मोदी-शाह सरकार इस तरह की **तीसरी सरकार** है, जो दो ताकतवर हस्तियों के नेतृत्व में चली, जिसे बराबर की हस्ती रखने वाले दो नेताओं ने मिलकर चलाया। बेशक, अकेले एक नेता के नेतृत्व में या अल्पकाल के लिए चलने वाली नेतृत्व विहीन सरकारें भी रहीं। किनारे खड़े होकर राजनीति का जायजा लेने वाले हम जैसे लोगों के लिए तो इन तीनों तरह की सरकारों पर नजर रखना एक दिलचस्प काम रहा है। चरण सिंह से लेकर वीपी सिंह, चंद्रशेखर और देवेगौड़ा से होते हुए आइके गुजराल तक की नेतृत्व विहीन सरकारें सबसे मनोरंजक रहीं। उनमें अंदर-अंदर खूब लड़ाइयां चलीं, अंदर की खबरें लीक होती रहीं और वे जल्दी ही धराशायी होती गईं और एक नेता वाली सरकारों (मसलन इंदिरा गांधी और राजीव की) में साजिशों की कहानियां खूब मिलती रहीं कि कौन है जो ताकतवर चौकड़ी के करीब पहुंच गया, कौन बाहर कर दिया गया। लेकिन बराबर कद वाले दो नेताओं के बीच सत्ता की साझेदारी से चलने वाली सरकारें भी कोई बोर नहीं करतीं।

पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभभाई पटेल के नेतृत्व वाली ऐसी पहली सरकार इतनी दिलचस्प थी कि आज भी वह सुर्खियों में आती रहती है, जैसा कि अभी पिछले सप्ताह ही हुआ। आप कह सकते हैं कि डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार उनके और सोनिया गांधी के बीच आपसी भरोसे के साथ सत्ता की साझेदारी से चली। लेकिन फर्क यह था कि प्रधानमंत्री बराबर के अधिकार रखने वालों में पहले नंबर पर नहीं थे।

दरअसल, दूसरे कार्यकाल में तो वे दूसरे नंबर पर भी नहीं रह गए थे और राहुल गांधी के बाद तीसरे नंबर पर पहुंच गए थे। इसके बाद हम क्रमशः अटल बिहारी वाजपेयी की और नरेंद्र मोदी की भाजपा-एनडीए की दो सरकारों पर आते हैं। दोनों सरकारें दो की सत्ता से चलीं- पहली वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी की और दूसरी नरेंद्र मोदी और अमित शाह की वर्तमान सरकार। दोनों में अंतर है। वाजपेयी और आडवाणी करीबी मित्र, 'सगोत्रीय', लंबे समय से **सहकर्मी और हमउम्र** थे। उन्हें हमेशा बराबर माना गया, एक ज्यादा लोकप्रिय, सर्वमान्य और उदार थे, तो दूसरे सख्त, ज्यादा सियासती और सिद्धांतवादी। वे एक-दूसरे से असहमत भी होते थे मगर फैसला दूसरे पर टाल देते थे। लोग उनकी तुलना ऐसे वृद्ध दंपती से करते थे जो एक-दूसरे के प्रति गहरे निष्ठावान, निर्भर और स्नेहिल होते हैं लेकिन अक्सर इस तरह झगड़ते भी हैं कि लंबे समय तक एक-दूसरे से मुंह फुलाए रहें। लेकिन मोदी और शाह बिलकुल अलग ही किस्म के हैं।

शाह की अगली परीक्षा

दिल्ली चुनाव के साथ भाजपा के बॉस के तौर पर शाह की पारी समाप्त हुई है। वे तो यही चाहते थे कि इस चुनाव का नतीजा अलग होता। लेकिन हरियाणा से दिल्ली और झारखंड तथा कुछ हद तक महाराष्ट्र के वोटरों ने उन्हें एक कड़वे सच का एहसास कराया है कि 'मोदी को वोट' का मतलब 'भाजपा को वोट' नहीं है और निश्चित ही ध्रुवीकरण वाली इसकी विभाजनकारी विचारधारा को वोट नहीं है। इस एहसास के साथ शाह अपने राजनीतिक जीवन के अपरिचित और दिलचस्प दौर में कदम रख रहे हैं। अब उनकी सफलता या विफलता एक महत्वपूर्ण महकमे के मंत्री के तौर उनके कामकाज से आंकी जाएगी। मोदी के साथ मिलकर उन्होंने हमारे राजनीतिक इतिहास की सबसे ताकतवर एवं दिलचस्प जोड़ी बनाई। अब आगे राजनीति पर जो कुछ लिखा जाएगा वह उनके बीच के समीकरण के स्वरूप से प्रभावित होगा।

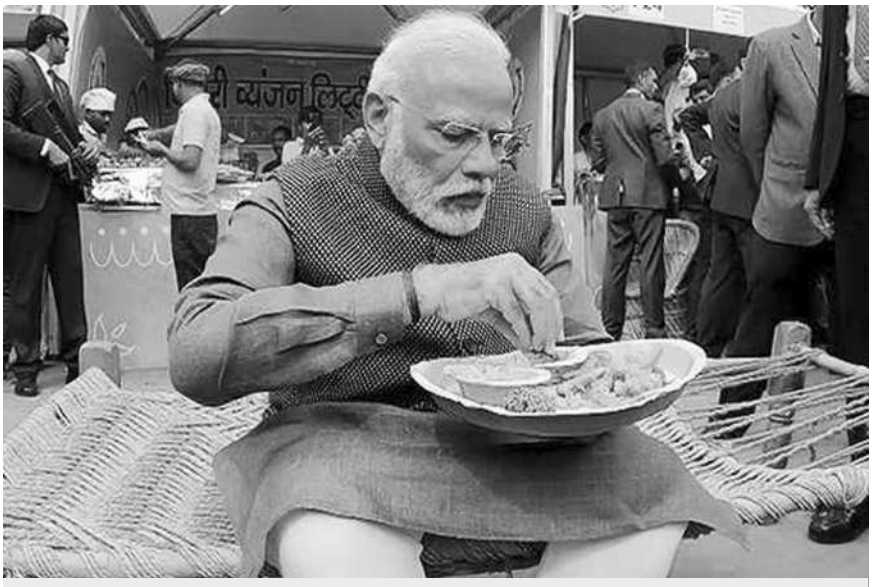

बिहार के वास्ते, पीएम मोदी अब लिट्टी चोखा के रास्ते

लिट्टी चोखा चख कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार में जीत चखने की जुगाड़ में हैं। लिट्टी चोखा से तो बिहार वालों का दिल का रिश्ता है। वैसे भी एक कहावत है कि दिल का रास्ता पेट से होकर जाता है। प्रतीकों की राजनीति करने में वैसे भी मोदी माहिर माने जाते हैं। लिट्टी चोखा खाना, उसकी फोटो जारी करवाना। मतलब साफ है, कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना। बहाना लिट्टी चोखा का लेकिन मोदी तो बिहार में बाजी मार लेना चाहते हैं। पिछली बार कसर रह गई थी। लालू और नीतीश की जोड़ी ने पटक दिया था। इस बार तो नीतीश बाबू भी साथ हैं। सोने पे सुहागा जैसा। मोदी संदेश भी दे रहे हैं। अगर वे लिट्टी तो नीतीश बाबू चोखा हैं। चटनी रामविलास पासवान को ही समझ लीजिए। बिहार के हर चौराहे पर लिट्टी चोखा मिल जाता है। ठेले से लेकर बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में। लिट्टी चोखा हर समाज और बिरादरी के लोगों की पहली पसंद रही है। जब चार दोस्त बैठते हैं, प्लेट में लिट्टी चोखा लग जाता है। चुनावी रैलियों में भी ये खूब बंटता है। पड़ोसी राज्य उप्र में इसे बाटी चोखा भी कहते हैं। दिल्ली चुनाव हारने के बाद नरेंद्र मोदी के लिए बिहार की लड़ाई आर-पार की बन गई है। हर हाल में जीतने का इरादा और वादा है। अभी नहीं तो फिर कभी नहीं के फॉर्मूले पर। हाल में महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में भाजपा की सरकार चली गई। अब बिहार को लेकर मोदी और अमित शाह की जोड़ी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। इस साल अब सिर्फ बिहार में ही चुनाव है। पिछले चुनाव का हिसाब हर हाल में भाजपा बराबर कर लेना चाहती है। अमित शाह कह चुके हैं नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव होगा। प्रशांत किशोर को बाहर कर नीतीश ने भी संदेश दे दिया है। बिहार में जेडीयू और भाजपा का गठबंधन अटूट है। जैसे लिट्टी और चोखा।

नेहरू और पटेल लगभग एक कद के नेता थे और उनके बीच कई असहमतियां भी थीं, जो सबको पता थीं। लेकिन उस व्यवस्था में बॉस कौन था, इसको लेकर कोई संदेह नहीं था। उनके बीच का तनाव बाद में क्या रूप लेता, यह हम नहीं जान सकते क्योंकि पटेल का जल्दी ही निधन हो गया। वाजपेयी और आडवाणी के बीच अलग तरह का समीकरण था। इसमें शक नहीं कि आडवाणी ने भाजपा को नया जन्म और रूप दिया, नए हिन्दुत्व के लिए जगह बनाई और उसमें पार्टी को मजबूती से खड़ा किया। उन्होंने पार्टी को बनाया भी और चलाया भी। भाजपा में वे एक जन-नेता भी थे और जुगाड़-नेता भी थे। उन्होंने गठजोड़ बनाए भी और तोड़े भी।

वाजपेयी एक रोमानी, मंचीय चेहरा थे। अपने अधिकांश राजनीतिक जीवन में उन्होंने आडवाणी का साथ दिया, भले ही कभी-कभी उनके तरीकों से आहत होकर किनारे हो लेते, जैसा कि बाबरी मस्जिद विध्वंस के बाद हुआ। लेकिन उन्होंने कभी आडवाणी का विरोध नहीं किया और न ही उनकी बात काटी। इसी तरह, जब पार्टी सत्ता में आई तब आडवाणी के सामने सच्चाई का व्यवहार कुशलता के साथ सामना करने का मौका आया। उन्हें पता था कि अलग-अलग विचारधाराओं वाले दलों को वे अपने नेतृत्व में कांग्रेस विरोध की पतली डोर से नहीं बांध पाएंगे। उन्हें सबको साथ लेकर चलने वाले, सबको मान्य, वाजपेयी जैसे नेता की जरूरत पड़ेगी। सो, वाजपेयी प्रधानमंत्री बने लेकिन पार्टी में और कई तरह से सरकार में भी असली सत्ता आडवाणी के हाथ में रही।

इसका शुरुआती प्रमाण हमें तभी मिल गया था जब वाजपेयी को अपने विश्वसनीय और मूल्यवान मित्र जसवंत सिंह को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने दिया गया और पार्टी के अंदर झगड़े चलते रहे, क्योंकि संघ के करीबी लोग उन्हें अपने करीबी ब्रजेश मिश्र और दत्तक दामाद रंजन भट्टाचार्य को लेकर परेशान करते रहे। इससे भी अहम यह कि 2002 गुजरात दंगों के मामले में वाजपेयी ने जब मोदी को बर्खास्त करना चाहा तो आडवाणी ने उन्हें रोक दिया। यहां तक कि युद्ध करने, शांति की राह पर चलने जैसे रणनीतिक मसलों पर भी आडवाणी की ही चली। यह एक **दस्तावेजी** तथ्य है कि जनरल परवेज मुशर्रफ के साथ आगरा शिखर सम्मेलन करने और उसे रद्द करने का विचार और फैसला भी आडवाणी का था। लेकिन वाजपेयी-आडवाणी के इर्द-गिर्द आम चाटुकारी और गपबाजी करने वाले हमेशा यही कहते रहे कि 'अरे भाई यह राम-लक्ष्मण की तरह हमेशा साथ रहते हैं।'

मोदी-शाह समीकरण कई तरह से अलग किस्म का है। इनमें से तीन सबसे बड़े अंतरों पर नजर डालते हैं। पहली बात यह कि ये दोनों करीब दो दशकों से साथ-साथ हैं। एक तो सर्वविजयी जननेता हैं और दूसरे एक तेजतर्रार पार्टी प्रभारी हैं। दोनों की भूमिकाएं स्पष्ट हैं और दोनों अपने-अपने हुनर में महारत रखते हैं। एक जो है वह वोट लाता है, तो दूसरा अपनी पार्टी एवं चुनावी मशीनरी को **चुस्त-दुरुस्त** रखता है, ताकि उन वोटों को इकट्ठा किया जा सके। इस लिहाज से यह सचमुच में नंबर वन और नंबर टू वाला रिश्ता है, जैसा कि कॉर्पोरेट दुनिया में सीईओ और सीओओ का या मुख्यमंत्री और उसके सबसे भरोसेमंद मुख्य सचिव का या कमांडेंट और सार्जेंट मेजर का होता है और हालांकि हाल में एक आयोजन में शाह ऐसी तुलना से मना कर चुके हैं, लेकिन आप उनके रिश्ते की तुलना चन्द्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के रिश्ते से भी कर सकते हैं।

दूसरी बात यह कि सार्वजनिक जीवन को लेकर दोनों का नजरिया बिलकुल अलग है। एक बाह्यमुखी जननेता हैं, जो दुनियाभर में अपनी प्रशंसा से प्रसन्न होते हैं, जबकि दूसरे नेता को नेपथ्य में रहकर सत्ता की डोर खींचने में मजा आता है और जो प्रमुख देशों के राजदूतों से भी मिलने में कतराते हैं। एक हैं, जो जनता को अपनी ओर खींचते हैं, तो दूसरे ऐसे हैं जो पार्टी के वफादारों को प्रेरित-उत्साहित करते हैं। एक हैं जो अच्छे पुलिसवाले की भूमिका निभाने की पूरी सावधानी बरतते हैं, तो दूसरे को अपनी आस्थाओं पर चलने में संतोष मिलता है। भले ही इसका मतलब खराब पुलिसवाले की भूमिका निभाना हो और तीसरी बात यह कि, पहली दो जोड़ियों के विपरीत इस जोड़ी में नंबर दो जो है वह नंबर वन से काफी छोटा (14 साल) है। इसलिए उसका राजनीतिक भविष्य नंबर वन से काफी आगे तक जा सकता है।

● **दिल्ली से रेणु आगाल**

आगामी राज्यसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस में जिस तरह की सक्रियता देखी जा रही है, उससे यह साफ हो गया है कि पार्टी में राहुल गांधी को अध्यक्ष के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। वहीं पार्टी के अंदर भी यह मांग लगातार तेज हो रही है कि राहुल गांधी को जल्द से जल्द पार्टी की कमान सौंप दी जाए।

राहुल की होगी वापसी!

राहुल गांधी को जल्द ही एक बार फिर से कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है। इसका संकेत इसलिए भी मिल रहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी के करीबी नेताओं को राज्यसभा भेजने की तैयारी हो रही है। यह इस बात का संकेत है कि पार्टी नेतृत्व ने उन्हें रिलॉन्च करने की पूरी तैयारी कर ली है। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी खराब सेहत के चलते सक्रिय राजनीति से दूर हैं। ऐसे में कांग्रेस राहुल गांधी की ताजपोशी के लिए पार्टी अधिवेशन बुलाएगी। ऐसी संभावनाएं हैं कि इस दौरान राहुल गांधी के नाम पर मुहर लगा दी जाएगी।

बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को मिली करारी हार के बाद 25 मई को कांग्रेस **वर्किंग कमेटी** की बैठक में अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। पार्टी नेताओं ने उन्हें मनाने की काफी कोशिश की। लेकिन वे नहीं माने और 3 जुलाई को इस्तीफे से जुड़ी चिट्ठी ट्विटर पर पोस्ट कर दी। इसमें उन्होंने लिखा था- अध्यक्ष के नाते हार के लिए मैं पूरी तरह जिम्मेदार हूं, इसलिए अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। सीडब्ल्यूसी को जल्द से जल्द बैठक बुलाकर नए अध्यक्ष का चुनाव करना चाहिए। पार्टी अध्यक्ष के तौर पर राहुल गांधी की ताजपोशी दिसंबर 2017 में हुई थी।

हालांकि इस बार राहुल गांधी की राह शायद उतनी आसान नहीं रहेगी, जितनी की पहली बार रही थी। दरअसल पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने की मांग कर डाली है। संदीप दीक्षित ने पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने की मांग की थी। बता दें कि संदीप दीक्षित ने कहा था कि इतने महीनों के बाद भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नया अध्यक्ष नहीं नियुक्त कर सके। इसका कारण यह है कि वह सब यह सोच कर डरते हैं कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? पूर्व सांसद दीक्षित ने कहा कि कांग्रेस के पास नेताओं की कमी नहीं है। अब भी कांग्रेस में कम से कम 6-8 नेता हैं जो अध्यक्ष बनकर पार्टी का नेतृत्व कर सकते हैं। वहीं संदीप दीक्षित के बयान का शशि थरूर ने भी समर्थन किया है। लेकिन पार्टी में जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं, उससे **साफ है कि अगला** अध्यक्ष राहुल गांधी ही होंगे।

गौरतलब है कि बीता साल कांग्रेस के लिए ज्यादा अच्छा नहीं रहा। जहां 2018 में तीन बड़े राज्यों में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी वहीं 2019 में तीन राज्यों में ठीक-ठाक सी टक्कर देकर कांग्रेस 2 राज्यों में सरकार में शामिल होने में कामयाब तो रही लेकिन आम चुनावों में पार्टी की हालत दयनीय हो गई। आम चुनावों में मोदी लहर के सामने कांग्रेस के कई बड़े दिग्गज और खासकर राहुल गांधी के तमाम करीबी युवा नेता अपने बड़े-बड़े नामों के साथ न्याय न कर पाए और चुनाव हार गए। और तो किसकी कहें, खुद राहुल गांधी अपनी परम्परागत अमेठी सीट से स्मृति ईरानी के सामने चुनाव हार बैठे। खैर पुरानी बातों को छोड़िए, बात करें इस साल अलग-अलग समय में खाली होने वाली राज्यसभा सीटों की। चूंकि राहुल गांधी की युवा टीम के लगभग

कांग्रेस में नहीं होंगे अध्यक्ष चुनाव

अब कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराने की बात को सिरे से नकार दिया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दीक्षित और बयानबाजी करने वाले अन्य नेता ज्ञान देने की बजाय अपने क्षेत्र में ध्यान दें और इस बारे में सोचें कि वे चुनावों में क्यों हारे? इस बीच, पार्टी सूत्रों का कहना है कि सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी एकमात्र दावेदार हैं और भविष्य में उनके जिम्मेदारी संभालने की प्रबल संभावना है। सुरजेवाला ने कहा कि मैंने संदीप दीक्षित का बयान नहीं देखा है, लेकिन मैं उन समेत सभी नेताओं से कहता हूं कि पहले वो यह देखें कि जब चुनाव लड़े तो कितने वोट आए और चुनाव क्यों हारे? इसमें मैं भी हूं। संदीप अगर ये सारी मेहनत अपने संसदीय क्षेत्र में लगा दें तो कांग्रेस जीत जाए। उन्होंने कहा, मैं इन नेताओं से कहना चाहता हूं कि पूरे देश को ज्ञान देने की बजाय अपने-अपने क्षेत्र में अपने काम से फायदा उठाएं। वहीं मुंबई कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष संजय निरुपम ने राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाए जाने का समर्थन किया है।

सभी खिलाड़ी आम चुनाव और कुछ तो विधानसभा चुनाव तक हार गए हैं, अब इनमें से ज्यादातर राज्यसभा जाने के जुगाड़ में लगे हुए हैं। इस सूची में ज्योतिरादित्य सिंधिया, मिलिंद देवड़ा, राजीव सातव से लेकर रणदीप सिंह सुरजेवाला तक शामिल हैं।

गौरतलब है कि मार्च-अप्रैल में कांग्रेस शासित प्रदेश राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कुल 8 सीटें खाली हो रही हैं। राजस्थान एवं मध्य प्रदेश में तीन-तीन और छत्तीसगढ़ में दो सीटें हैं। इनमें से 5 सीटें हर हाल में कांग्रेस के खाते में जाएंगी। वहीं महाराष्ट्र में सात और झारखंड में दो सीटें खाली हो रही हैं, यहां कांग्रेस साझा सरकार की भूमिका में हैं। ऐसे में महाराष्ट्र में कांग्रेस एक, बहुत ज्यादा करें तो दो सीटें जबकि झारखंड में अगर हेमंत सोरेन सरकार चाहे तो एक सीट कांग्रेस को मिल सकती है। हरियाणा की दो में एक पर और उत्तर प्रदेश की खाली हो रहीं 10 में से भी एक सीट कांग्रेस के नाम होना पक्का है।

बात करें राजस्थान की तो यहां राज्यसभा के लिए खाली होने वाली तीनों सीटों पर अभी उम्मीदवार तय नहीं है, लेकिन चर्चाओं में यहां से अविनाश पांडे, भंवर जितेंद्र सिंह और मुकुल वासनिक, गुलाम नबी सहित 7-8 का नाम मीडिया में बताया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश की तीन में से दो सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया और वर्तमान सांसद दिग्विजय सिंह का राज्यसभा जाना करीब-करीब पक्का माना जा रहा है। ऐसे ही हरियाणा की दो में से एक सीट से कुमारी शैलजा के फिर से उच्च सदन में जाना पूर्ण रूपेण पक्का है।

जानकारों की मानें तो इन सभी के बीच रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कि हाल ही में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में कैथल से अपनी सीट न बचा सके थे, भी राज्यसभा जाने के इच्छुक बताए जा रहे हैं। यही वजह है कि सुरजेवाला अपने लिए भूमि तलाशने में लगे हैं, क्योंकि हरियाणा की कुल 5 राज्यसभा सीटों में से केवल 2 सीटें खाली हो रही हैं। ऐसे में 2 में से बमुश्किल अगर कांग्रेस के खाते में 1 सीट आ भी जाती है तो उस पर कुमारी शैलजा का नाम करीब-करीब फाइनल होने के चलते उनका यहां काम नहीं बनेगा। वहीं महाराष्ट्र में भी उनके भूमि तलाशने का कोई औचित्य नहीं है। मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में पहले ही वर्चस्व की लड़ाई चरम पर है और वहां के कांग्रेस नेताओं का नंबर लग जाए तो वो ही बड़ी बात होगी। ऐसे में रणदीप सुरजेवाला की नजर अब राजस्थान पर है।

बता दें, सुरजेवाला पूर्व और भविष्य के कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के काफी नजदीक हैं और अगर राहुल गांधी कहेंगे तो यहां के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राहुल गांधी की बात टालेंगे नहीं, ये भी पक्का है। बता दें, राजस्थान से राज्यसभा की इस साल खाली होने वाली 3 में से 2 सीटों का कांग्रेस के खाते में आना पक्का है। वर्तमान में यहां की 10 में से 9 सीटों पर भाजपा के **सांसद काबिज** हैं, वहीं भाजपा के मदन लाल सैनी के निधन के बाद खाली हुई सीट पर हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का चयन हुआ है।

युवा नेतृत्व को उभारने की कवायद हुई तेज

देशभर में कांग्रेस में जिस तरह राज्यसभा में भेजे जाने वाले चेहरे सामने आ रहे हैं उसमें अधिकांश वे नेता हैं, जिन्हें राहुल गांधी का करीबी माना जाता है। अगर उन नामों को राज्यसभा में भेजा जाता है तो निश्चित तौर पर यहां कांग्रेस की आवाज प्रबल होगी। संख्या बल के मुताबिक नहीं बल्कि युवा चेहरों के अनुसार। देखा जाए तो राजस्थान सीट से वरिष्ठ नेता डॉ. मनमोहन सिंह उच्च सदन में हैं जो दो बार देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। लेकिन बढ़ती आयु के चलते उनकी आवाज सदन में उतनी प्रबल नहीं है। ऐसे में राज्यसभा में युवा शक्ति ढलती कांग्रेस की आवाज को न केवल मुखर कर सकती है बल्कि सदन में अपनी बातों को प्रबलता से रख भी सकती है। पार्टी सूत्रों का कहना है कि पिछले कई दशकों से पार्टी में बुजुर्ग नेताओं का वर्चस्व रहा है। इसलिए यह कोशिश की जा रही है कि पार्टी में युवा नेतृत्व को आगे किया जाए। इससे पार्टी में नए जोश और नई सोच का संचार होगा।

राजस्थान में राज्यसभा की 3 सीटों के लिए कांग्रेस से अविनाश पांडे, मुकुल वासनिक, भंवर जितेंद्र सिंह, प्रियंका गांधी, गुलाम नबी आजाद, गौरव वल्लभ और रामेश्वर डूडी तक के नाम मीडिया की सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन इन सभी नामों में एक नाम भी ऐसा नहीं है जिसको रणदीप सुरजेवाला के नाम के साथ रिप्लेस नहीं किया जा सकता हो, और वो भी तब जबकि सुरजेवाला के लिए राहुल गांधी निर्देश दें। वहीं मध्यप्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के नाम के साथ छेड़छाड़ एक दम से नहीं की जा सकती है। दोनों के नामों पर मुख्यमंत्री कमलनाथ की हामी भी हो चुकी है। ऐसे में यहां किसी और के नाम की गुंजाइश नहीं बचती। ऐसे ही महाराष्ट्र में मिलिंद देवड़ा की नाराजगी को दूर करना भी जरूरी है। ऐसे में राजस्थान ही सुरक्षित प्रदेश है जहां किसी का भी नाम कटे, विरोध होने की संभावना ना के बराबर है।

अब बात करें उत्तर प्रदेश की तो यहां जितिन प्रसाद का नाम कांग्रेस के दावेदारों में सामने आ रहा है। जितिन प्रसाद के बारे में तो ये भी कहा जा रहा है कि अगर उन्हें कांग्रेस की ओर से राज्यसभा का उम्मीदवार नहीं बनाया गया तो वे भाजपा में शामिल हो सकते हैं। यहां से उन्हें आसानी से उच्च सदन में भेजा जा सकेगा। छत्तीसगढ़ से पुराने नेताओं की ही दावेदारी प्रबल है। वहीं महाराष्ट्र से राहुल गांधी के दो करीबी नेता मिलिंद देवड़ा और राजीव सातव **कड़े जुगाड़** में लगे हुए हैं ताकि अगले पांच साल आराम से राज्यसभा की कुर्सियों पर बैठकर निकाले जा सकें। बता दें, राजीव सातव गुजरात के प्रभारी भी हैं और राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं। यहीं से रजनी पाटिल, मुकुल वासनिक और राजीव शुक्ला भी दावेदारी में लगे हुए हैं।

वहीं झारखंड की एक सीट पर अगर कांग्रेस को मौका मिलता है तो यहां से प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी आरपीएन सिंह को राज्यसभा भेजा जा सकता है। वे युवा नेता हैं और राहुल गांधी के करीबी भी। ऐसे में उन्हें अन्य नेताओं पर वरीयता मिल सकती है। हालांकि यहां झामुमो और कांग्रेस में सीट को लेकर तनातनी होना निश्चित है लेकिन स्थानीय नेताओं ने जिस तरह आरपीएन सिंह को विश्वास दिलाया है, उससे तो यही लग रहा है कि वे झारखंड जीत ही लेंगे।

● **इन्द्र कुमार**

लाचार भाजपा

हार का ठीकरा कांग्रेस के सिर

वरिष्ठ भाजपा नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने माना कि हाल में राज्य में संपन्न हुए पंचायत चुनावों के नतीजे उनके पार्टी की उम्मीद के अनुरूप नही हैं लेकिन इसका ठीकरा उन्होंने सत्ताधारी दल पर फोड़ा। कौशिक ने कहा, 'कांग्रेस ने सत्ता का दुरुपयोग किया है, जैसे तमाम लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को धता बताकर, डरा धमकाकर, प्रशासनिक दुरुपयोग कर अध्यक्षों का चुनाव कराया है।' वे आगे कहते हैं, 'सत्तारूढ़ दल के नेताओं ने चुने हुए शासकीय कर्मचारी, परिवार या व्यवसाय से जुड़े जिला और जनपद पंचायत सदस्यों का भयादोहन किया है लेकिन उसके बावजूद भाजपा समर्थित प्रत्याशी बड़ी संख्या में जीतकर आए हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेसी कुनीतियों और सत्ता के दुरुपयोग का अपना ही कांग्रेसी रिकार्ड तोड़ देने के बावजूद जिला एवं जनपद पंचायतों सदस्यों के चुनाव में लगभग आधी सीटों पर कब्जा करने में भाजपा समर्थित प्रत्याशी 'सफल' रहे हैं। कौशिक के अनुसार जिला पंचायतों में 170 से अधिक सीटों पर और जनपद पंचायतों में 1300 भाजपा समर्थित प्रत्याशी जीते हैं।

पिछले एक साल से राज्य स्तरीय चुनावों में भाजपा की हार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हार की इस कड़ी में राज्य में 15 साल शासन कर चुकी भाजपा को एक और झटका 3 फरवरी को संपन्न हुए पंचायत चुनाव के नतीजों ने दिया है। राज्य में 145 जनपद और 27 जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए हुए चुनाव के नतीजों से भाजपा की साख एक बार फिर उस वक्त कमजोर हुई जब कांग्रेस समर्थित प्रत्याशी करीब 75 प्रतिशत ग्रामीण निकायों में अपना कब्जा जमाने में कामयाब रहे। इसे भाजपा की लाचारी कहें या फिर चुनावी जीत के लिए इच्छाशक्ति की कमी या लगातार मिल रही हार से पार्टी के नेताओं का पस्त होता हौंसला। ज्ञात हो कि कई पंचायतें ऐसी थी जहां भाजपा के जीते हुए सदस्यों की संख्या ज्यादा थी लेकिन जीत कांग्रेस प्रत्याशियों के हाथ लगी। छिटपुट हिंसक घटनाओं के बीच सत्ताधारी पार्टी को यह भारी भरकम जीत 110 जनपद और 20 जिला पंचायतों में मिली है। वहीं भाजपा समर्थित उम्मीदवार महज 34 जनपद और सात जिला पंचायतों पर अपना कब्जा जमाने में कामयाब रहे।

भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस की जीत भूपेश बघेल सरकार द्वारा अपनाई गई अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग, पंचायत सदस्यों की खरीद फरोख्त और उन्हें डरा धमकाकर अपने कब्जे में लेकर जुटाए गए बहुमत से हुई है। वहीं कांग्रेस ने इस आरोप को भाजपा की शर्मनाक हार से हो रही फजीहत से बचने का एक सहारा बताया है। कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि पिछले 14 महीनों में बघेल सरकार द्वारा किए गए कार्यों के कारण ही सत्तारूढ़ दल को इस दौरान हुए सभी राज्यस्तरीय चुनावों में लगातार जीत हासिल हुई है। पार्टी का यह भी कहना है कि भाजपा के आरोप 'निराधार' हैं क्योंकि नगरीय निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद उनके नेताओं ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए जनता में भ्रम फैलाने का प्रयास किया और साथ ही यह दावा किया कि उन्हें पंचायत चुनावों में भारी सफलता मिलने जा रही है।

कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि कई जनपदों में तो भाजपा के बड़े नेताओं ने पार्टी द्वारा समर्थित सदस्यों की संख्या अच्छी तादात में होने के बावजूद भी मेहनत करना उचित नहीं समझा और नतीजा कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में गया। पीसीसी अध्यक्ष और पार्टी विधायक मोहन मरकाम ने कहा 'पहले नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस की एक तरफा जीत हुई और अब ग्रामीण मतदाताओं ने भी 27 में 20 जिला पंचायत में कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजयी बनाया हैं। राज्य के 145 जनपद पंचायत के चुनाव हुए जिनमें 110 में कांग्रेस को जीत मिली है। यह जीत छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली 14 महीने की सरकार के कार्यक्रमों और कांग्रेस पार्टी की नीतियों पर ग्रामीण जनता की भी मुहर है।' मरकाम ने आरोप लगाया कि भाजपा किसानों के नाम पर प्रोपेगेंडा करती है, दुष्प्रचार करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी भाजपा पर जनता ने विश्वास नहीं किया।

पंचायत चुनावों में भाजपा की हार के लिए पार्टी के बड़े नेता भी दोषी माने जा रहे हैं। जनपद और जिला पंचायत दोनों ही चुनावों में भाजपा के बड़े नेता जिन्हें पार्टी ने 15 सालों तक शासन करने का मौका दिया गंभीर नहीं दिखे। स्वयं भाजपा के नेता यह मानते हैं कि यदि बड़े नेताओं ने गंभीरता दिखाई होती तो पार्टी के कब्जे में इससे कहीं ज्यादा ग्रामीण निकायों पर अपना कब्जा जमा सकती थी।

भाजपा की हार को लेकर कुछ इसी प्रकार की धारणा कांग्रेस के नेताओं में भी है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर बताया कि 2020 के चुनाव में ऐसी कई जनपद पंचायतें थी जहां भाजपा समर्थित सदस्यों की संख्या कांग्रेस की अपेक्षा काफी ज्यादा थी लेकिन विपक्षी दल के नेताओं की सक्रियता और नेतृत्व के संग्रक्षण के अभाव में उसके चुने हुए सदस्यों ने कांग्रेस प्रत्याशियों का साथ दिया।

कांग्रेस के नेता और पार्टी के धरसीवां विधानसभा सीट में पड़ने वाली पंचायतों के कॉर्डिनेटर संजय ठाकुर कहते हैं, 'लगता है भाजपा के नेताओं ने अपनी हार चुनाव से पहले ही मान ली थी। विपक्ष का कोई बड़ा नेता पंचायत चुनावों में सक्रिय नहीं दिखा जिससे यह कहा जा सके कि भाजपा चुनावी संघर्ष में है।'

● **रायपुर से टीपी सिंह**

प्रदेश में वैसे तो मुख्यमंत्री स्वयं योगी हैं, लेकिन इस बार उन्होंने बजट में मंदिरों के रखरखाव और विकास पर मोटी राशि का प्रावधान कर यह दर्शा दिया है कि वे कितने धार्मिक हैं।

मंदिरों पर मेहरबानी

उत्तर प्रदेश विधानसभा में वर्ष 2020-21 के लिए 5,12,860.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन में बजट पेश करते हुए जानकारी दी कि बजट में 10,967.80 करोड़ रुपए की नई योजनाओं का प्रावधान किया गया है। बजट में धार्मिक स्थलों पर विशेष ध्यान दिया गया है। अयोध्या में उच्च स्तरीय पर्यटक अवस्थापना सुविधाओं के विकास के लिए 85 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं अयोध्या हवाई अड्डे के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रस्तावित हैं।

वाराणसी में संस्कृति केंद्र की स्थापना के लिए बजट में 180 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा गोरखपुर के रामगढ़ ताल में वाटर स्पोर्ट्स के लिए 25 करोड़ रुपए, वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए 200 करोड़ रुपए का भी प्रावधान किया गया है। खन्ना ने कहा कि मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। बजट में कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड़ रुपए, आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड़ रुपए तथा गोरखपुर और अन्य शहरों की मेट्रो के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रस्तावित किए गए हैं।

उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने राज्य की योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा विधानसभा में पेश आम बजट को आंकड़ों की बाजीगरी बताते हुए इसे प्रदेश के किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों के जले पर नमक छिड़कने जैसा करार दिया है। लल्लू ने बजट पर प्रतिक्रिया में कहा कि 450 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य देने की घोषणा करके सत्ता में आने वाली भाजपा तीन वर्षों में मात्र गन्ने के मूल्य में 10 रुपए की ही वृद्धि कर पाई है। उन्होंने कहा कि युवा बेरोजगारों की तादात पिछले दो वर्षों में 12.5 लाख बढ़ गई, लेकिन उनके लिए नए रोजगार देने के बजाय बजट में सेवानिवृत्त शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में नौकरी देने की घोषणा बेरोजगार युवाओं के साथ विश्वासघात है। वहीं कौशल विकास योजना भी छलावा साबित हुई।

लल्लू ने 18 मंडलों में अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना की घोषणा को भी झूठ का पुलिंदा करार देते हुए इसे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी द्वारा शुरू किए गए नवोदय विद्यालयों को खत्म करने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि कृषि पर लागत कम करने, खाद, बीज, पानी, कृषि यंत्र, कीटनाशक, बिजली वगैरह के दामों में कमी का कोई प्रावधान बजट में नहीं किया गया है जबकि पिछले तीन वर्षों में अनिवार्य कृषि उपयोग की इन चीजों के दामों में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हो चुकी है। इसके मुकाबले किसानों के उपज मूल्य में की गई बढ़ोत्तरी नगण्य है। लल्लू ने कहा कि शिक्षा मित्र, आंगनबाड़ी, रसोइया, आशा बहू, रोजगार सेवक, चौकीदार, होमगार्ड, अनुदेशक एवं मदरसा शिक्षकों के लिए बजट में कुछ भी नहीं है जो अत्यंत निराशाजनक है। समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश सरकार के बजट को 'पुरानी बोतल में नया पानी' करार दिया और कहा कि इस बजट में प्रदेश के किसानों, छात्रों, युवाओं, महिलाओं और आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है। बजट के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता समाजवादी पार्टी के राम गोविंद चौधरी ने कहा कि यह बजट गरीब विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, पिछड़ा वर्ग विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी, दलित विरोधी, महिला विरोधी, नौजवान विरोधी है।

उन्होंने कहा, राज्य की वास्तविक स्थिति यह है कि प्यार, दया के हंसते हुए माहौल को खराब कर दिया गया है। 5,12,860.72 करोड़ रुपए का इनका बजट है, पुरानी बोतल में नए पानी को रखा गया है। पिछले बजट के पैसों का क्या हुआ यह इन्होंने कुछ बताया नहीं और इस बजट में केवल अनुमान है। इस बजट से समाज के किसी वर्ग को कोई फायदा नहीं होगा। किसी भी तबके का कोई हित नहीं है। उन्होंने कहा कि यह बजट दिशाहीन है और जनता के खिलाफ है।

बसपा की अध्यक्ष मायावती ने बजट को जनता की अपेक्षाओं के साथ छलावा बताते हुए कहा है कि बजट में सरकार ने जो बड़े-बड़े वादे और दावे किए हैं वे पूरी तरह से खोखले हैं। राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए ट्वीट कर कहा, 'उप्र सरकार का विधानसभा में पेश बजट जनता की आशाओं व आकांक्षाओं के साथ छलावा है। इस बजट से प्रदेश का विकास और यहां की 22 करोड़ जनता का हित एवं कल्याण संभव नहीं है।' उन्होंने कहा, 'यही बुरा हाल इनके (योगी सरकार) पिछले बजटों का भी रहा है, जो जनहित एवं जनकल्याण के मामले में भाजपा की कमजोर इच्छाशक्ति का परिणाम है।'

● **लखनऊ से मधु आलोक निगम**

अंकोरवाट की तर्ज पर अयोध्या में इक्ष्वकुपुरी

अयोध्या विवाद के अंत के बाद अब योगी आदित्यनाथ की योजना इस धर्मनगरी को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल बनाने की है। इसके लिए योगी सरकार अयोध्या में कंबोडिया के अंकोरवाट की तर्ज पर नई नगरी बसाएगी। इक्ष्वकुपुरी के नाम से बसाए जाने वाले इस क्षेत्र से अयोध्या में न केवल अंतरराष्ट्रीय बल्कि उच्च वर्ग के देशी पर्यटकों को भी आकर्षित करने की योजना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ड्रीम प्रोजेक्ट माने जा रहे इक्ष्वकुपुरी के निर्माण के बाद पर्यटन की दृष्टि से यह लोगों की सबसे पसंदीदा जगह बनेगी। प्रदेश सरकार का मानना है कि अध्यात्म और पर्यटन के अनूठे आकर्षण वाली इक्ष्वकुपुरी से अयोध्या में न केवल व्यावसायिक गतिविधियां बढ़ेंगी बल्कि रोजगार के नए अवसर खुलेंगे।

सीधी जंग की सियासत

पिछले विधानसभा चुनावों में वसुंधरा राजे को कमान सौंपने के मामले में भाजपा नेतृत्व का तुजुर्बा काफी कसैला रहा था। बावजूद अजमेर और जयपुर में आयोजित संघ के चिंतन शिविरों में राजे के विकल्प का मुद्दा काफी कसमसाता रहा। लेकिन भाजपा नेतृत्व ने पारम्परिक सुल्तान को ही इस तर्क के साथ कमान सौंपना बेहतर समझा कि राजे-शाह का गठजोड़ प्रदेश में भाजपा को फिर से सत्ता में ला सकता है। लेकिन चुनावी **नतीजे झिंझोड़** कर बता गए कि वसुंधरा राजे मोदी मॉडल की सबसे कमजोर कड़ी थी। इसके कसैले सबक के बाद ही संघ के पदाधिकारी उन सूरमाओं पर टकटकी लगाए हुए थे, जो पार्टी को संवारकर फिर से सत्ता का राजमुकुट पहना सके।

शताब्दी वर्ष की तरफ तेजी से बढ़ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सत्ता में सीधी धमक के दस्ताने पहन लिए हैं। इन दिनों राजस्थान में जिस तरह भाजपा की राजनीति संघनिष्ठ संगठन मंत्री चंद्रशेखर के इर्द-गिर्द घूम रही है उसने संघ समर्थक विश्लेषक राकेश सिन्हा के इस तर्क पर मुहर लगा दी है कि 'वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सत्ता में सीधा दखल न सिर्फ संघ की विवशता है। बल्कि समय की मांग और अनिवार्यता भी है।' राजनीतिक विश्लेषकों ने उन्हें सियासी खेल का धुरंधर और कामयाबी की चाबी मानते हुए ऐसा हुनरमंद माना है, जो प्रदेश में भाजपा को सत्ता के गलियारों में ले जा सकता है।

सूत्रों का कहना है कि पांच राज्यों में सत्ता के घाट पर फिसल चुका भाजपा नेतृत्व भी अब यह मानने लगा है कि राज्यों के चुनावों में राष्ट्रीय मुद्दों की बजाय क्षेत्रीय मुद्दों और स्थानीय चेहरों पर दांव खेला जाना चाहिए। विश्लेषकों का कहना है कि अब नए सियासी महामंथन के बाद अगर संघ खुलकर सत्ता के संघर्ष की दहलीज पर कदम रखने जा रहा है, तो देखना ज़्यादा दिलचस्प होगा। खासकर संघ प्रमुख भागवत के उस बयान के बाद कि 'केवल राजनीति देश में परिवर्तन नहीं ला सकती। परिवर्तन तो केवल लोगों के द्वारा ही लाया जा सकता है।' बहरहाल सूत्रों का कहना है कि अपने राजनीतिक कौशल की सबसे बड़ी परीक्षा देने के लिए संघ ने राजस्थान को चुना है। संघ प्रदेश में भाजपा को फिर से सत्ता में लाने के लिए कई मोर्चों पर काम कर रही है। सीएए को लेकर भाजपा के समर्थन अभियान से भी संघ सतुष्ट नहीं है। उसी का नतीजा है कि संघ ने संपर्क अभियान की बागडोर अपने हाथों में थाम ली है। संघ के कार्यकर्ता घर-घर जाकर लोगों को ऐसे पम्पलेट बांट रहे हैं, जो सीएए की अच्छाइयों का बखान करते नजर आते हैं।

राजनीतिक दक्षता के इस मुहाने पर अगर चंद्रशेखर खूबियों से लबरेज नजर आते हैं, तो इसकी बेशुमार वजहें हैं। सत्ता और संगठन में खम ठोककर तालमेल का मसौदा पढ़ने वाले चंद्रशेखर ने विस्तारक योजना जैसे कार्यक्रम चलाए और संगठन को मजबूती देने के लिए 50 लाख सदस्य जोड़े हैं। विधानसभा और लोकसभा चुनावों में संभाग स्तर पर प्रभारी बनाए गए। पदाधिकारियों को संगठनात्मक कामकाज का बंटवारा किया। चंद्रशेखर यही पद वाराणसी में भी 2014 में संभाल चुके हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां से संसदीय चुनाव लड़ा था। विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा 29 साल में पहली बार हुआ जब किसी संगठन महामंत्री की पकड़ को इतना मजबूत देखा गया। चंद्रशेखर ने बेशक अपने लिए कोई सुर्खियां बटोरने की कोशिश नहीं की। लेकिन उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि गिनी जाएगी कि वसुंधरा राजे की बुझती चमक के बीच सिर्फ चंद्रशेखर ही ऐसा नेता साबित हुए, जो महज ढाई साल में प्रदेश भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा बन गए।

करीब दो दशकों से राजस्थान में भाजपा की सियासत वसुंधरा राजे तक ही सीमित रही। इससे पहले भैरोसिंह शेखावत पार्टी के केंद्र बिंदु रहे। लेकिन प्रदेश संगठन महामंत्री के तौर पर चाहे ओम प्रकाश माथुर हो या प्रकाश चंद्र प्रदेश भाजपा में वैसा वर्चस्व कायम नहीं कर पाए? जैसा चंद्रशेखर ने किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के रूप में सतीश पूनिया की तैनाती समेत कई बदलावों में चंद्रशेखर का प्रभाव साफ नजर आता है।

● **जयपुर से आर.के. बिन्नानी**

महारानी पूरी तरह हासिए पर

संगठन मंत्री के पद को पार्टी और संघ के बीच महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है। बाद में राजे और पार्टी नेतृत्व के बीच टकराव के चलते यह पद 8 साल तक खाली ही रहा। लेकिन इस टकराव को दूर करने में चंद्रशेखर ही कामयाब रहे। सौरभ भट्ट कहते हैं कि अतीत से भविष्य का निर्माण तो संभव नहीं है। लेकिन चंद्रशेखर पर अगर संघ की नजरें गड़ी हैं, तो उन्हें अतीत ओर वर्तमान दोनों टटोलने होंगे। उधर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह अब भी राजे से मुंह फुलाए हुए हैं। पिछले दिनों नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में जोधपुर में हुई शाह की सभा से वसुंधरा राजे ने दूरी ही बनाए रखी। शाह की सभा के लिए शहर में लगाए गए पोस्टरों में भी वसुंधरा राजे की तस्वीर नदारद थी। सूत्रों का कहना था कि राजे को शाह के कार्यक्रम में आने का निमंत्रण ही नहीं दिया गया था। इससे पहले जयपुर में सीएए के समर्थन में रैली निकाली गई। भाजपा की सभा में राजे को आमंत्रित नहीं किया गया था। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राजे के लिए इससे बड़ा अप्रत्यक्ष संकेत क्या हो सकता है कि सीएए को लेकर 5 जनवरी को देश में लॉन्च किए गए संपर्क अभियान में भी उन्हें शामिल नहीं किया गया, जबकि इसमें शिवराज सिंह से लेकर रमन सिंह, रघुवरदास और देवेंद्र फडणवीस सरीखे सभी पूर्व मुख्यमंत्री शामिल थे।

राज्यसभा पर रार

महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास आघाडी की गठबंधन सरकार बनने के बाद कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में खींचतान जारी है। भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच हो या डाटा संशोधन कानून पर पर उद्धव ठाकरे का रुख या स्वतंत्र वीर सावरकर का मुद्दा हो, इन विषयों को लेकर तीनों ही दलों में कई बार मतभेद दिखा है। भीमा कोरेगांव हिंसा की जांच एनआईए को सौंपने का शरद पवार विरोध कर चुके हैं, तो वहीं एनसीपी और कांग्रेस के विपरीत उद्धव ठाकरे ने नागरिकता संशोधन कानून और एनपीआर का समर्थन किया है। आने वाले दिनों में यह मतभेद और गठबंधन सरकार में तनाव और भी ज्यादा देखने को मिल सकता है। अप्रैल महीने में महाराष्ट्र की 7 राज्यसभा सीटें खाली हो जाएंगी। इन 7 सीटों पर अपने-अपने दल से राज्यसभा सांसद भेजने के लिए सभी पार्टियां कोशिश कर रही हैं।

महाराष्ट्र में राज्यसभा की कुल 19 सीटें हैं। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 विधायकों वाली सदन में एक राज्यसभा सदस्य को चुनने के लिए 37 विधायकों के वोट की जरूरत होती है। इस वक्त महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के पास 105 विधायक हैं। भाजपा के 105 विधायक और अन्य छोटे दलों के विधायकों के साथ भाजपा 3 लोगों को राज्यसभा भेज सकती है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के 56 विधायक, एनसीपी के 54 विधायक, जबकि कांग्रेस के 44 विधायक हैं। इन तीनों दलों सहित छोटे दलों को मिलाकर बना महाराष्ट्र विकास आघाडी कुल 4 लोगों को राज्यसभा भेज सकता है। मौजूदा समीकरण के मुताबिक शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के 1-1 राज्यसभा सांसद होंगे लेकिन चौथा राज्यसभा सांसद महाराष्ट्र विकास आघाडी के किस दल का होगा इस पर खींचतान जारी है।

महाराष्ट्र की सात राज्यसभा सांसद जिनका कार्यकाल खत्म हो रहा है उसमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार, एनसीपी नेता माजिद मेमन, कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई, शिवसेना के राजकुमार धूत, आरपीआई के रामदास आठवले, भाजपा के अमर पंडित और भाजपा के समर्थन से राज्यसभा सांसद बने संजय काकडे हैं। एक तरफ जहां एनसीपी चाहती है कि राज्यसभा सांसद की चौथी सीट पर एनसीपी का नेता बैठे, वहीं कांग्रेस चाहती है कि चौथी सीट का उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी से हो क्योंकि कांग्रेस को महाराष्ट्र सरकार में कम साझेदारी मिली है। जबकि शिवसेना का कहना है कि चौथी सीट पर राज्यसभा सांसद कौन चुना जाएगा इसका फैसला महाराष्ट्र विकास आघाडी के नेताओं के बीच आम सहमति से बनेगा।

भाजपा अपने विधायकों के दम पर 3 लोगों को राज्यसभा में भेज सकती है। भाजपा अपने सहयोगी दल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता और केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले को एक बार फिर मौका दे सकती है। वहीं सातारा में हुए लोकसभा उपचुनाव में अपनी लोकसभा सीट गंवाने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज उदयनराजे भोसले को भाजपा राज्यसभा भेज सकती है। तीसरी सीट के लिए भाजपा किसी पार्टी के वरिष्ठ नेता को राज्यसभा भेज सकती है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक बार फिर राज्यसभा में अगले 6 साल के कार्यकाल के लिए दिख सकते हैं। वहीं कांग्रेस ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लगभग 1 साल पहले कांग्रेस छोड़कर शिवसेना से जुड़ने वाली प्रियंका चतुर्वेदी को शिवसेना अपने कोटे से राज्यसभा भेज सकती है।

राज्यसभा में इस साल विपक्षी ताकत के और कमजोर होने की संभावना है। इस वर्ष राज्यसभा की 68 सीटें खाली हो रही हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस को इसमें कई सीटें गंवानी पड़ सकती हैं। सूत्रों के मुताबिक, कई राज्यों में स्थिति कमजोर होने के चलते कांग्रेस इस साल खाली होने वाली अपनी 19 में से 9 सीटें गंवा सकती है। यह स्थिति तब है जब अटकलें है कि पार्टी प्रियंका गांधी वाड्रा, ज्योतिरादित्य सिंधिया और रणदीप सुरजेवाला सहित कुछ बड़े लोगों को उच्च सदन में लाने पर विचार कर रही है। कांग्रेस अपने दम पर 9 सीटों को बरकरार रखने और अपने सहयोगियों की मदद से एक या दो और सीटें जीतने को लेकर आश्वस्त है। पार्टी उन राज्यों में सीटें हासिल करने के लिए तैयार है, जहां वह सत्ता में है। इनमें छत्तीसगढ़, मध्यप्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक, अप्रैल, जून और नवंबर में 68 रिक्त सीटों को भरने के लिए चुनाव होने के बाद विपक्षी ताकत में कमी आएगी। इसके साथ ही एनडीए धीरे-धीरे ऊपरी सदन में बहुमत की ओर बढ़ सकता है। गौरतलब है कि अप्रैल में राज्यसभा की 51 सीटें, जून में 5, जुलाई में 1 और नवंबर में 11 सीटें रिक्त होनी हैं।

● **बिन्दु माथुर**

इन राज्यों से भी रिक्त हो रही सीटें

राज्यसभा में महाराष्ट्र से 6 सीटें रिक्त हो रही हैं, जिनमें एनसीपी प्रमुख शरद पवार की सीट भी शामिल है। इसके अलावा तमिलनाडु से भी 6 सीटें खाली हो रही हैं, जबकि पश्चिम बंगाल और बिहार से पांच-पांच और गुजरात, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश से चार-चार सीटें रिक्त होंगी। कांग्रेस राजस्थान से खाली हो रही राज्यसभा की तीन में से दो सीटें रख सकती है, जबकि मध्यप्रदेश से तीन में से दो, छत्तीसगढ़ से दो, महाराष्ट्र और कर्नाटक से एक-एक सीट जीत सकती है। पार्टी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मेघालय और असम से सीटें गंवाएगी। सत्तारूढ़ एनडीए के पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है और सरकार को उच्च सदन में महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करवाने के लिए अन्नाद्रमुक और बीजद जैसे मित्र दलों का समर्थन प्राप्त करना होता है। राज्यसभा में भाजपा के सबसे अधिक 82 सदस्य हैं और कांग्रेस के 46 सदस्य हैं। उच्च सदन की कुल क्षमता 245 है। राज्यसभा में 12 नामित सदस्य हैं, जिनमें से 8 भाजपा से जुड़े हैं।

नीतीश को कौन देगा टक्कर?

बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने हैं और यह चर्चा बिहार के सियासी हल्के में इन दिनों बड़ी तेज है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार को टक्कर देने वाला कौन है। स्थानीय मीडिया वेब पोर्टल पर इसको लेकर रिपोर्ट्स छाप रही है और सोशल मीडिया पर भी इससे जुड़े तमाम पोस्ट देखे जा सकते हैं। यह चर्चा यू हीं नहीं हो रही, इसके पीछे तमाम कारण हैं। पहला तो ये कि बिहार के विपक्षी गठबंधन में मुख्यमंत्री पद के चेहरे के नाम पर बहुत रार है।

महागठबंधन की सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी राजद ने पहले से अपना मुख्यमंत्री चेहरा घोषित तो कर दिया है, मगर दूसरी सबसे बड़ी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता तेजस्वी के नाम पर सहमति नहीं दे रहे हैं। वे कहते हैं कि यह बात महागठबंधन की को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में तय होगी कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। कांग्रेस की ही तरह का स्टैंड बिहार की दूसरी छोटी-बड़ी विपक्षी पार्टियों का भी है। हम पार्टी के जीतनराम मांझी कहते हैं कि 'को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से नहीं हुई है। मैंने यह बात दर्जनों बार राजद के लोगों को बोली, महागठबंधन की दूसरी बैठकों में इस मुद्दे को उठाया, मगर न जाने फिर भी राजद को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कराने में रूचि क्यों नहीं दिखा रहा है। ऐसे नहीं चल पाएगा।' उपेंद्र कुशवाहा और मुकेश सहनी भी यही बात कहते हैं। जहां तक बात लेफ्ट पार्टियों की है तो कन्हैया कुमार उनके चेहरे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी लेफ्ट पार्टियां महागठबंधन का हिस्सा नहीं थी।

कथित तौर पर बिहार में विपक्ष का चेहरा लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी हैं। बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता भी तेजस्वी ही हैं। मगर वो केवल इसलिए हैं क्योंकि वे सबसे बड़ी पार्टी के नेता हैं। ऐसे में सवाल है कि तेजस्वी यादव को-ऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक कराकर ये क्यों नहीं तय करा लेते हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? जानकार बताते हैं तेजस्वी यादव शायद कन्हैया कुमार से डर रहे हैं। इस वक्त और भी डर रहे हैं क्योंकि कन्हैया जो यात्रा कर रहे हैं, उसकी सभाओं में भीड़ जुट रही है। यह पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान भी देखा गया था जब लेफ्ट पार्टियों के नेताओं के कई बार कहने के बावजूद भी राजद ने बेगूसराय सीट से अपने उम्मीदवार तनवीर हसन को उतार दिया। उस समय भी ये चर्चा उठी थी कि तेजस्वी यादव ने ये फैसला कन्हैया कुमार से डरकर लिया है।

जहां तक बात चेहरे को लेकर कन्हैया के नाम की है, तो इस पर सहमति दूसरी सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस की भी लगती दिख रही है। इसकी वजह है कटिहार के कदवा विधानसभा से विधायक राज्य के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और बिहार कांग्रेस के थिंक टैंक माने जाने वाले शकील अहमद खां की कन्हैया के साथ उनकी यात्रा में मौजूदगी।

कन्हैया की मौजूदा चल रही यात्रा को कवर करते हुए ऐसा लगा मानो यात्रा का चेहरा केवल कन्हैया हैं, बाकी सभी चीजों का प्रबंधन और आयोजन शकील अहमद खां ही कराते हैं। मसलन स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय, यात्रा के ठहरने का प्रबंध, अधिक से अधिक मुसलमानों को जोड़ना वगैरह। कन्हैया की सभाओं में जो लोग जुटते हैं उनमें लेफ्ट पार्टियों के कोर वोटर्स भी शामिल होते हैं जो हमेशा हर रैली और सभा में पहुंचते हैं। लेकिन इस समय की सभाओं में एक बड़ा मुसलमान तबका आता है जो शकील अहमद खां के कारण आता है और सीएए-एनआरसी के कारण भी आता है। कांग्रेस को लगता है कि कन्हैया कुमार के साथ आने में कोई नुकसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो गठबंधन बनेगा उसमें वह सबसे बड़ी पार्टी होगी। कन्हैया कुमार केवल चेहरा होंगे। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर लड़ने की कांग्रेस की कामना भी इससे पूरी हो सकती है। कांग्रेस को कन्हैया के साथ आने में सबसे बड़ा फायदा यह है कि उसका जातिगत समीकरण भी नहीं बिगड़ेगा। केवल यादव वोट अलग होने का खतरा रहेगा। जो कुल वोटों का करीब 14 फीसदी है। लेकिन इसके बदले उसे लेफ्ट के कोर वोटर्स मिलेंगे। जाति के आधार पर बनी दूसरी छोटी पार्टियों का सहयोग मिलता रहेगा।

कांग्रेस को पता है कि राजद अब लालू यादव के समय वाला राजद नहीं रहा जो सभी विपक्षियों को जोड़ने के लिए धूरी का काम करते थे। और जहां तक बात राजद के कोर यादव वोटर्स का है तो वह अब पहले की तरह एकमुश्त नहीं रहा। यादवों के कई नेता हो चुके हैं जो मौजूदा राजद नेतृत्व को टक्कर भी देते हुए लगते हैं। हालांकि कांग्रेस को इससे मतलब नहीं कि राजद में क्या चल रहा है और यादवों के नेता कौन हैं, बल्कि उसका मकसद उस चेहरे को खड़ा करना है जो भाजपा-जदयू सरकार को टक्कर दे सके। तेजस्वी में उसकी तलाश पूरी होती नहीं दिख रही है इसलिए कन्हैया कुमार को वह नेता बना रही है। सीएए-एनआरसी ने कन्हैया के साथ मिलकर कांग्रेस को एक नई उम्मीद दिखाई है।

● **विनोद बक्सरी**

कन्हैया पर होगा कांग्रेस का दांव

कांग्रेस यह भी देख रही है कि कन्हैया के साथ उपेंद्र कुशवाहा और जीतनराम मांझी भी मंच शेयर कर रहे हैं। आखिर में सवाल यही रह जाता है कि कांग्रेस क्यों राजद जैसी बड़ी पार्टी को छोड़कर चुनाव में लेफ्ट के साथ जाएगी जिसका मुश्किल से बिहार में कोई वजूद बचा है? जवाब खुद कांग्रेस ही देती है। प्रदेश अध्यक्ष मदनमोहन झा कहते हैं, कन्हैया में क्या बुराई है? इसके पहले भी कांग्रेस को लेफ्ट का साथ मिला है। और हमारी पहली लड़ाई संघवाद से है, संविधान को बचाने के लिए है। एक बात तो जरूर है कि कन्हैया कुमार के छात्र राजनीति से मुख्य धारा की राजनीति में आने के साथ ही लेफ्ट की गतिविधियां बिहार में बढ़ गई हैं। कन्हैया के साथ आने से कांग्रेस के साथ न केवल लेफ्ट आएगा बल्कि हम, रालोसपा और वीआईपी जैसी छोटी पार्टियों का भी साथ मिलेगा। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह राजद का गठबंधन बनाने को लेकर रवैया है, उससे वे निराश दिखते हैं। राजद के नेता मानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में वो जरूरत पड़ने पर अकेले भी चुनाव लड़ने को तैयार हैं, लेकिन कन्हैया कुमार का समर्थन नहीं करेंगे।

चीन की फितरत

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में चीन के खिलाफ प्रस्ताव पास

तिब्बत के धार्मिक गुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी के मुद्दे को लेकर चीन और अमेरिका के बीच रिश्ते सामान्य नहीं हैं। दलाई लामा के उत्तराधिकारी को लेकर अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने तिब्बती नीति और समर्थन अधिनियम को सर्वसम्मति से पारित किया है। इसमें कहा गया है कि तिब्बत के धार्मिक नेता के चयन का अधिकार चीन सरकार के बजाय तिब्बतियों का है। इसका मकसद तिब्बत के समर्थन वाली नीति को मजबूत करना और हिमालय में बौद्ध क्षेत्र के प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित और सशक्त बनाना है, जो कई दशकों से चीन के नियंत्रण में रहा है। इस पूरे विषय पर चीन की तरफ से कहा गया था कि अमेरिका धार्मिक आजादी के नाम पर चीन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है। बता दें कि इससे पहले अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने तिब्बत में मानवाधिकारों और पर्यावरण संरक्षण के लिए वाशिंगटन के समर्थन को मजबूत करने वाले विधेयक को मंजूरी दी थी।

नोवेल कोरोना वायरस के प्रकोप से घिरे चीन ने एक बार फिर भारत के साथ एक शत्रुतापूर्ण मोर्चा खोल दिया है। बीजिंग ने अरुणाचल प्रदेश के स्थापना दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की यात्रा का दृढ़ता से विरोध किया है। चीन ने भारत को सीमा मुद्दे को पेचीदा करने के खिलाफ चेतावनी दी है। अरुणाचल प्रदेश 34 साल पहले 20 फरवरी को एक केंद्रशासित प्रदेश से पूर्ण राज्य बना था। यह क्षेत्र 1913-14 में ब्रिटिश भारत का हिस्सा था और औपचारिक रूप से तब शामिल किया गया था, जब 1938 में भारत और तिब्बत के बीच सीमा के तौर पर मैकमोहन रेखा स्थापित हुई थी। अरुणाचल प्रदेश को लेकर भारत की संप्रभुता को लेकर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गेंग शुआंग ने बीजिंग में मीडिया को बताया, चीनी सरकार ने तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को कभी मान्यता नहीं दी है और शाह की यात्रा का दृढ़ता से विरोध करते हैं।

दरअसल चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत क्षेत्र का एक हिस्सा मानता है। इसलिए वह प्रधानमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्रियों के अरुणाचल **प्रदेश के दौरे को** लेकर अपनी आपत्ति जताता रहा है। गृहमंत्री अमित शाह के अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर चीन ने जो ऐतराज जताया है, उसका कोई औचित्य नहीं है। चीन की यह पुरानी प्रवृत्ति है कि वह इस तरह की आपत्तियां दर्ज कराकर सिर्फ विवाद की दिशा में ही कदम बढ़ाता रहा है। गृहमंत्री अरुणाचल प्रदेश के 34वें स्थापना दिवस पर दो दिन के राज्य के दौरे पर गए थे और भारत-चीन सीमा पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत की थी। ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है जब चीन ने किसी भारतीय नेता के दौरे पर इस तरह की आपत्ति जाहिर की है। जब कभी कोई भारतीय नेता अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर जाता है तो चीन की ओर से इस तरह की आपत्ति आ जाती है।

भारत में अमेरिकी राजदूत रिचर्ड वर्मा के दौरे पर चीन ने ऐसे ही आंखें दिखाई थीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरुणाचल दौरे पर भी उसने ऐसा ही विरोध जताया था। भारत एक नहीं कई मौकों पर साफ कह चुका है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, और इसमें कहीं कोई किसी तरह का संशय नहीं होना चाहिए। ऐसे में चीन के इस विरोध का क्या कोई मतलब रह जाता है?

हमेशा की तरह इस बार भी भारत ने चीन को दो टूक जवाब देते हुए साफ कर दिया है कि अरुणाचल प्रदेश को लेकर उसे कोई गफलत नहीं रखनी चाहिए, अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और गृहमंत्री का वहां का दौरा सामान्य बात है। भारत के सभी नेता, केंद्रीय मंत्री, अधिकारी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर ठीक उसी तरह जाते हैं जैसे देश के दूसरे हिस्सों में। इसलिए किसी भी भारतीय की अरुणाचल प्रदेश यात्रा पर आपत्ति दर्ज कराने का उसे कोई अधिकार नहीं है।

भारत चीन सीमा साढ़े तीन हजार किलोमीटर लंबी है और चीन इसे लेकर दशकों से विवाद कर रहा है। वह तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश पर अपना अधिकार जताता रहा है। लेकिन यह देखने वाली बात है कि अरुणाचल प्रदेश पर वाकई उसका हक होता तो क्या वह अब तक चुप बैठता? पूरी दुनिया देख रही है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न राज्य है, वहां निर्वाचित सरकार है, देश के सारे कायदे-कानून, संविधान के प्रावधान वहां लागू होते हैं, भारत के निर्वाचन आयोग की देखरेख में विधानसभा होते हैं। इतना सबकुछ होते हुए भी अगर चीन अरुणाचल पर दावा करता है तो यह हास्यास्पद ही है। इससे उसकी विवादों को जन्म देने की नीयत ही सामने आती है।

सवाल यह है कि चीन भारत के खिलाफ आखिर कब तक इस तरह का रुख प्रदर्शित करता रहेगा। चीन का सीमा विवाद सिर्फ भारत से ही नहीं है, **जितने देशों से उसकी सीमाएं** लगती हैं, सभी जगह कोई न कोई विवाद बना हुआ है। इससे यह तो साफ है कि सीमा विवादों की आड़ में चीन पड़ोसी देशों के इलाकों में कब्जा करने की नीयत रखता है। लद्दाख के आसपास के इलाकों में चीनी सैनिकों की घुसपैठ की खबरें आती ही रहती हैं। डोकलाम में चीनी सैनिक जिस तरह से भारतीय सीमा में आकर कब्जे की कोशिशें करते रहे हैं, वह किसी से छिपा नहीं है। पिछले साल चीन ने अपने यहां छपे तीस हजार से ज्यादा उन नक्शों को नष्ट करवा दिया था जिसमें अरुणाचल प्रदेश और ताइवान को उसका हिस्सा नहीं बताया गया था।

भारतीय नेताओं की अरुणाचल प्रदेश की यात्रा को लेकर चीन का विरोध उकसावे की हरकत से ज्यादा कुछ नहीं है। वह अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न हिस्से के तौर पर मान्यता देता है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। बेहतर यही है कि चीन भारत के साथ रिश्ते बिगाड़ने के बजाय यह सोचे कि सीमा विवाद को कितनी शांति और तर्कसंगत तरीके से सुलझाया जा सकता है।

● **बिन्दु माथुर**

कारोबारी ट्रम्प की कूटनीतिक पारी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के भारत दौरे से कई उम्मीदें पाली गई थीं। इस दौरे पर दोनों देशों में कोई ट्रेड डील तो नहीं हुई, लेकिन भारी-भरकम डिफेंस डील जरूर मुकम्मल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रम्प के बीच निजी बातचीत की भी तमाम व्याख्याएं की गईं। जिससे यह बात निकलकर आई है कि आखिर ट्रम्प के इस दौरे से भारत को क्या हासिल हुआ। जानकारों का कहना है कि राष्ट्रपति ट्रम्प का यह चुनावी साल है। बड़े समझौते की उम्मीद नहीं थी, लेकिन बड़ी घोषणा की आस जरूर थी। कूटनीति के जानकर मान रहे हैं कि राष्ट्रपति ने इस मामले में निराश किया। अमेरिका के लिहाज से वह एक शानदार कूटनीतिक पारी खेलकर गए, लेकिन भारत के हित में उम्मीद के सिवा कुछ खास नहीं आया।

चीन का प्रभुत्व रोकने में भारत का सहयोग लेने, बढ़ाने की कूटनीतिक पारी भी खेल गए। अपनी प्रेस वार्ता में भारत आकर पाकिस्तान और प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना दोस्त बताया। वह भारत से पाकिस्तान को संदेश दे गए। विदेश मंत्रालय के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी का कहना है कि ट्रम्प ने एक चतुर कारोबारी नेता की पारी खेली। दो दिन के दौरे में वह हर कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी की जमकर तारीफ करते रहे। इसी की आड़ में उन्होंने अपने दौरे को सफल बनाने की कोशिश की। उम्मीद थी कि रक्षा प्रौद्योगिकी में साझा विकास की कोई घोषणा होगी। यह नहीं हो पाया। अपाचे हेलीकॉप्टर खरीद की प्रक्रिया चल रही थी। यह सौदा होना ही था और आगे बढ़ गया। 24 एमएच-60 रोमियो हेलीकॉप्टर भारतीय नौसेना को चाहिए। यह सौदा अब हो जाएगा। सेना के पूर्व मेजर जनरल का कहना है कि अमेरिका के साथ इस तरह का रक्षा सौदा बड़ी बात नहीं है। अब यह सौदा अमेरिका के हित में है। इसमें कोई तकनीकी हस्तांतरण या साझा डेवलपमेंट शामिल नहीं है।

अब भारत को दुनिया का हर देश अपना उत्तम हथियार देना चाहता है। रूस का एस-400 प्रतिरक्षी मिसाइल सिस्टम और इसके जवाब में अमेरिका का नासाम्स मिसाइल सिस्टम देने की पेशकश इसका उदाहरण है। सवाल हाई लेवेल की प्रौद्योगिकी में साझेदारी का है। सैन्य अफसर का कहना है कि भारत अमेरिका की फौज पहले से ही उच्च स्तरीय सैन्य अभ्यास कर रही हैं। इन सब क्षेत्र में कोई नई घोषणा नहीं हुई है। जो पहले से चल रहा है, वही आगे बढ़ा है। तेल और गैस के क्षेत्र में सहयोग भी संभावित था। राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहीं भी भारत की कमजोरी का फायदा नहीं उठाया है। यह भी बड़ा सहयोग है। कूटनीतिक जानकारों के अनुसार यह हमारे कूटनीतिक शिल्पकारों की बड़ी जीत है। ट्रम्प ने कश्मीर में मध्यस्थता के सवाल पर कहा कि भारत और पाकिस्तान सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। दोनों आपस में मामला सुलझा लेंगे। सीएए को राष्ट्रपति ट्रम्प ने भारत के आंतरिक मामले का तर्क मानते हुए कोई टिप्पणी नहीं की।

दिल्ली में **सांप्रदायिक तनाव** और हिंसा पर कोई टिप्पणी नहीं की। कुछ बोलने से बचे। भारत में मुसलमानों के साथ भेदभाव पर कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी से बात की। ईसाइयों के साथ भेदभाव पर भी बात की। प्रधानमंत्री ने उन्हें बताया कि वह धार्मिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं। इसके लिए प्रतिबद्ध हैं और कड़ी मेहनत कर रहे हैं। कुल मिलाकर वह भारत के **प्रयासों पर संतुष्टि** जाहिर करके गए हैं। उन्होंने भारत के रिकॉर्ड, विरासत, संस्कृति की सराहना की है। हालांकि सूत्र का कहना है अब से पहले भारत के आंतरिक मामलों पर इस तरह से शायद ही कभी सवाल उठा हो।

पाकिस्तान, अफगानिस्तान के फ्रंट पर हमारी चिंता बनी है। दक्षिण चीन सागर में अमेरिका हमारे साथ है, यह भी हमारे लिए पर्याप्त है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने हमारे प्रधानमंत्री के साथ रिश्ते को निजी स्तर तक ले जाने का संदेश दिया है। इससे भारत को काफी बल मिलेगा। कारोबारी लिहाज से कोई बड़ी घोषणा हो जाती या सहयोग के क्षेत्र में कुछ बड़ी घोषणा होती तो जरूर इसका अलग संदेश जाता। अमेरिका के साथ रहकर हमने काफी कुछ पाया है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहमति अन्य क्षेत्र में साझा सहयोग से काफी कुछ पहले से मिलता आ रहा है। राष्ट्रपति ट्रम्प के दौरे से यह परंपरा और मजबूत हुई है।

● **कुमार विनोद**

आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई का लिया संकल्प

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा बयान और फिर अपनी प्रेस कांफ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दोनों देशों के संबंधों और भारत से संबंधित मसलों पर जो कुछ कहा उससे यही रेखांकित हुआ कि वह भारत-अमेरिका के रिश्तों को एक नई ऊंचाई देने को तत्पर हैं। यही कारण रहा कि एक ओर जहां उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में भारत के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई, वहीं दूसरी ओर उन मसलों पर कोई प्रतिकूल टिप्पणी भी नहीं की जिन्हें नाजुक मान लिया गया था। सच तो यह है कि यह मान्यता भी मीडिया के एक खास हिस्से की ओर से गढ़ी गई थी और उसी के द्वारा यह माहौल बनाया गया था कि अमेरिकी राष्ट्रपति धार्मिक स्वतंत्रता, नागरिकता संशोधन कानून, कश्मीर आदि के मामले में भारत को सवालों से घेर सकते हैं। उन्होंने न केवल इस कृत्रिम माहौल को ध्वस्त किया, बल्कि साफ तौर पर कहा कि भारत में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून को उचित ही भारत का आंतरिक मामला करार दिया। इससे कुछ लोगों को निराशा हुई होगी, लेकिन सच तो यही है कि एक संप्रभु राष्ट्र होने के नाते भारत को भी अन्य देशों की तरह अपने नागरिकता कानून का निर्धारण करने का अधिकार है। इस कानून में संशोधन को लेकर देश के साथ विदेश में झूठ का एक पहाड़ अवश्य खड़ा किया गया है, लेकिन इससे यह सच्चाई बदलने वाली नहीं है कि यह कानून नागरिकता प्रदान करने का है, न कि छीनने का।

हम पुरातन से कहते आ रहे हैं महिलाएं पुरुषों से किसी भी मायने में कम नहीं हैं, लेकिन अभी तक कई मायनों में हम उन्हें अपने बराबर नहीं मानते हैं...

बराबरी का अधिकार

भारत की सेना में महिलाओं की भूमिका पर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला दिया है। महिलाओं की काबिलियत को पूरा समर्थन देते हुए, अदालत ने कहा कि सेना में स्थायी कमीशन हर महिला अधिकारी को मिलेगा, चाहे वो कितने भी वर्षों से सेवारत हों। इसके अलावा अदालत ने यह भी कहा कि महिलाओं को कमांड पोस्टिंग में भी तैनात किए जाने का पूरा हक है। जिस दौर में स्त्रियों ने अमूमन हर स्तर पर यह साबित किया है कि वे घर से लेकर दहलीज से बाहर किसी भी मोर्चे पर मुश्किल और जटिल हालात का बराबरी से सामना कर सकती हैं, उसमें उनकी क्षमताओं को कठघरे में करना अपने आप में बेहद अफसोसजनक पहलू है। खासतौर पर सैन्य महकमों में अलग-अलग भूमिकाओं में खुद को सौंपी गई ड्यूटी को महिलाओं ने जिस कुशलता से निभाया है, वह उनकी बहादुरी और काबिलियत का सबूत है। अगर केंद्र सरकार की इच्छा से सबकुछ होता तो शायद सेना में संघर्ष कर रही महिलाओं को फिर निराशा ही हाथ लगती। लेकिन गत दिनों सेना में महिलाओं की भूमिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया, वह आने वाले दिनों में एक बड़े और क्रांतिकारी बदलाव का वाहक बनेगा।

अदालत ने साफ लहजे में कहा कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आने वाली सभी महिला अफसर स्थायी कमीशन की हकदार होंगी। हालांकि युद्ध में सीधे लड़ने देने का फैसला सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार और सेना पर छोड़ दिया है और इसे नीतिगत मामला बताया है। मगर थलसेना में महिला अफसरों की कमांड पोस्टिंग पर रोक को बेतुका बताकर अदालत ने इसे बराबरी के अधिकारों के खिलाफ कहा।

गौरतलब है कि इस मुद्दे को लेकर महिलाएं लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रही थीं और पुरुष वर्चस्व के समांतर भेदभाव के खिलाफ बराबरी के अधिकार की मांग कर रही थीं। स्थायी कमीशन से लेकर यूनिट और कमान के नेतृत्व यानी कमांड पोस्टिंग को लेकर सरकार का रुख बेहद नकारात्मक था और अदालत में जिस तरह की दलीलें दी गईं, वे न केवल बेहद उथली थीं, बल्कि बराबरी के मूल्यों पर आधारित एक आधुनिक समाज की परिकल्पना के खिलाफ भी।

केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने कहा कि सरकार की दलीलें 'भेदभावपूर्ण' और परेशान करने वाली थीं और स्टीरियोटाइप पर आधारित थीं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि सैनिक महिला अधिकारियों के नेतृत्व में काम करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हैं। इस पर अदालत ने कहा कि लिंग के आधार पर आक्षेप करना महिलाओं की मर्यादा और देश का अपमान है। दो जजों की पीठ ने यह भी कहा कि महिलाओं की शारीरिक विशेषताओं का उनके अधिकारों से कोई संबंध नहीं है और इस तरह की सोच को बढ़ाने वाली मानसिकता अब बदलनी चाहिए।

अदालत ने सरकार को तीन महीने में फैसले को लागू करने के लिए कहा है। फैसले को सेना में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक बड़ी जीत माना जा रहा है। इस मामले में 2010 में ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि शार्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में भर्ती हुई महिलाएं भी पुरुषों की तरह स्थाई कमीशन की हकदार हैं। केंद्र ने इस फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक सुनवाई चल रही है तब तक फैसले को लागू करवाने के लिए कोई बलपूर्वक कदम नहीं उठाए जाएंगे।

● **ज्योत्सना अनूप यादव**

सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

अदालत ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं था कि हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग गई थी और केंद्र सरकार को तुरंत हाईकोर्ट के फैसले पर अमल करना चाहिए था। केंद्र सरकार ने हाईकोर्ट के फैसले के नौ साल बाद, फरवरी 2019 में एक अधिसूचना जारी की थी, जिसके तहत महिला सैन्य अधिकारियों को सेना के कुल 10 विभागों में स्थाई कमीशन देने की इजाजत दी गई थी। हालांकि यह सिर्फ उन महिला अधिकारियों के लिए था जो 14 से कम वर्षों से सेवा में हों। इसके अलावा यह इजाजत सिर्फ स्टाफ पोस्टिंग के लिए थी, कमांड पोस्टिंग के लिए नहीं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये दोनों ही प्रतिबंध हट गए हैं। फैसला देते वक्त अदालत ने एक महत्वपूर्ण बात और कही, कि यह एक दोषपूर्ण धारणा है कि महिलाएं पुरुषों से कमजोर हैं। इस निर्णय पर महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ने वालों ने अदालत की सराहना की है।

नाना पुराण निगमागम सम्मतं

श्रीरामचरित मानस भारतीय संस्कृति में एक विशेष स्थान रखता है। उत्तर भारत में रामायण के रूप में कई लोगों द्वारा प्रतिदिन पढ़ा जाता है। श्रीरामचरित मानस में इस ग्रन्थ के नायक को एक महाशक्ति के रूप में दर्शाया गया है जबकि महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण में श्रीराम को एक मानव के रूप में दिखाया गया है। तुलसी के प्रभु राम सर्वशक्तिमान होते हुए भी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। रामचरित मानस के बारे में कहा जाता है...

नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद् रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोह्यपि।

अत: यह विश्वास पूर्वक कहा जा सकता है कि गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज ने अपनी मौलिकता में और अपनी कल्पना शीलता में सृजन धर्मिता का निर्वहन किया है। हृदयस्थ श्रीराम भक्ति के आश्रय में तथा भूतभावन भगवान शिव की कृपा से तत्कालीन उपलब्ध भारतीय पारम्परिक संस्कृत साहित्य का आधार लेकर श्रीरामचरितमानस को भाषा बद्ध किया है। रामायण के सृजन में उन्हें शोध की सामग्री महर्षि वेदव्यास प्रणीत पुराण, गीता, उपनिषद् आदि साहित्य से प्राप्त हुई है। अस्तु:- श्रीरामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदासजी का बहुमूल्य 'शोध-ग्रन्थ' है, जिसकी संरचना देश, काल, परिस्थिति आधारित होते हुए भी कालजयी, सार्वभौमिक मृत्युञ्जयी साहित्य है।

इस ग्रंथ में रामायण को अच्छी तरह से चौपाईयों के माध्यम से बताया गया है किस तरह राम का जीवन रहा, कैसे महापुरुष बने। इसीलिए रामचरित मानस की हर एक चौपाई का मंत्र सिद्ध है जिन्हें सच्चे मन से पढ़ने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आपके अशुभ दिन चल रहे है। जिसके कारण आपको कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो इन मंत्रों के प्रभाव से आपके घर समृद्धि बनी रहेगी। यह मंत्र सिर्फ सुख के लिए ही नहीं है बल्कि बारिश न होने पर, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए हो या फिर ज्ञान प्राप्ति के लिए हो। इन मंत्रों का मनन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। रामायण के यह चौपाई मंत्र आपको रामायण कामधेनु की तरह मनोवांछित फल देते है।

विश्व में आज जितना साहित्य उपलब्ध है वह प्राचीन साहित्य के अनुक्रम में नूतन सृजन कहा जा सकता है। साहित्य का एक अर्थ यह भी है कि- 'वह विचारों का शब्दश: (शाब्दिक) संग्रह है।' मानव मस्तिष्क में विचार शताब्दियों से आकार ग्रहण करते रहे हैं क्योंकि मनुष्य चिंतनशील प्राणी है विचार शून्यता उसका स्वभाव (गुण) नहीं है। मानव मस्तिष्क में पारम्परिक विचारों की अनुगूंज बनी रहती है। देश, काल और परिस्थितिजन्य वह पारम्परिक वैचारिक अनुगूंज युगानुकल नए संदर्भ में प्रस्फुटित होकर नवीन साहित्य का आकार ग्रहणकर मनुष्यमात्र का मार्गदर्शक हो, मानवता के कल्याण में सहायक तत्व बनता है।

महात्मा कबीर एक अध्यात्म साधक थे, वे अपनी आध्यात्मिक साधना की अनुभूतियों के माध्यम से तर्क पूर्ण शैली में अपनी छोटी-छोटी क्षणिकाओं में भी गंभीर बात कह देते थे। भक्त हृदय सूरदासजी श्रीकृष्ण के सौन्दर्य, माधुर्य और वात्सल्यभाव के निरूपण में निरंतर निमग्न रहते थे। श्रीकृष्ण की रूप माधुरी का अनुभव भक्तों के हृदयों में करा देने में सूरदासजी सिद्धहस्त महापुरुष हैं। गुरुनानक देवजी ज्ञानी संत के साथ-साथ सामाजिक संघर्ष के दौर के अनुभवी संत होने के कारण परिस्थितिजन्य कर्त्तव्यबोध जागरण कराने वाले महापुरुष सिद्ध हुए। श्रीकृष्ण भक्ति में निरंतर निमग्ना श्रीकृष्णोपासिका मीराबाई तो भक्तिरस की रसधार में ऐसी डूबी कि 'मैं तो प्रेम दिवाणी मेरो दरद न जाणै कोय', 'मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।' इतना ही नहीं जित देखूं तित श्याममयी है की रसानुभूति से श्रीकृष्णमयी ही हो गई।

उपर्युक्त भक्तों ने जो कुछ भी कहा-गाया अथवा लिखा या इनके मुख से निकला वह कहीं किसी के द्वारा संगृहीत किया गया। वह एक विपुल व समृद्ध साहित्य के रूप में अक्षय निधि, विश्व धरोहर 'भक्ति साहित्य' हो गया। इसी क्रम में श्री गोस्वामी तुलसीदास कृत श्रीरामचरितमानस तो अनुपम साहित्य सिद्ध हुआ। उन्होंने 'श्रीरामचरितमानस' के विभिन्न स्थलों में अपने हृदयस्थ रामकथा रूपी बीज के पड़े रहने का भी उल्लेख किया है और श्रीराम कृपा के माध्यम से उसके अंकुरित होने का उल्लेख भी किया है। श्रीरामचरितमानस की रचना शैली में उन्होंने श्रीरामकथा सरिता के मूलोद्गम का भी संकेत करते हुए श्रीरामकथा परम्परा का भी स्मरण किया है। श्रीराम अनंत हैं तो श्रीराम कथा भी अनंत है 'हरि अनंत हरि कथा अनंता - कहहिं सुनहिं बहु विध सब संता।' श्रीरामचरितमानस में कथा का शुभारंभ भी जिज्ञासा से हुआ है 'श्रीराम कौन हैं?' यह प्रश्न शाश्वत तथा इस प्रश्न का उत्तर भी पारम्परिक है।

उपर्युक्त प्रश्नजन्य शाश्वत और उत्तरजन्य परम्परा अपने आरंभिक काल से अद्यावधि अक्षुण्ण और प्रासंगिक है। इसीलिए साहित्य मनीषी साहित्य को विचारों का, चिंतन का और जिज्ञासा का अनुगामी मानते आए हैं।

श्री गोस्वामी तुलसीदासजी ने रामचरितमानस के मंगलाचरण एवं मानस की आरंभिक भूमिका में तथा रामायणजी की आरती और अपनी अन्य साहित्यिक रचनाओं (जिसे हम तुलसी साहित्य के नाम से जानते हैं) में इस तथ्य का उल्लेख किया है कि श्रीरामचरितमानस मेरी परम्परा से प्राप्त धार्मिक, पौराणिक साहित्य पर आधारित श्रीरामकथा के रूप में शोध ग्रंथ है। मंगलाचरण का एक पद देखने से यह बहुत स्पष्ट हो जाता है।

रामचरितमानस में भगवान श्रीराम के चरित्र का चित्रण जितने प्रभावशाली तरीके से किया गया है, उतने ही प्रभावशाली तरीके से भगवान राम के माध्यम से जीवन को जीने का तरीका भी बताया गया है। रामचरितमानस में मनुष्य को बताया गया है कि जीवन को सफल और सुखी बनाना है तो राम को भजने के साथ ही सांसारिक व्यवहार का भी ध्यान रखना होगा। यानि रामचरितमानस में विभिन्न पहलुओं पर भी गौर किया गया है।

● ओम

माँ की ममता

भारत रिसर्च सेंटर के मशहूर वैज्ञानिक डॉ. रस्तोगी आज बेहद प्रसन्न नजर आ रहे थे। उन्होंने यंत्रचालित मानव के सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में तरह-तरह की भावनाएं डालने की तकनीक विकसित कर ली थी। दुनियाभर के वैज्ञानिक उनकी इस उपलब्धि का साक्षात्कार करने के लिए भारत रिसर्च सेंटर पर पधार चुके थे और अगले कुछ ही घंटों में उन्हें सबके सामने भावनाओं से युक्त उस मशीनी मानव का प्रदर्शन करना था।

सबके समक्ष प्रदर्शन से पहले उन्होंने एक मशीनी मानव को जिसे सिलिकॉन की मदद से एक महिला का रूप दिया गया था, नजदीक ही एक रोते हुए एक छोटे बच्चे को चुप कराने का आदेश दिया और उसे समझाया, यह तुम्हारा ही बच्चा है और तुम इसकी मां हो।

तत्काल ही वह मशीनी मानव आदेश का पालन करने में लग गया। किसी महिला की भांति उसे गोद में उठाकर चुप कराने का प्रयास करने लगी लेकिन बच्चा चुप होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लगभग पांच मिनट बाद ही डॉ. रस्तोगी की झुंझलाहट भरी आवाज गूंजी, क्या कर रही हो? नहीं चुप हो रहा तो उसको उठाकर पटक दो, उसकी आदत सुधर जाएगी।

मुड़कर उस मशीनी मानव ने रस्तोगी की तरफ देखा, उठी और अचानक बिजली की तेजी से एक झन्नाटेदार थप्पड़ रस्तोगी की गाल पर रसीद करते हुए बोली, क्या तुझे तेरी मां ने इसी तरह चुप कराया था?

थप्पड़ से लाल अपने गालों को सहलाते हुए रस्तोगी की आंखों में आंसू आ गए थे, खुशी के आंसू।

— राजकुमार कांदु

संदेश बिना आ जाओगे

जब गीत बुलाएंगे मेरे,
तुम खुद को रोक न पाओगे
संदेश बिना आ जाओगे।
प्रेमी मन का जब गठबंधन,
इक-दूजे से हो जाता है
उठती है उर में हूक कहीं,
प्रियतम जब कोई बुलाता है
ये तो वाणी है रुहों की,
कानों से ना सुन पाओगे।
संदेश बिना आ जाओगे।
दुनिया कहती है गीत जिन्हें,
मेरे अनुराग की सरिता है
इसकी धाराएं और पनघट,
प्रेमी उर का घट भरता है
मेरी गंगा के अमृत को,
बिन चखे ही क्या रह जाओगे?
संदेश बिना आ जाओगे।
आकाश-क्षितिज की सीमाएं,
इनको तो रोक न पाती है
नारायण के कानों तक भी,
आवाज प्यार की जाती है
फिर तुम तो हो भगवान मेरे,
क्या मुझको यूं तड़पाओगे?
संदेश बिना आ जाओगे।

— शरद सुनेरी

वह भूखी होगी

अरे आज लंच ब्रेक में छुट्टी लेकर घर जा रहे हो!

हाँ यार...आज टिफिन लाना भूल गया।

तो आओ 'आज मेरे साथ खाना खालो... मैंने तेरी पसंद के रेस्टोरेंट से ही मंगाया है 'आ जा' रमेश खाना प्लेट मे सर्व करते हुए बोला।

नहीं यार वो क्या है न कि आजकल तेरी भाभी से गृहयुद्ध चल रहा है ऐसे में उसे लगेगा कि मैंने कुछ नहीं खाया... और जब तक मैं न खा लूं वह भी भूखी रहती है।

हाथ का निवाला हाथ में ही रह गया रमेश के... आज अपनी पत्नी से लड़कर टिफिन भी नहीं लाया था, यह कहकर कि बाहर खा लूंगा।

चल मैं भी छुट्टी लेकर जाता हूं रमेश बोला!

अरे तुम क्यों?

क्योंकि आज मैं भी टिफिन नहीं लाया!

ओहहह! कहकर दोनों हंस दिए।

— रजनी चतुर्वेदी
(विलगैयां)

पुरूष चित महिलाएं हिट

इस समय भारतीय पुरूष क्रिकेट टीम न्यूजीलैंड के दौरे पर है और पहले वनडे सीरीज फिर टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को चित कर दिया है। वहीं टी-20 महिला वर्ल्ड कप में भारतीय महिला टीम हिट पर हिट दे रही है। लगातार दो मैच जीतने के बाद तीसरे मैच में भी न्यूजीलैंड को 4 रन से हराकर टीम इंडिया वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसी के साथ टीम इंडिया चौथी बार वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंची है। इससे पहले भारत ने 2009, 2010 और 2018 में सेमीफाइनल तक का सफर तय किया था। इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की यह लगातार तीसरी जीत है। टीम इंडिया ने पहले ऑस्ट्रेलिया, फिर बांग्लादेश और अब न्यूजीलैंड को चारों खाने चित कर दिया है।

मेलबर्न के **जक्शल** ओवल ग्राउंड पर खेले गए इस मुकाबले में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 4 रनों से शिकस्त दी। कीवी टीम को मैच जीतने के लिए 134 रनों की दरकार थी लेकिन वह 5 विकेट पर 130 रन बना सकी। न्यूजीलैंड की तरफ से सबसे अधिक 34 रन एमिलिया केर ने बनाए। भारत की ओर से सभी गेंदबाजो ने बेहतरीन बॉलिंग की। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में टीम इंडिया **महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप** 2020 में अजेय रही हैं। भारतीय महिला टीम लगातार दूसरी बार टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने में सफल रही। इससे पहले टीम इंडिया 2018 में वेस्टइंडीज में खेले गए टी-20 महिला वर्ल्ड कप में अंतिम चार में पहुंची थी। जहां तक महिला टी-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 की बात है तो भारत का सफर शानदार रहा है। टीम इंडिया लगातार इस वर्ल्ड कप में अब तक तीन मैच जीत चुकी है। किसी भी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए तीन मैच जीतने जरूरी हैं। भारत 6 अंकों के साथ ग्रुप-ए में शीर्ष पर है। इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश को हरा चुकी है। न्यूजीलैंड के विरुद्ध खेले गए मैच में जब टीम इंडिया ने अपनी पारी में 8 विकेट पर 133 रन बनाए तो ऐसा लगा कि भारत का वर्ल्ड कप में विजयी अभियान रुक जाएगा। लेकिन टीम इंडिया की महिला गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड पर शुरुआत से ही दबाव बनाया और नियमित अंतराल पर विकेट आउट किए। कीवी टीम का पहला विकेट 13 रनों पर गिरा। ओपनर बल्लेबाज रचेल प्रीस्ट 12 रन बनाकर आउट हुईं। उसके बाद कप्तान सोफी डिवाइन भी बहुत देर तक क्रीज पर नहीं टिक पाईं और वह 14 रन बनाकर पवेलियन चलती बनीं।

तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने उतरी खतरनाक खिलाड़ी **सूजी बेट्स** को दीप्ति शर्मा ने सिर्फ 6 रनों पर पवेलियन की राह दिखाई। टीम इंडिया के लिए खतरा दिख रहीं मैडी ग्रीन को राजेश्नवरी गायकवाड़ ने आउट कर भारत की तरफ मैच का रुख मोड़ दिया। इसके बाद निचले क्रम में एमिलिया केर ने कीवी टीम को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी लेकिन कामयाब नहीं हुईं। उन्होंनें 34 रनों की नाबाद पारी खेली। इस मैच में भारत की तरफ से सभी महिला गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी की। यही कारण रहा कि कीवी टीम की कोई भी खिलाड़ी टिक नहीं पाई। टीम इंडिया की तरफ से दीप्ति शर्मा, शिखा पांडेय, राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम यादव और राधा यादव ने 1-1 विकेट लिया। मैच में 46 रनों की पारी खेलने वाली शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया।

● **आशीष नेमा**

शेफाली के आगे सब पस्त

महिला वर्ल्डकप में सचिन तेंदुलकर के नाम से ख्यात शेफाली वर्मा सब पर भारी पड़ रही हैं। शेफाली के प्रदर्शन से भारतीय महिला क्रिकेट टीम वर्ल्डकप के सेमीफाइनल में पहुंच गई है। देशवासियों को उम्मीद है कि इस बार भारतीय महिला क्रिकेट टीम टी-20 वर्ल्डकप का खिताब जरूर जीतेगी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम में शीर्ष क्रम में अहम भूमिका निभाने वाली सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को खुशी है कि युवा शेफाली वर्मा महिला टी-20 वर्ल्डकप में अपने प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींच रही हैं। उनका मानना है कि इससे टीम संतुलित बन गई है। पिछले दो-तीन वर्षों में भारतीय टीम का अहम अंग रही 23 वर्षीय मंधाना ने कहा कि शेफाली ने दिखा दिया कि वह उनकी तरह खेलने में सक्षम हैं।

स्मृति मंधाना ने कहा, 'पिछले दो-तीन वर्षों में मैंने ढेर सारे रन बनाए विशेषकर पावरप्ले में लेकिन अब शेफाली भी उसी तरह से रन बना रही है जैसे मैं बनाती थी। इससे टीम अधिक संतुलित बन गई है। वह जिस तरह से बल्लेबाजी करती है वैसे में उसके साथ बल्लेबाजी करना आसान है।' 16 साल की शेफाली ने वर्ल्डकप में अब तक तीन मैचों में 114 रन बनाए हैं, जिसमें 8 छक्के और 11 चौके शामिल है। उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया, इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ मैच में 39 रन बनाने के लिए मैच की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया था। मंधाना ने कहा, 'मैं पावरप्ले में अहम भूमिका निभाती रही हूं, लेकिन अब शेफाली भी इन ओवरों में तेजी से रन बना रही है। उसने बड़ा प्रभाव छोड़ा है और टीम अधिक संतुलित बन गई है।'

पाक्षिक पत्रिका अक्स के स्वामित्व एवं अन्य विषयों संबंधित विवरण

घोषणा

फार्म 4 (नियम 8 देखिए)

प्रकाशन	: भोपाल
प्रकाशन अवधि	: पाक्षिक
मुद्रक का नाम	: राजेन्द्र आगाल
नागरिकता	: भारतीय
पता	: 150 जोन-1 प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल
प्रकाशक का नाम	: राजेन्द्र आगाल
नागरिकता	: भारतीय
पता	: 150 जोन-1 प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल
संपादक का नाम	: राजेन्द्र आगाल
नागरिकता	: भारतीय
पता	: 150 जोन-1 प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल
उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हों तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	: राजेन्द्र आगाल 150 जोन-1 प्रथम तल मनोरमा काम्पलेक्स महाराणा प्रताप नगर भोपाल

मैं राजेन्द्र आगाल एतद् द्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकृत जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिए गए विवरण सत्य हैं।

दिनांक : 01.03.2020

राजेन्द्र आगाल
हस्ताक्षर

एक्टर नहीं जर्नलिस्ट बनना चाहती थीं

हिना खान

टेलीविजन में अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीतने के बाद एक्ट्रेस हिना खान ने बिग बॉस और खतरों के खिलाड़ी जैसे रिऐलिटी शो में प्रतियोगियों को दमदार टक्कर दी थी।

हिना विक्रम भट्ट द्वारा निर्देशित फिल्म हैक्ड से अपना बॉलीवुड डेब्यू कर चुकी हैं। हालिया एक इंटरव्यू में एक्टर बनने के सवाल पर हिना बताती हैं कि सच कहूं, तो मैंने कभी एक्टर बनने का नहीं सोचा था बल्कि मैं तो जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। मैं अपने कॉलेज के सेकंड इयर में थी और ये रिश्ता क्या कहलाता है के लिए यूं ही ऑडिशन दे दिया था। संयोगवश चुन ली गई। ऐक्टिंग तो बस हो गई, शायद यह सब किस्मत की बात है।

रहमान बोले - मैंने डायरेक्टर को पाकिस्तानी एक्टर्स कास्ट करने से मना किया था

ग्रैमी और ऑस्कर अवॉर्ड विजेता म्यूजिक कंपोजर एआर रहमान की फिल्म 99 सॉन्ग्स का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। इस मौके पर रहमान ने फिल्म से जुड़ी जानकारी साझा की।

रहमान बताते हैं, मैंने निर्देशक विश्वेश कृष्णमूर्ति से पूछा कि वह हमारी फिल्म के हीरो के लिए भारत से ही किसी कलाकार की तलाश क्यों नहीं करते, जो गाना गा सकें और पियानो बजा सके। निर्देशक ने कहा कि सर पाकिस्तानी कलाकार गाने के साथ-साथ म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स भी अच्छी तरह बजाना जानते हैं। मैंने निर्देशक से कहा कि अगर आपने पाकिस्तानी कलाकार को फिल्म में लिया तो हम उस समय क्या करेंगे, जब भारत-पाकिस्तान के बीच हंगामा होगा।

'कई हीरोइन्स ने रिजेक्ट किया, तब जाकर मुझे मिली हसीन दिलरुबा'

बॉलीवुड एक्ट्रेस तापसी पन्नू कहती हैं कि वह बहुत ही लालची लड़की हैं और इसी लालच की वजह से वह बॉक्स आफिस और फिल्म इंडस्ट्री में चल रही हैं। लोग उन्हें पसंद भी कर रहे हैं और कई लोग किरकिरी भी कर रहे हैं।

मैं बड़ी लालची हूं इसलिए चल रही हूं

फिल्म हसीन दिलरुबा पर तापसी बताती हैं, जब यह कहानी लोगों को अप्रोच की जा रही थी, तब इस बीच मेरी बात निर्देशक से हुई थी और मैंने उनसे पूछा भी था कि अरे उस कहानी का क्या हुआ, तब उनका जवाब था कि माफ कीजिए, उस कहानी को किसी और के साथ कर रहे हैं। इस बीच निर्देशक और उस हिरोइन की बात नहीं बनी और वह फिल्म मुझे मिल गई। उस फिल्म को लेकर मुझे ऐसा लग रहा था कि वह किरदार मुझे ही निभाना चाहिए, वह मेरी किस्मत में थी, तभी तो दुनिया-जहान में हां-न करते हुए मेरे पास आ गई।

नीना गुप्ता बोलीं...

मैंने प्यार में टॉर्चर, हिंसा सब सहा है

तीन साल पहले सोशल मीडिया के जरिए काम की तलाश करने वाली एक्ट्रेस नीना गुप्ता इन दिनों सुपर बिजी हैं। हाल ही उनकी फिल्म पंगा आई है, तो अगली फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान भी रिलीज हो चुकी है। इधर, उनके स्टाइलिश लुक की भी खूब चर्चा है। हाल ही में एक इंटरव्यू में फेमिनिजम के सवाल पर नीना ने कहा... क्या है फेमिनिजम? मुझे नहीं पता। औरत की कोई इज्जत तो करता नहीं है, फेमिनिजम बोलते रहते हैं। जो बोलते हैं, वे घर में औरत की कितनी इज्जत करते हैं, मैं जानना चाहती हूं। फेमिनिजम कुछ नहीं है, बकवास है सब। मैं स्ट्रॉन्ग हूं, ये आप कैसे कह सकती हैं, आपको पता ही नहीं है कि मैंने क्या सहा है? आप तो सिर्फ मेरी मीडिया इमेज के हिसाब से मुझे जानते हैं, लेकिन असल में मुझे कौन जानता है? वह तो मैं अपनी जिंदगी पर किताब लिखूंगी, तभी कोई जान पाएगा, उसमें भी मैं कुछ चीजें नहीं बताऊंगी। इसलिए, कौन जानता है कि किसी ने मेरे साथ क्या धोखा किया? मेरे बॉयफ्रेंड ने कैसे टॉर्चर किया, कोई जानता है? मुझ पर डोमेस्टिक वॉयलेंस हुई, कोई जानता है?

कस्बे के रसीले कवि

मेरे कस्बे में जितने कवि हैं, उससे चौगुने पत्रकार हैं। यहां कवि होने के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। कस्बे में हॉकर भी पत्रकार बनने की सोचता है। पत्रकारिता की बात ही कुछ और होती है। पत्रकार की कलम से सभी खौफ खाते हैं। वो रुतबा कविताई में कहां? यह तो घर-फूंक तमाशा है। इसके बावजूद कस्बे में ज्ञात-अज्ञात दर्जन भर कवि तो होंगे ही। इनमें लगभग सभी मंच-प्रेमी हैं। गणेशोत्सव, नवदुर्गा उत्सव, होली जैसे अवसरों पर ये कविगण पुरजोर कोशिश कर दो-चार कवि सम्मेलन जुटा ही लेते हैं। इनकी उत्कट अभिलाषा रहती है कि इन्हें कविता-पाठ के लिए 501 मिले। हालांकि बाद में ये 51 रुपए का लिफाफा लेकर भी संतोष कर लेते हैं। वैसे भी संतोष रूपी धन के आगे सभी धन धूल के समान है।

मेरे कस्बे के कुछ दिग्गज कवियों ने किसी न किसी रस पर अपना अधिकार जमा रखा है। एक कवि तो बहुत निराले हैं। वे सभी रसों का उद्धार करने पर आमादा हैं। ये श्रोताओं के मूड के अनुसार रस परिवर्तन करते रहते हैं। मैंने उन्हें सलाह दी है कि वे अपना उपनाम सबरस रख लें। वे मेरी राय पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं।

वैसे तो रस नौ प्रकार के होते हैं, पर इन कवियों के लिए श्रृंगार, हास्य और वीर रस ही काम के हैं। इनकी नजरों में शेष सारे रस निरर्थक हैं। ये बिना रस के कोई कविता नहीं लिखते। इनका मानना है कि यदि कविता में रस नहीं होगा तो रसिक श्रोता उसमें रस कैसे ले पाएंगे। नीरस कविता को कौन सुनेगा? इसलिए यह ठीक ही है कि कविताएं रसदार रहें। नई कविता के कवि ये नोट करें कि मेरे कस्बे के कवियों ने मुक्तिबोध, केदारनाथ अग्रवाल, धूमिल, रघुवीर सहाय आदि कवियों का नाम तक नहीं सुना है। ऐसे कवियों की कविताएं इनके सर के ऊपर से हवाई जहाज के समान निकल जाती है, इनकी पहुंच और पकड़ से परे।

अपना परिचय हास्य कवि के रूप में देने वाले हास्य कवि सम्राट से मैं काफी भयभीत रहता हूं। ये कवि महोदय एक होटल के मालिक भी हैं। मैं इनकी होटल के सामने से नजर बचाकर निकलने की कोशिश करता हूं। लेकिन कविवर की पैनी दृष्टि से बच नहीं पाता हूं। वे मुझे दबोच ही लेते हैं। दबोचने के पश्चात वे कम से कम पांच कविताओं का रसपान जरूर कराते हैं। इनकी कविताओं में कुत्ते, गधे, पुलिस, डंडे आदि शब्द बरसते ही रहते हैं। जब वे अपनी हास्य कविता सुनाना शुरू करते हैं तो मैं सीरियस होने लगता हूं। पहली कविता सुनकर जब मैं नहीं हंसता हूं तो वे तुरंत दूसरी कविता शुरू कर देते हैं। अंत में मैं एक नकली हंसी हंसता हूं जिसे वे असली समझते हैं। किसी जरूरी काम का बहाना बनाता हूं। तब कहीं जाकर मेरी मुक्ति संभव होती है।

कस्बे में वीर रस के एक धुरंधर कवि मौजूद हैं। ये एकदम कृशकाय हैं। पूरे शरीर पर नीलवर्णी नसें उभरी हुई हैं। मुझे घोर आश्चर्य है कि ऐसा सींकिया शख्स वीर रस की कविता कैसे उत्पादित कर लेता है। इनकी कविता का प्रस्तुतीकरण भी देखने योग्य होता है। इनकी कविताओं में कश्मीर, दुश्मन, वतन, बम आदि शब्दों की झड़ी लगी रहती है।

जब कविवर अपना सुप्रसिद्ध गीत सुनाने लगते हैं तो उनका चेहरा महाविकृत हो जाता है। लगता है कवि मंच पर नहीं सीधे रणभूमि पर खड़े हैं। टेंटुआ गले से बगावत करता सा प्रतीत होता है। गले में उभरी एक खास मोटी नली अपनी क्षमता से अधिक फूल जाती है। मुझे हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं अधिक दबाव के कारण नली फूट न जाए, अन्यथा काव्य-प्रेमी श्रोतागण कविवर की ओजस्वी वाणी से सदा के लिए वंचित हो जाएंगे। सौभाग्य से आज तक ऐसी दुर्घटना नहीं घटी। आज भी कविवर उस गीत को उसी जोश के साथ सुनाते हैं।

कवि-मंडली में श्रृंगार रस के एक अन्य कवि पतझड़जी भी मौजूद हैं। इन्होंने श्रृंगार रस की वियोग शाखा पर अधिकार जमा रखा है। इन्होंने ढाक के तीन पात की तरह अभी तक मात्र तीन गीत लिखे हैं। यही इनकी कुल पूंजी है, जिसे वे पिछले तीस बरसों से खर्च कर रहे हैं। किंतु आज तक यह पूंजी समाप्त नहीं हुई है। भगवान ऐसी बरकत किसे देता है।

कविवर की दुर्बल देह पतझड़ का प्रतीक लगती है। पर्णहीन टहनियों से हाथ-पांव। कोटरों में धंसी वीरान आंखें, निचुड़ा हुआ चेहरा, जिस पर झाड़ीनुमा दाड़ी। सुना है कि इनकी जिंदगी में एक बार बसंत आया था। एक दिन बेवफा बसंत कवि को धोखा देकर अन्यत्र चला गया। फिर पतझड़ स्थायी होकर रह गया। बेवफा बसंत फिर लौटकर नहीं आया। यही कारण है कि वियोगी कवि ने अपना नाम ही पतझड़ रख लिया। इनके तीनों गीतों में एक टूटे हृदय की पीड़ा कूट-कूट कर भरी है।

कवि-मंडली का हर कवि अपने पास 8-10 चुटकुलों का भंडार रखता ही है। हर रस का कवि अवसर आने पर इनका इस्तेमाल करने से नहीं चूकता। जब कविता नहीं जम पाती तो चुटकुलों से काम चलाया जाता है। कई बार कविता से अधिक चुटकुले कारगर साबित होते हैं। अंधे को क्या चाहिए दो आंखें। कवियों को वाहवाही और तालियों से मतलब। कविता से मिले या चुटकुलों से क्या फर्क पड़ता है।

ऊपर उल्लेखित सभी कवियों का मानना है कि इन्हें यदि अवसर मिलता तो ये आज देश की अग्रपंक्ति के कवियों में गिने जाते। अज्ञात कारणों से इन्हें अवसर नहीं मिला। खैर! वैसे भी सब मनचाहा कब पूरा होता है, शायर ने सच ही कहा है-

कभी किसी को मुकम्मल जहान नहीं मिलता,
कहीं जमीं तो कहीं आसमान नहीं मिलता।

● **गोविन्द सेन**

विश्वसनीय खबरों के लिए पढ़ते रहिए

In Pursuit of Truth

पाक्षिक अक्स

www.akshnews.com

लॉगऑन करें

www.akshnews.com

वार्षिक सदस्यता के लिए संपर्क करें, 150, जोन-1, एम.पी.नगर भोपाल
फोन:0755-4017788,2575777

D-17008

2015-2020... इंदौर का कायापलट

स्वच्छता सर्वेक्षण – 2019 में हैट्रिक

स्वच्छता सर्वेक्षण – 2017 में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर

स्वच्छता सर्वेक्षण – 2018 में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर

धन्यवाद इंदौर...

हृदय से धन्यवाद इंदौर की जनता को... जिन्होंने हमारी परिषद के सभी अभियानों को व्यापक समर्थन व सहयोग दिया। आपके साथ के बिना किसी भी उपलब्धि तक पहुँचना मुश्किल ही नहीं बल्कि असंभव था। आपने अपनी हर जिम्मेदारी निभाई और आपकी सहभागिता से ही शहर का चौतरफा विकास संभव हो पाया।

श्रीमती मालिनी लक्ष्मणसिंह गौड़
महापौर एवं विधायक क्षेत्र क्र. 04

अजयसिंह नरूका
सभापति

श्रीमती फौजिया शेख अलीम
नेता प्रतिपक्ष

आशीष सिंह (आई.ए.एस.)
आयुक्त

निगम परिषद पदेन सदस्य – सांसद – श्री शंकर लालवानी एवं
विधायकगण – संजय शुक्ला, रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, महेन्द्र हार्डिया, जीतू पटवारी, तुलसीराम सिलावट, विशाल पटेल
महापौर परिषद सदस्यगण –
शंकर यादव, राजेन्द्र राठौर, चंदुराव शिंदे, दिलीप शर्मा, बलराम वर्मा, सुधीर देड़गे, संतोषसिंह गौर, सूरज कैरो, अश्विनी शुक्ल, श्रीमती शोभा रामदास गर्ग